



४/१२/८८
१३/१२/८८

भारत का राजापत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर, 15 1986/कार्तिक 24, 1908

No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 15, 1986/KARTIKA 24, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

भाग II—संख्या 3—चर्चा-संख्या (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आवेदन और अधिसूचनाएँ
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than
the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 1986

मूलना

का. आ. 3825:—नोटरीज नियम, 1956
के नियम 6 के अनुसरण में सक्तम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री जग मोहन लाल शर्मा, प्रृष्ठोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे निम का थाना (गजस्थान) व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्त पर किसी भी प्रकार का शास्त्रेष इस सूचना के प्रकाशन के चौंदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[म. 5 (61)/86-याय]

MINISTRY OF LAW & JUSTICE
(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 30th October, 1986

NOTICE

S.O. 3825.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Jag Mohan Lal Sharma Advocate, for appointment as a Notary to practice in Nim Ka thana (Rajasthan).

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(61)/86-Jud]

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1986

मूलना

का. आ. 3826:—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्तम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री प्रीम प्रकाश गुप्ता, प्रृष्ठोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे

मासी (यू. पी.) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्त पर किसी भी प्रकार प्राप्ति इस सूचना के प्रकाशन के बाद दिन के भीतर लिखित रूप में भर पास भेजा जाए।

[सं. 5 (72) /86-एव्या]

आर. एन. पोद्दार, संघम प्राधिकारी

New Delhi, the 4th November, 1986

NOTICE

S.O. 3826.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri O. P. Gupta Advocate, for appointment as a Notary to practise in Jhansi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(72)86-Judl.]

R. N. PODDAR, Competent Authority

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1986

आदेश

का० आ० 3827—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक सरकार की सहमति से, आयुद्ध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) को धारा 25 और धारा 30 के अधीन दण्डनीय अपराधों और भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 के अधीन दण्डनीय अपराधों और उन्हीं अपराधों और उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वसे ही संव्यवहार के अनन्त्रम में किए गए किसी अन्य अपराध के संबंध में या उनसे संबंधित प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षड्यंत्रों के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य पर करती है।

[संख्या 228/16/86-ए० श्री० डी० (II)]

जी० सीतारामन, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. & PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 4th November, 1986

ORDER

S.O. 3827.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the

Central Govt. with the consent of the Government of Karnataka, hereby extends the power and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Karnataka for the investigation of offences punishable under sections 25 and 30 of the Arms Act, 1959 (Act 54 of 1959) and offences punishable under section 5 of the Indian Explosives Act 1884 (Act 4 of 1884) and attempts, abettments and conspiracies in relation to, or in connection with the said offences and any other offences committed in the course of the same transaction arising out of the same facts.

[F. No. 228/16/86-AVD-II]

G. SITARAMAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रस्तुत कर बोर्ड

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1986

(प्रायर)

का० आ० 3828.—ग्रामक अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269धध के परत्तुक के खण्ड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, हाउर्सिंग डिवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन लि० बम्बई को इसकी गृह बधत योजना स्कीम और अरुण से सम्बद्ध जमा स्कीम को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है। दिनांक 18-7-1986 की पूर्ण अधिसूचना को इस सीमा तक संशोधित किया गया है।

[फा सं० 414/104/84-आ०क०(जां०)]

एस. राजगुरु, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 28th October, 1986.

(INCOME TAX)

S.O. 3828.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of proviso to section 269SS of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies, Housing Development Finance Corporation Limited, Bombay in respect of its Home Savings Plan Scheme, Loan Linked Deposit Scheme and Certificate of Deposit Scheme, including cumulative Interest Scheme for the purpose of the said section. The earlier notification dated 18-7-1986 is to this extent modified.

[F. No. 414/104/84-IT(INV)]

S. RAJGURU, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1986

का० आ० 3829.—आषकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 193 के परत्तुक के खण्ड

(ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ हाउसिंग इवेल-पैट फार्मास कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित ऋण पद्धों को विनिर्दिष्ट करती है :—

- (1) एच० डी० एफ० सी० 12.5 प्रतिशत ऋणपत्र (1992-1996)
- (2) एच० डी० एफ० सी० — 12.5 प्रतिशत ऋण (1995)
- (3) एच० डी० एफ० सी० — 12.5 प्रतिशत ऋण पत्र (1996)

[सं 6981—फा. स. 27552/86-आ.क. (ब)]

New Delhi, the 29th October, 1986
INCOME TAX

S.O. 3829.—In exercise of the power conferred by clause (ii) of the proviso to section 193 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the following bonds issued by the Housing Development Finance Corporation Limited, New Delhi, for the purposes of the said clause, namely :—

- (1) HDFC—12.5% Bonds (1992-1996).
- (2) HDFC—12.5% Bonds (1995).
- (3) HDFC—12.5% Bonds (1996).

[No. 6981—F. No. 27552/86-IT(B)]

का० आ० 3830.—प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 193 के परन्तुक के खण्ड (ii-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए नैशनल हाईड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए “7 वर्षीय 14% आरक्षित विमोच्य असंपरिवर्तनीय बंधपत्र (“क” श्रंखला)” को विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 6982 फा. सं. 275/81/86 आ. क. (ब)]

S.O. 3830.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to section 193 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the “7-Year 14% Secured Redeemable Non-convertible Bond—(A. series)” issued by the National Hydroelectric Power Corporation Limited, New Delhi, for the purposes of the said clause.

[No. 6982 F. No. 275/81/86-IT(B)]

का० आ० 3831.—प्रायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 193 के परन्तुक के खण्ड (ii ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ इन्डियन पैटे-केमिकल्स द्वारा जारी किए गए “1986 आई. पी. सी. एस. -14% प्रतिशत आरक्षित मोचनीय असंपरिवर्तनीय ऋण पद्धों को विनिर्दिष्ट” करती है।

[सं. 6983—फा. सं. 275/109/86-आ. क. (ब)]

वा. नागराजन, निदेशक

S.O. 3831.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to section 193 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the “1986—IPCL—14% Secured Redeemable non-convertible Bonds” issued by the Indian Petrochemicals Corporation Limited, Baroda, for the purposes of the said clause.

[No. 6983 F. No. 275/109/86-IT(B)]

B. NAGARAJAN, Director.

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1986

आदेश

स्टाम्प

का० आ० 3832.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899

(1899 का 21) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उस शल्क को माफ करती है जो नेशनल स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा जारी किये जाने वाले केवल दस करोड़ रुपये के मूल्य के प्रामिसरी नोटों “आई.डी.ओ.आई.डी.ओ.” ऋण 10 करोड़ हॉ (1986)—प्रथम सृष्टिकला के स्वरूप के बंध-वर्त्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है।

[सं. 40/86-स्टाम्प—फा. सं. 33/46/86-बि. कर]

बी० आर० मेहमी, अवर सचिव

New Delhi, the 4th November, 1986

ORDER

STAMPS

S.O. 3832.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of promissory Notes “IDBI” loan Rs. 10 crores (1986)—1st Series of the value of ten crores of rupees only to be issued by the National Small Industries Corporation, Limited, New Delhi, are chargeable under the said Act.

[No. 40/86-Stamp. F. No. 33/46/86-ST]

B. R. MEHMI, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1986

का० आ० 3833.—प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बोर्ड की अधिकृतना सं. 4306 (फा. सं. 261/13/81 आ० का. न्याय, दिनांक 13-11-81) सं. 4448 (फा. सं. 261/6/82 आ० का. न्याय, दिनांक 1-2-82), सं. 4041 (दिनांक 7-10-82 सं. 4962 (फा. सं. 261/6/82 आ० का. न्याय, दिनांक 10-11-82 और सं. 6518 (फा. सं. 279/143/84-आ० का. न्याय, दिनांक 29-11-85 (में आंशिक संशोधन करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निर्देश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेजों के अपीलीय सहायक प्रायकर आद्यक्ष के लिए विधीरित उन मध्य शक्तियों और आय को छोड़कर जिनपर को आविष्कार आयहर मादृत

(प्राप्तील) में निहित है, अनुसूची के स्तरम् (3) को तत्त्वानुच्छी प्रविष्टि में विनिर्विष्ट आयकर परिमण्डलों, बाड़ी, और जिलों में आयकर में निर्धारित सभी व्यक्तियों और आय के सम्बन्ध में प्रभावे कार्य करेंगे:—

अनुसूची

क्र. सं. रेंज	आयकर परिमण्डल / बोर्ड / जिला	
1	2	3
1. अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त इन्हीर रेंज, इन्हीर	1. इन्हीर के सभी आयकर अधिकारी 2. सहायक आयुक्त संचाल एलक, इन्हीर 3. आयकर प्रधिकारी, धार 4. आयकर परिमण्डल, खण्डवा 5. आयकर प्रधिकारी, खण्डवा	
2. अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, उज्जीन रेंज उज्जीन,	1. आयकर परिमण्डल, उज्जीन 2. आयकर परिमण्डल, रत्नाम 3. आयकर परिमण्डल, मन्दसौर 4. आयकर परिमण्डल, नीमच 5. आयकर परिमण्डल, देवास	
3. अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, भोपाल रेंज, भोपाल।	1. भोपाल के सभी आयकर अधिकारी 2. भोपाल में मुख्यालय के साथ आयकर अधिकारी सेहोर 3. आयकर परिमण्डल इटारसी 4. आयकर परिमण्डल बेतल 5. आयकर परिमण्डल, विदिशा	
4. अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त खालियर रेंज, खालियर,	1. खालियर के सभी आयकर अधिकारी 2. आयकर परिमण्डल, गुरा 3. आयकर परिमण्डल, गिरपुरी 4. आयकर परिमण्डल, मुरेना	

2. जहाँ कहीं कोई आयकर परिमण्डल आई जिला अधिकारी उसका कोई आय इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज में अन्तरित कर दिया गया हो, वहाँ उस आयकर परिमण्डल, बाईं या जिला अधिकारी उसके किसी भाग में किए गए कर निवारियों से उत्पन्न होने वाली प्रतीक्षा इस अधिसूचना की तारीख से तकालपूर्व रेंज के उस अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष विचाराधीन पड़ी अपेक्षा जिसके प्रधिकारी क्षेत्र से उक्त आयकर परिमण्डल, बाईं या जिला अधिकारी उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो, इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से रेंज के उस अपीलीय सहायक आयुक्त को अन्तरित की जाएंगी और उसके द्वारा निपटाई जाएगी, जिसके अधिकारी क्षेत्र में उक्त परिमण्डल, बोर्ड और जिला अधिकारी उसका कोई भाग अन्तरित किया गया है।

यह घावेश दिनांक 1-10-1986 से लागू होगा।

[सं. 6942/86 (फा. सं. 261/27/86 फा. का. न्या. 7)]

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 30th September, 1986

S.O. 3833.—In exercise of the power conferred by Sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of

1961) and in partial modification of Board's notification No. 4306 (F.No.261/13/81-ITJ dated 13-11-81), No. 4448 (F.No. 261/6 /82-ITJ dated 1-2-82), No.4041 (dt.7-10-82) and 4962 (F.No. 261/6/82-ITJ dt.10-11-82) and No. 6518 dt. 29-11-85 (F.No.279/143/84-ITJ), the Central Board of Direct Taxes hereby directs that Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in column (1) of Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax in the Income-tax circles, wards and districts specified in the corresponding entry in column No. 2 thereof excluding all persons and income assessed to Income-tax over which the jurisdiction vests in Commissioners of Income-Tax (Appeals):

SCHEDULE

S.No.	Range	Income-tax Circle, Wards and Districts
1	2	3
1.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Indore Range, Indore.	1. All ITOs at Indore 2. A.C.E.D. Indore. 3. I.T.O. Dhar. 4. I.T. Circle, Khandwa. 5. I.T.O. Khargone,
2.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Ujjain Range, Ujjain.	1. I.T.Circle, Ujjain. 2. I.T.Circle, Ratlam. 3. I.T.Circle, Mandsaur. 4. I.T.Circle, Neemuch. 5. I.T.Circle, Dewas.
3.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Bhopal Range, Bhopal	1. All I.T.Os at Bhopal 2. I.T.O. Sehore with Hqrs. at Bhopal. 3. I.T.Circle, Itarsi. 4. I.T.Circle, Betul. 5. I.T.Circle, Vidisha.
4.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax Gwalior Range, Gwalior.	1. All I.T.Os at Gwalior. 2. I.T.Circle, Guna. 3. I.T.Circle, Shivpuri. 4. I.T.Circle, Morena.

2. Wherever on Income-tax circle, wards, district or part thereof stands transferred by this notification from one Range to another Range, appeals arising out of the assessments made in that I. T. Circle, wards or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of the Range from whom that I. T. Circle, ward or district or part thereof is transferred shall from the date this notification takes effect be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said circle, ward or district or part thereof is transferred.

This order shall take effect from 1-10-1986.

[No. 6942/86 (F. No. 261/27/86-ITJ)]

का. फा. 3834.—आयकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 121क की उपघारा (1) के द्वारा प्रदत्त अक्षियों का प्रयोग करते हुए और बोर्ड की दिनांक 7-7-1978 की पूर्ववर्ती अधिसूचना सं. 2302 (फा. सं. 261/7/78-प्रा. क. (न्या.)), दिनांक 14-1-82 की अधिसूचना सं. 4413 (फा. सं. 261/27/81 प्रा. का. (न्या.)) और दिनांक 14/15-9-84 की अधिसूचना सं. 5988 (फा. सं. 261/17/84 प्रा. का. (न्या.)) में अधिकारी संरोक्षन रहते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा निवेश देना है कि नीचे पी गई अनुसूची

के सन्दर्भ (1) में विनिविष्ट प्रभारों के आयकर आयुक्त (प्रपील) सन्दर्भ (2) की तस्वीरीय प्रविष्टियों में विनिविष्ट आयकर बाईं, परिमंडल और जिलों में आयकर, अधिकार अधिकार व्याज कर के लिए निर्धारित ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में कार्य निर्वहण करेंगे औ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (ज), कम्पनी (अनुलाभ) अधिकार अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 11 की उपधारा (i) और अधिकार अधिनियम, 1974 (1974 का 45) की धारा 15 की उपधारा (i) में उल्लिखित किसी भी आदेश से व्यक्ति हुए हैं, और ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों की व्येषणों के सम्बन्ध में भी, जिनके लिए बोई ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उपधारा 2 के खण्ड (1) के उपवर्णों के अनुसार निवेश दिया है या भविष्य में निवेश है।

मनुसूची

मुख्यालयों सहित प्रभार	आयकर बाईं / परिमंडल	
1	2	3
1. आयकर आयुक्त (प्रपील) भोपाल	निम्नलिखित के अधिकार धोत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी बाईं/परिमंडल:—	
	(i) नि. स. आ., भोपाल रेंज, भोपाल।	
	(ii) नि. स. आ., ग्वालियर रेंज, ग्वालियर।	
	(iii) नि. स. आ., (कर-नि.) रेंज, ग्वालियर।	
	(iv) नि. स. आ., (कर-नि.) रेंज, भोपाल	
2. आयकर आयुक्त (प्रपील) इन्दौर	सम्पदा शुल्क परिमंडल, आयकर परिमंडल, धार और "न" बाईं, इन्दौर को छाँड़कर, निम्नलिखित के अधिकार धोत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी बाईं / परिमंडल:—	
	(i) नि. स. आ., रेंज-I, इन्दौर	
	(ii) नि. स. आ., (निर्वाचन) रेंज, इन्दौर	
3. आयकर आयुक्त (प्रपील) II इन्दौर	निम्नलिखित के अधिकार धोत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी बाईं/परिमंडल :—	
	(i) नि. स. आ., रेंज-II, इन्दौर	
	(ii) नि. स. आ., उज्जैन रेंज, उज्जैन।	
	(iii) नि. स. आ., रेंज-I इन्दौर के अधिकार धोत्र में आने वाले सम्पदा शुल्क परिमंडल, आयकर परिमंडल, धार और "न" बाईं, इन्दौर।	
4. आयकर आयुक्त (प्रपील), जबलपुर	आयकर आयुक्त, जबलपुर के अधिकार धोत्र में आने वाले सभी बाईं / परिमंडल, सम्पदा शुल्क परिमंडलों सहित।	

जहाँ बोई आयकर परिमंडल, बाईं प्रधान जिला अधिकार रेंज अधिकार उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक अधिकार धोत्र में अन्तरित कर दिया गया हो, वहाँ उस आयकर परिमंडल, बाईं प्रधान जिला प्रधान रेंज अधिकार उनके किसी भाग में किए गए निर्धारणों में उल्लंघन होने वाली और इस सारी धोत्र में तत्काल पूर्ण, उस अधिकार धोत्र के आयकर आयुक्त (प्रपील) के गमन विवादीन अपीलें, जिनके अधिकार धोत्र में उक्त आयकर परिमंडल, बाईं, प्रधान जिला प्रधान रेंज अधिकार उपकार कोई भाग अन्तरित किया गया हो, इस अधिसूचना के लागू होने की तरीख से उस अधिकार धोत्र के आयकर आयुक्त (प्रपील) को अन्तरित की जाएगी और उसके द्वारा निपटाई जाएगी, जिसके अधिकार धोत्र में उक्त परिमंडल, बाईं या जिला या रेंज या उसका कोई भाग अन्तरित किया गया है।

यह अधिसूचना 1-10-1986 से लागू होगी।

[सं. 6941/86 (फा. स. 261/26/86-आ. क. (स्पा))]

मुरोद्व पाल, अधर सचिव
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोई

S.O. 3834—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in partial modification of Boards earlier notification No. 2302 dt. 7-7-1978 (F.No.261/7/78-ITJ) No. 4413 (F. No. 261/27/81-ITJ dt. 14/1/82), No. 5988 (F.No. 261/17/84-ITJ dt.14/15-9-84), the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Commissioners of Income-tax (Appeals) of the charges specified in column (1) of the Schedule below, shall perform their functions in respect of such persons assessed to Income-tax or Sur-tax or Interest Tax in the Income-tax Wards, Circles & Districts specified in the corresponding entries in the column No. (2) thereof as are aggrieved by any of the orders, mentioned in classes (a) to (h) of Sub-section (2) of section 246 of the Income-tax Act, 1961 in Sub-section (1) of Section 11 of the Companies (Profits) Sur-tax Act, 1964 (7 of 1964) and in Sub-section (1) of Section 15 of Interest Tax Act, 1974 (45 of 1974) and also in respect of such persons or classes of persons as the Board has directed or may direct in future in accordance with the provisions of clause (1) of Sub-section (2) of Section 246 of the Income-tax Act, 1961.

SCHEDULE

Charges with Head Quarter Income-tax Wards/Circles

	1	2
1. Commissioner of Income-tax (Appeals), Bhopal.	All wards/circles falling within the jurisdiction of :—	
	(1) IAC, Bhopal Range, Bhopal.	
	(2) IAC, Gwalior Range, Gwalior.	
	(3) IAC (Asstt.) Range, Gwalior	
	(4) IAC (Asstt.) Range, Bhopal.	
2. Commissioner of Income-tax (Appeals), Indore.	All ward/circles, excluding Estate Duty Circle, Income-tax Circle, Dhar AND 'C' Ward, Indore falling within the jurisdiction of :—	
	(1) IAC, Range-I, Indore.	
	(2) IAC (Asstt.), Range, Indor	

1	2
---	---

3. Commissioner of Income-tax (Appeals)-II, Indore

All wards/circles falling within the jurisdiction of:

- (1) IAC, Range-II Indore.
- (2) IAC, Ujjain Range, Ujjain.
- (3) Estate Duty Circle, Income-tax Circle, Dhar and 'C' Ward, Indore falling within the jurisdiction of IAC, Range-I, Indore.

4. Commissioner of Income-tax (Appeals), Jabalpur.

All wards/circles including E.D. Circles falling within the jurisdiction of C.I.T., Jabalpur.

Whereas the Income-tax Circle, Ward or district or Range or part thereof stands transferred by this Notification from one charge to another charge, appeals arising out of the assessments made in that Income-tax Circle, ward or district or Range or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Commissioner of Income-tax (Appeals) of the charge from whom that Income-tax circle, ward or district or Range or part thereof is transferred shall from the date of this Notification take effect, be transferred to and dealt with by the Commissioner of Income-tax (Appeals) of the charge to whom the said Circle, ward or district or Range or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 1-10-1986.

[No. 6941/86/F.No. 261/26/86 -IT(J)]
SURENDER PAUL, Under Secy.
Central Board of Direct Taxes

(आधिकार्य कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 1986

का. आ. 3835—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एवं द्वारा श्री आर. डी. देशपांडे को फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फतेहपुर का अध्यक्ष नियुक्त करती है, तथा 16-8-86 से प्रारम्भ होकर 31-8-89 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री आर. डी. देशपांडे अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[सं. एफ. 2-14/86-प्रार. आर. बी.]

(Dept. of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 23rd October, 1986

S.O. 3835.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri R. D. Deshpande as the Chairman of the Patchpur Kshetriya Gramin Bank, Patchpur and specifies the period commencing on the 16-8-86 and ending with the 31-8-89 as the period for which the said Shri R. D. Deshpande shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2-14/86-RRB]

का. आ. 3836—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एवं द्वारा श्री के. यू. याजिक को सुलतानपुर

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुलतानपुर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 10-8-86 से प्रारम्भ होकर 31-8-89 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री के. यू. याजिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[सं. एफ. 2/13/86-प्रार. आर. बी.]

S.O. 3836—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri K. U. Yagnik as the Chairman of the Sultanpur Kshetriya Gramin Bank, Sultanpur and specifies the period commencing on the 10-8-86 and ending with the 31-8-89 as the period for which the said Shri K. U. Yagnik shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2-13/86-RRB]

का. आ. 3837—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री ओ. पी. गर्ग को जिनकी धारा 11 की उपधारा (1) के तहत सुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुलतानपुर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की तीन वर्ष की पहली अवधि 30-9-85 को समाप्त हो गई है, 1-10-85 से प्रारम्भ होकर 9-8-86 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उक्त बैंक का पुनः अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[सं. एफ. 2/13/86-प्रार. आर. बी.]

S.O. 3837.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby reappoints Shri O. P. Garg whose earlier tenure of three years appointment under sub-section (1) of section 11 had expired on 30-9-85 as the Chairman of Sultanpur Kshetriya Gramin Bank, Sultanpur for a further period commencing from 1-10-85 and ending with 9-8-86.

[No. F. 2-13/86-RRB]

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 1986

का. आ. 3838—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री रामचरण पांडे को जिनकी धारा 11 की उपधारा (1) के तहत बर्धमान ग्रामीण बैंक, बुर्दावान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की तीन वर्ष की पहली अवधि 22-10-1985 को समाप्त हो गयी है, 23-10-1985 से प्रारम्भ होकर 18-7-1986 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये उक्त बैंक का पुनः अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[सं. एफ. 2-85/82-प्रार. आर. बी.]

New Delhi, the 27th October, 1986

S.O. 3838.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby reappoints Shri Ramcharan Pandey whose earlier tenure of three years appointment under sub-section (1) of section 11 had expired on 22-10-1985 as the Chairman of Bardhaman Gramin Bank, Burdwan for a further period commencing from 23-10-85 and ending with 18-7-1986.

[No. F. 2-85/82-RRB]

का. आ. 3839—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रबल्ल शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एन. एन. चक्रवर्ती को वर्धमान ग्रामीण बैंक, बर्दवान (प. बंगाल) का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 19-7-86 से प्रारम्भ होकर 31-7-89 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री एन. एन. चक्रवर्ती अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[सं. एफ. 2/85/82-प्रार. आर. बी.]

S.O. 3839.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Shri N. N. Chakravorty, Chairman, Bardhaman Gramin Bank, Burdwan (W.B.) and specifies the period commencing on the 19-7-86 and ending with the 31-7-89 as the period for which the said Shri N. N. Chakravorty shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2-85/82-RRB]

का. आ. 3840—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रबल्ल शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री जे.आर. नकदी को गोमती ग्रामीण बैंक, जैनपुर (उत्तर प्रदेश) का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 12-8-86 से प्रारम्भ होकर 31-8-89 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री जे.आर. नकदी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ 2-21/86-प्रार.आर. बी.]

च०वा० मीरचन्दनानी, निवेशक

S.O. 3840.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri J. R. Naqvi as the Chairman of Gomti Gramin Bank, Jaunpur (Uttar Pradesh) and specifies the period commencing on the 12-8-1986 and ending with the 31-8-1989 as the period for which the said Shri J. R. Naqvi shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2-21/86-RRB]

‘ C. W. MIRCHANDANI, Director.

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1986

का. आ. 3841—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकार्ण उपबंध) योजना, 1980 की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसार में केन्द्रीय सरकार श्री के. एक. भारत प्रधानमंत्री, रिजर्व बैंक, स्टाफ कालेज, मान्द्रास-600018 को श्री ओ. पी. सोहानी के स्थान पर, एतद्वारा अन्धा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या एफ. 9/2/86-श्री. ओ.-1]

एम. एस. सीतारामन, अवर सचिव

New Delhi, the 28th October, 1986

S.O. 3841.—In pursuance of sub-clause (g) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government hereby appoints Shri K. N. Bhargava, Principal, Reserve Bank Staff College, Madras as a Director of Andhra Bank vice Shri O. P. Sojhani.

[No. F. 9/2/86-B.O. I]

M. S. SEETHARAMAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1986

का० आ० 3842.—केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक वित्त नियम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 21 की उपधारा (2) के अनुसार में भारतीय औद्योगिक वित्त नियम के निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियम द्वारा 25 नवंबर, 1986 को जारी किए जाने वाले और 25 नवंबर, 2001 को परिपक्व होने वाले बांडों पर देय ब्याज की दर एतद्वारा 11 प्रतिशत (ग्यारह प्रतिशत) वार्षिक निर्धारित करती है।

[फा. सं. 6(10)/86-प्राई.एफ. 1]

New Delhi, the 29th October, 1986

S.O. 3842.—In pursuance of Sub-section 2 of section 21 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948), the Central Government, on the recommendation of the Board of Directors of the Industrial Finance Corporation of India, hereby fixes 11 percent (eleven percent) per annum as the rate of interest payable on the bonds to be issued by the said Corporation on 25th November, 1986 and maturing on 25th November, 2001.

[F. No. 6(10)/86-IF-I]

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1986

का० आ० 3843.—केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक वित्त नियम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 21 की उपधारा (2) के अनुसार में भारतीय औद्योगिक वित्त नियम के निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियम द्वारा 1 जनवरी, 1987 से 21 दिसंबर, 1987 की अवधि के लिए जारी किए जाने वाले बांडों पर देय ब्याज की दर एतद्वारा 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) वार्षिक निर्धारित करती है।

[फा. सं. 6(27)/86-प्राई.एफ. 1]

पी. के मल्होत्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 31st October, 1986

S.O. 3843.—In pursuance of sub-section (2) of Section 21 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948), the Central Government, on the recommendation of the Board of Directors of the Industrial Finance Corporation of India hereby, fixes 10 percent (Ten percent) per annum as the rate of interest payable on the bonds having currency during the period 1st January 1987 to 31st December, 1987, to be issued by the said Corporation.

[F. No. 6(27)/86-IF-I]

P. K. MALHOTRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1986

का०ग्रा० 3844:—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध एवं प्रकीर्ण उपक्रम) स्कीम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (ख) (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री गुडिपति गोपाल कृष्णमृति, विशेष सहायक, बैंक आफ इंडिया, हैदराबाद मुख्य शाखा को दिनांक 31 अक्टूबर, 1986 से 30 अक्टूबर, 1989 तक बैंक आफ इंडिया के निदेशक मंड़ल में निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं एफ० 15/5/82-भाई० आर०]

सतपाल भाटिया, अव० अधिकारी

New Delhi, the 31st October, 1986

S.O. 3844.—In pursuance of sub-clause (b)(i) of clause 3, read with sub-clause (2) of clause 9, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri Gudipaty Gopala Krishna Murthy, Special Assistant, Bank of India, Hyderabad Main Branch, as a Director on the Board of Directors of the Bank of India with effect from 31st October, 1986 to 30th October, 1989.

[No. F. 15/5/82-IR]

S. P. BHATIA, Under Secy.

कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मध्य प्रदेश

इंदौर, 27 अक्टूबर, 1986

अधिसूचना संख्या 12/86

का०ग्रा० 3845.—मध्यप्रदेश समाहर्तालय इंदौर के निम्नलिखित अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ममूह “ख” निवर्तन की आयु प्राप्त करने पर उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथियों को जासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

- श्री एम० एच० जोशी 30-9-86 (अपराह्न)
- श्री डी० पी० निवारी 30-9-86 (अपराह्न)

[फा० सं० II (3) 2-गोप/86]

एस. बी. रामाकृष्णन, समाहर्ता

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE
Indore, the 27th October, 1986

NOTIFICATION NO. 12/86

S.O. 3845.—The following Superintendent of Central Excise Gr. 'B' of Central Excise Collectorate, Indore having attained the age of Suporannuation retired from Govt. service on the dates as shown against each:—

S. Name of the Officer No.	Date
1. Shri M.H. Joshi	30-9-86 (AN)
2. Shri D.P. Tiwari	30-9-86 (AN)
[C. No. II (3)2-CON/86]	
S.V. RAMAKRISHNAN, Collector	

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 1986

का०ग्रा० 3846:—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के जासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 1043 G of II/86—2

के उपनियम (4) के अनुसरण में वाणिज्य व वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत भाने वाले निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके कर्मचारी इन्हीं ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:—

वाणिज्य मंत्रालय :

- सैन्यस्ल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०, जनपथ “ए” बैरेक्स, नई दिल्ली-110001.
- क्षेत्रीय कार्यालय, नियंत्रक, आयात-नियर्ति श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)

वस्त्र मंत्रालय :

- नेशनल टेक्स्टाइल कारपोरेशन लि० (गुजरात) अहमदाबाद।

[फाइल सं०ई-11011/22/86-हिन्दी]

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 16th July, 1986

S.O. 3846.—In pursuance of Sub-rule (4) of rule 10 of the Official Language (Use for Official purposes of the Union) Rule, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices under the Ministry of Commerce and Ministry of Textiles, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

Ministry of Commerce :

- Central Cottage Industries Corporation of India Ltd., Janpath 'A' Barracks, New Delhi-110001.
- Office of the Controller of Imports and Exports, Srinagar (Jammu & Kashmir)

Ministry of Textiles :

- National Textiles Corporation Ltd., (Gujarat), Ahmedabad.

[File No. E-11011/22/86-Hindi]
VED PRAKASH, Director

कार्यालय संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात

(केन्द्रीय लाइसेंस भेद)

[फा०मं०-एडीबी/आई/यूडीईए०/84/एएप०८५/ए.एलए०-१/सीए०१]

निरस्त आदेश

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1986

का० ग्रा० 3847:—मैसर्स अब्दुल शकूर एंड संस, 3/डी-II, कोहना मुगल, कुली बाजार का इमामबादा, मुरादाबाद को 41 662 एम टीक्स्टाइल्स स्ट्रेप का नाम करने के लिए अधिसंघ आयात लाइसेंस में योकि 3080729 फॉर्म ९-८-८४ रु 4,84,600/- प्रदात किया गया था:

फर्म ने उक्त लाइसेंस की एकत्रित नियंत्रण प्रयोजन कापी प्रस्तुत की है तथा कहा है कि अधिसंघ लाइसेंस की सीमागत प्रयोजन कापी कहीं अस्थानस्थ हो गई है। लाइसेंस 4,84,600 रु की थी जारी किया गया था।

आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 दिनांक 7-12-55 की धारा 9(डी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए में उक्त अधिकार साइरेंस को नियंत्रण करने के आदेश देता है।

[फाइल सं.-एडीओ/नाई/पूडी/ई-एम/84/एम. 85/ए-एल-एस-1]

सी एल. ए/ 812

डा. आर. के. धवन,

उप मुख्य नियंत्रक, आयात एवं नियंत्रण

कुते संयुक्त मु. नि.-आयात एवं

नियंत्रण

OFFICE OF THE JT. CHIEF CONTROLLER OF
IMPORTS & EXPORTS
(Central Licensing Area)

New Delhi, the 16th July, 1986

CANCELLATION ORDER

S.O. 3847.—M/s. Abdur Shakoor & Sons, 3/D. II Kohna Mughal Kuli Khan Ka Iman Bara, Moradabad were granted advance licence No. P/K/3080729 dt. 9-8-84 for Rs. 4,84,600 for import of 41.662 M. T. of Brass Scrap.

The firm have surrendered the Exchange Control Purpose copy of the said licence intimating that the Customs Purposes copy of the advance licence has been misplaced. The amount for which the licence was issued is Rs. 4,84,600.

In exercise of the powers conferred on me under Section 9(d) of Import (Control) order, 1955 dated 7-12-1955 as amended upto date, I hereby order cancellation of the said advance licence.

[F. No. Adv/Lic/UDES/84] AM. 85[ALS. I/CLA/812]
(DR.) R. K. DHAWAN, Dy. Chief Controller of I & E
for Jt. Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 1986

का. आ. 3848.—राजनयिक और कौमसुलीय ऑफिसर (शास्त्र और फीस) अधिनियम, 1948 (1948 का 41वा), की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा भारत का राजदूतावास, रियाद में सहायक श्री आर. के. कपूर को 12-9-86 से कौमसुली एजेंट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[टी. 4330/1/86]

के. नागराजन, अवर सचिव (कौमसुली)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 24th October, 1986

S.O. 3848.—In pursuance of the clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorise Shri R. K. Kapoor, Assistant in the Embassy of India, Riyadh to perform the duties of Consular Agent with effect from 12-9-86.

[टी. 4330/1/86]

K. NAGARAJAN, Under Secy. (Consular)

सद्योग मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1986

का. आ. 3849:—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक अवधारण अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एवं द्वारा इस अधिसूचना के अनुसारन में उल्लिखित उनकमों के पंजीकरण को, उक्त उनकमों के बहु उनकम हीने पर, जिन पर उन अधिनियम के भाग का अधिनाय-III के उपशब्द अवधारणा नहीं होते हैं, के नियंत्रण को प्रधिकृत करती है।

[सं. 16/12/86-एम. 3]

एल. सो. गोपल, अवर सचिव

अधिसूचना सं. 16/12/86 एम. III का अनुसारन

क्रम सं.	उनकमों के नाम	पंजीकृत पाता	पंजीकृत संक्षा
1. मै.	गोदावरी सुगर मिल, लि.,	फंडमेंट विल्डिंग, भद्रामा गांव, रोड, पी. व. नं. 122, "Q" लोट बम्बई-400023	1231/75
2. मै.	गोदावरी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.,	--वर्सोरिंग--	1232/75
3. मै.	केपन मैटल प्रोडक्शन प्रा. लि., (भूत पूर्व भारत कैमोफ्लू प्रा. लि.)	लभ्यो इमोरेंज विल्डिंग सर फिरोज़ भावू मेडिना रोड, बम्बई-1	540/70

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 29th October, 1986

S.O. 3849.—In pursuance of Sub-Section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of the undertakings mentioned in the Annexure to this notification, the said undertakings being undertakings to which the provisions of Part A Chapter III of the said Act no longer apply.

[No. 16/12/86-M. III]

L. C. GOYAL, Under Secy.

Annexure to the Notification No. 16/12/86. M-III

S. No.	Name of the Undertakings	Registered Address	Registration Number
1.	M/s. Godavari Sugar Mills Ltd.	Fanzabhoi Building, Mahatma Gandhi Road, P.B. No. 122- A, Fort Bombay-400 023.	1231/75
2.	M/s. Godavari Invest- ment & Finance Corpo- ration Ltd.	—do—	1232/75
3.	M/s. Kisan Metal Products Private Ltd. (Formerly Bhavana Chemicals Private Ltd.)	Laxmi Insurance Building, Sir Phirozshah Motha Road, Bombay-1	540/70

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर 1986

T'U-TU

का. आ. 3850 — भारत सरकार के राजसत्र भाग-II, खण्ड 3, उपर्युक्त (ii) दिनांक 6 अक्टूबर, 1984 पृष्ठ क्रमांक 2919 और 2020 का आ. संख्या क्रमांक 0-12016/133/83-प्रोड के अन्तर्गत भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय, (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना संख्या क्रमांक 3148 दिनांक 6 अक्टूबर 1984 के अन्तर्गत-पेट्रोलियम और खनिज पार्षद साईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 की धारा 6 उपधारा (i) के अधीन बणित गंव-च-होली तहसील-हवेली जिला-पुणे महाराष्ट्र के अन्तर्गत अधिसूचना में बणित भूमि में खसरा नम्बर, हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल कालम 1 के बदले अनुसूची में खसरा नम्बर, हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल कालम 2 में दो गई अनुमतियों को पढ़ें।

निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि में पाईप लाईन विछाने का प्रयोजन अलाईनमेट बदलने से अब न रहा है। अब अतः, निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि घारा 6 के उपघारा (i) के प्रधिसंचना को अनुसूची से कम कर द गई है।

अनसची

भाग—1

कालम II पढ़ें

फालम 1 के लिये

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
च-होली	134	1 + 4	00-32-40}	च-होली	134	का भाग	00-47-00
	134	4	00-36-54}			"	
	302	1	00-16-20		302	"	00-25-00
	303	1	00-43-06		303	"	00-20-00
	303	2	00-18-75				
	305	का भाग	00-27-00		305	"	00-19-00
	307	1	00-05-50		307	"	00-36-00
	309	1	00-14-58		309	"	00-47-00
	352	1	00-70-20		352	"	00-45-00
	352	2	00-05-40				
	406	3 + 4	00-32-40		406	"	00-47-00
	408	2	00-21-60		408	"	00-39-00
	409	का भाग	00-16-20		409	"	00-45-00
	410	"	00-39-60		410	"	00-36-00
	414	1	00-08-64		414	"	00-12-00
	428	1	00-06-66		428	"	00-22-00
	430	3	00-18-00				
	430	4	00-06-00		430	"	00-34-00
	430	5	00-14-40				
	432	1	00-07-00		432	"	00-18-00
	432	6	00-05-94				
	433	2	00-16-25		433	"	00-19-00
	433	3	00-10-08				
	435	1-अ	00-01-62		435	"	00-27-00
	435	1-ब	00-15-30				
	435	2	00-05-40				

भाग—I

कालम II पर्यंत

कालम 1 के लिये

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
च—होली	443	2-4	00-14-76	च—होली	443	का भाग	00-39-00
	444	का भाग	00-29-62		444	"	00-52-00
	445	"	00-25-92		445	"	00-34-00
	668	1+07	00-61-60		668	"	00-39-00
	669	का भाग	00-28-44		669	"	00-25-00
	670	"	00-39-60		670	"	00-41-00
	711	(1-03)	00-06-90		711	"	00-09-00
	712	का भाग	00-18-50		712	"	00-20-00
	713	"	00-21-60		713	"	00-23-00
	714	"	00-32-40		714	"	00-45-00
	736	3	00-14-94		736	"	00-22-00
	737	1	00-06-39		737	"	00-09-00
	737	2	00-04-50				
	738	2	00-05-00				
	738	3			738	"	00-09-00
	738	4	00-03-39				
	739	का भाग	00-34-40		739	"	00-68-00
	798	1	00-08-64				
	798	2	00-05-58		798	"	00-17-00
	798	3	00-21-60				
	799	1	00-14-76		799	"	00-13-00
	800	4	00-01-80		800	"	00-14-00
	803	का भाग	00-09-00		803	"	00-16-00
	804	2	00-32-40		804	"	00-38-00
	811	का भाग	00-63-36		811	"	00-32-00

भाग—II

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
च—होली	306	का भाग	00-02-00
	353	"	00-22-00
	407	"	00-01-00
	431	"	00-02-00
	718	"	00-13-00
	719	"	00-07-00

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS
CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th October, 1986

S.O. 3850.—In the Notification of Government of India, Ministry of Energy (Department of Petroleum) No. 0-2016/133/83-Prod date 6-10-84 published under S.O. No. 3148 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) at page 2919 & 2920 issued under Section 6 Sub-Section (i) of the Petroleum & Minerals Pipe Lines (Acquisition of

Right of User in Land) Act, 1962 in respect of villages Charholi for S. Nos. and areas shown in the Column No. 1 of the Schedule appended to this corrigendum read and S. Nos. and areas as shown in column No. 2 of the said schedule.

Lands mentioned in the Part II of the appended schedule, however do not come under the Pipe Line Project due to change in the alignment and therefore, they are deleted from the schedule appended to the Notification under section 6 Sub Section (i) referred to above.

Read (Col.—II).

For (Col.—I).

PART—I

Village	G. No.	H. No.	Area	Village	G. No.	H. No.	Area
1	2	3	4	5	6	7	8
Charoli	134	1+4	00-32-40	Charoli	134	(pt)	00-47-00
	134	4	00-36-54		302	(pt)	00-25-00
	302	1	00-16-10				
	303	1	00-43-06		303	(pt)	00-20-00
	303	2	00-18-75				
	305	(pt)	00-27-00		305	(pt)	00-19-00
	307	1	00-05-50		307	(pt)	00-36-00
	309	1	00-14-58		309	(pt)	00-47-00
	352	1	00-70-20		352	(pt)	00-45-00
	352	2	00-05-40				
	406	3+4	00-32-40		406	(pt)	00-47-00
	408	2	00-21-60		408	(pt)	00-39-00
	409	(pt)	00-16-20		409	(pt)	00-45-00
	410	(pt)	00-39-60		410	(pt)	00-36-00
	414	1	00-08-64		414	(pt)	00-12-00
	428	1	00-06-60		428	(pt)	00-22-00
	430	3	00-18-00				
	430	4	00-06-00		430	(pt)	00-34-00
	430	5	00-14-40				
	432	1	00-07-00				
	432	6	00-05-94,		432	(pt)	00-18-00
	433	2	00-16-25				
	433	3	00-10-08		433	(pt)	00-19-00
	435	1-A	00-01-62				
	435	1-B	00-15-30				
	435	2	00-05-40		435	(pt)	00-27-00
	443	2+4	00-14-76		443	(pt)	00-39-00
	444	(pt)	00-29-62		444	(pt)	00-52-00
	445	(pt)	00-25-92		445	(pt)	00-34-00
	668	1+7	00-61-60		668	(pt)	00-39-00
	669	(pt)	00-28-44		669	pt	00-25-00
	670	(pt)	00-39-60		670	(pt)	00-41-00
	711	1+03	00-06-90		711	(pt)	00-09-00
	712	(pt)	00-18-50		712	(pt)	00-20-00
	713	(pt)	00-21-60		713	(pt)	00-23-00
	714	(pt)	00-32-40		714	(pt)	00-45-00
	736	3	00-14-94		736	(pt)	00-22-00
	737	1	00-06-39				
	737	2	00-04-50		737	(pt)	00-09-00
	738	2					
	738	3	00-09-00		738	(pt)	00-09-00
	738	4	00-03-39				
	739	(pt)	00-34-40		739	(pt)	00-68-00
	798	1	00-08-64				
	798	2	00-05-58		798	(pt)	00-17-00
	798	3	00-21-60				

PART—I

Village	G.No.	H.No.	Area	Vijlge	G.No.	H.No.	Area
1	2	3	4	5	6	7	8
Charoli	799	1	00-14-76		799	(pt)	00-13-00
	800	4	00-01-80		800	(pt)	00-14-00
	803	2(pt)	00-09-00		803	(pt)	00-16-00
	804	2	00-32-40		804	(pt)	00-38-00
	811	(pt)	00-63-36		811	(pt)	00-32-00

PART—II

Village	G.No.	H.No.	Area
Charoli	306	(pt)	00-02-00
	353	(pt)	00-22-00
	407	(pt)	00-01-00
	431	(pt)	00-02-00
	718	(pt)	00-13-00
	719	(pt)	00-07-00

[No. O-12016/133/83-Prod-I]
P. K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1986

गुह्य पत्र

का. प्रा. 3851:— भारत सरकार के राजन्त्र भाग II खण्ड 3, उपकार्ड (ii) विनांक 10 दिसम्बर, 1983 पृष्ठ क्रमांक 4586 और 4587 का. प्रा. संख्या क्रमांक ओ-12016/133/83 प्रोड के अंतर्गत भारत सरकार, उजों मंत्रालय (विद्युतिकरण विभाग, को अधिकृतना संलग्न क्रमांक 4448 दिनांक 10 दिसम्बर, 1983 के अंतर्गत—विद्युतिकरण और खनिज पार्क लाई (पूर्व में उत्तों के विभाग ना अर्थात्) अधिकृत 1962 की भाग 3 उपधारा (i) के अंतर्गत विभिन्न गांव—क्षेत्रों] तहसील—देवी विहार—पुणे महाराष्ट्र के अंतर्गत अधिकृतना में खणित भूमि में खसरा नम्बर, हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल क्रमांक 1 के धरते अनुसूची में खसरा नम्बर, हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल क्रमांक 2 में दी गई अनुसूची को पढ़ें।

निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में खणित भूमि में पाई जाई विकास का प्रयोजन अनाईटमेट बदलते से प्रवर्तन रहा है, प्रवर्तन के अंतर्गत अनुसूची के भाग 3 में खणित भूमि घारा 3 के उपधारा (i) के अधिकृतना की अनुसूची से कम कार दी गई है।

अनुसूची

भाग I

क्रमांक II पर्याप्त		क्रमांक 1 के लिए					
गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल	गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8
चहोली	134	1 + 4	00-32-40	चहोली	134	का. संग	00-47-00
	134	4	00-36-54		302	"	00-25-00
	302	1	00-16-20				
	303	1	00-43-06		303	"	00-20-00
	303	2	00-18-75				
	305	का. भाग	00-27-00		305	"	00-19-00
	307	1	00-05-50		307	"	00-36-00
	309	1	00-14-58		309	"	00-47-00
	352	1	00-70-00		352	"	00-45-00
	352	2	00-05-40				
	406	3 + 4	00-32-40		406	"	00-47-00
	408	2	00-21-60		408	"	00-39-00
	409	का. भाग	00-16-20		409	"	00-45-00
	410	"	00-39-60		410	"	00-36-00
	414	1	00-08-64		414	"	00-12-00
	428	1	00-08-66		428	"	00-22-00
	430	3	00-18-00				

भाग 1

कालम 1 के लिए

कालम II पढ़े	वासरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	सेवफल	गांव	वासरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	सेवफल
चहोसी	430	4	00-06-00	चहोसी	430	का भाग	00-34-00
	430	5	00-14-40			"	00-18-00
	432	1	00-07-00		432	"	00-19-00
	432	6	00-05-94			"	00-27-00
	433	2	00-16-25		433	"	00-39-00
	433	3	00-10-08			"	00-52-00
	435	1=प	00-01-62		435	"	00-34-00
	435	1=स	00-15-30			"	00-45-00
	435	2	00-05-40			"	00-20-00
	443	2+4	00-14-76		443	"	00-22-00
	444	का भाग	00-29-62		444	"	00-39-00
	445	"	00-25-92		445	"	00-41-00
	668	1+7	00-61-60		668	"	00-39-00
	669	का भाग	00-28-44		669	"	00-25-00
		"	00-39-60		670	"	00-41-00
	711	(1+3)	00-06-90		711	"	00-09-00
	712	का भाग	00-18-50		712	"	00-20-00
		"	00-21-60		713	"	00-23-00
	714	"	00-32-40		714	"	00-45-00
	736	3	00-14-94		736	"	00-22-00
	737	1	00-06-39		737	"	00-09-00
	737	2	00-04-50				
	738	2	00-09-00		738	"	00-08-00
	738	3					
	738	4	00-03-39		739	"	00-68-00
	739	का भाग	00-34-40				
	798	1	00-08-64		798	"	00-17-00
	798	2	00-05-58				
	798	3	00-21-60				
	799	1	00-14-76		799	"	00-13-00
	800	4	00-01-80		800	"	00-14-00
	803	का भाग	00-09-00		803	"	00-16-00
	804	2	00-32-40		804	"	00-38-00
	811	का भाग	00-63-36		811	"	00-44-00

भाग II

गांव	वासरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	सेवफल
चहोसी	306	का भाग	00-02-00
	353	"	00-22-00
	407	"	00-01-00
	431	"	00-02-00
	718	"	00-13-00
	719	"	00-07-00

इ. सलम प्राधिकारी

[क. O-12016 /133 /83 - प्रीष्ठ]

New Delhi, the 28th October, 1986

CORRIGENDUM

S.O. 3851.—In the Notification of Government of India, Ministry of Energy (Department of Petroleum) No. O-12016/133/83-Prod., date 10-12-83 published under S.O. No. 4448 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) at pages 4586 & 4587 issued under Section 3, Sub-section (i) of the Petroleum & Minerals Pipe Lines (Acquisition of

Right of User in Land) Act, 1962 in respect of villages Charholi for S. Nos. and areas shown in the Column No. 1 of the Schedule appended to this corrigendum, read S. Nos. and areas as shown in column No. 2 of the said schedule.

Lands mentioned in the Part II of the appended schedule, however do not come under the Pipe Line Project due to change in the alignment and therefore, they are deleted from the schedule appended to the Notification under Section 3, Sub-section (i) referred to above :

SCHEDULE

Read (Col II)

For (Col-I)

PART-I

Village	G. No.	H. No.	Area	Village	G. No.	H. No.	Area
Charoli	124	1+4	00-32-40	Charoli	134	(Pt)	00-47-00
	134	4	00-36-54		302	(Pt)	00-25-00
	302	1	00-16-20		303	(pt)	00-20-00
	303	1	00-43-06		305	(pt)	00-19-00
	303	2	00-18-75		307	(pt)	00-36-00
	305	(pt)	00-27-00		309	(pt)	00-47-00
	307	1	00-05-50		352	(pt)	00-45-00
	309	1	00-14-58		352	(pt)	00-47-00
	352	1	00-70-20		406	(pt)	00-47-00
	352	2	00-05-40		408	(pt)	00-39-00
	406	3+4	00-32-40		409	(pt)	00-45-00
	408	2	00-21-60		410	(pt)	00-36-00
	409	(pt)	00-16-20		414	(pt)	00-12-00
	410	(pt)	00-39-60		428	(pt)	00-22-00
	414	1	00-03-64		430	(pt)	00-34-00
	428	1	00-05-66		432	(pt)	00-18-00
	430	3	00-18-00		432	(pt)	00-19-00
	430	4	00-05-00		433	(pt)	00-27-00
	430	5	00-14-40		433	(pt)	00-34-00
	432	1	00-07-00		435	(pt)	00-39-00
	432	6	00-05-94		435	(pt)	00-52-00
	433	2	00-16-25		443	(pt)	00-34-00
	433	3	00-10-08		444	(pt)	00-39-00
	435	1-A	00-01-62		444	(pt)	00-41-00
	435	1-B	00-15-30		445	(pt)	00-25-00
	435	2	00-05-40		668	(pt)	00-41-00
	443	2+4	00-14-76		668	(pt)	00-39-00
	444	(pt)	00-29-62		669	(pt)	00-45-00
	445	(pt)	00-25-92		670	(pt)	00-32-00
	668	1+07	00-61-60		711	(pt)	00-09-00
	669	(pt)	00-28-44		712	(pt)	00-20-00
	670	(pt)	00-39-60		713	(pt)	00-23-00
	711	(1+3)	00-06-90		714	(pt)	00-45-00
	712	(pt)	00-18-50		736	(pt)	00-32-00
	713	(pt)	00-21-60		736	(pt)	00-09-00
	714	(pt)	00-32-40		737	(pt)	00-09-00
	736	3	00-14-94		737	(pt)	00-09-00
	737	2	0-04-39		738	(pt)	00-09-00
	737	2	0-04-50		738	(pt)	00-09-00
	738	2	00-09-00		738	(pt)	00-09-00
	738	3	00-03-39		739	(pt)	00-68-00
	738	4	00-34-40		798	(pt)	00-17-00
	739	(pt)	00-08-64		798	(pt)	00-17-00
	798	1	00-05-58		798	(pt)	00-17-00
	798	2	00-21-60		798	(pt)	00-17-00
	798	3					

Village	G. N.	H. No.	Area	Village	G. No.	H. No.	Area
Charoli—(concl.)	799	1	00-14-76	Charoli (contd.)	799	(pt)	00-13-00
	800	4	00-01-80		800	(pt)	00-14-00
	803	7(pt)	00-09-00		803	(pt)	00-16-00
	804	2	00-32-40		804	(pt)	00-38-00
	811	(pt)	00-63-36		811	(pt)	00-32-00

PART-II

Village	G. No.	H. No.	Area
Chroll	306	(pt)	00-02-00
	353	(pt)	00-22-00
	407	(pt)	00-01-00
	431	(pt)	00-02-00
	718	(pt)	00-13-00
	719	(pt)	00-07-00

Sd./
(Competent Authority)
[No. O-12016/133/31-P:21]

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1986

का. ना. 3851.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ए.ट.एन.सी.आर. से ए.ए.ए.सी.टी.ए.क. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आपोग द्वारा विभाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्यावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अंजित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज वाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अंजन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अंजित करने का अपना आशय एतबद्वारा घोषित किया है :

बायतें कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के भीतर पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आपोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत :

अनुसूची

एस. एन. सो. आर. से एम. एम. सी. टी. ए.क. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : मेहसाना

गांव	सर्वे नं	हेक्टर	आर.	सेटीयर
बलोल	1757	0	12	60
	1760	0	07	68
	1652	0	07	20
	1762	0	01	32

[सं O-12016/186/86 ओ एत जो-डी-4]

New Delhi, the 29th October, 1986

S.O. 3852.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SNCR to S. S. CTF in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1952), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the said Land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makaroura Road, Badodara, (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipe line from ROU from SNCR to S.S. CTE.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Acre	Centiares
Balol	1757	0	12	60
	1760	0	07	68
	1652	0	07	20
	1762	0	01	32

[No. O-12016/186/86-ONG-D 4]

का० आ० 3853.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में वह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं. 15 से एस.आई.पी. 34 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विभाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रति होता है कि ऐसी लाइनों को विभाने के प्रयोजन के लिये एन्ड्रुपावड़ अनुपूर्वी में विभिन्न भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आवश्यक एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई अस्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाईन विभाने के लिए आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं. करजासन-1 से कलोनी-126 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विभाई जानी चाहिए।

और ऐसा आवश्यक करने वाला हर अवित्त विनियिक्तः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उससे सुनवाई अवित्तगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायों को माफ़ित।

प्रनस्तुती

कूप नं. 15 से एस.आई.पी.-34 तक पाइप लाइन विभाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कड़ी

गोब	सर्वे नं	हेक्टर	आर.	सेंटीयर
थोल	1423/पी	0	55	00

[सं. O-12016/185/86-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 3853.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. 15 to S.I.P. 34 in Gujarat State pipeline should be laid by the oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any Person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Comptent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from well No. 15 to S.I.P. 34,

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Acre	Centiares
Thol	1423/P	0	55	00

[No. O-12016/185/86-ONG. D 4]

का० आ० 3854.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में वह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं. करजासन-1 से कलोनी-126 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विभाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विभाने के प्रयोजन के लिये एन्ड्रुपावड़ अनुपूर्वी में विभिन्न भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आवश्यक एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई अस्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाईन विभाने के लिये आवश्यक सभग प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आवश्यक करने वाला हर अवित्त विनियिक्तः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसको सुनवाई अवित्तगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायों की माफ़ित।

अनुसूची

कूप नं. करजीसन-1 से कलोल-126 तक पाइप लाइन
विलाने के लिये।

राज्य: गुजरात जिला: मेहसाना तालुका: कड़ी

SCHEDULE

Pipeline from well No. Karjisan-1 to Kalol-126

State : Gujarat Taluka : Kadi District : Mehsana

गांव	सर्वे नं.	हैक्टेयर आर.	सेन्टीयर
धुमासन	670	0	18 30
	669	0	3 0
	671	0	18 90
	666	0	12 0
	733	0	4 50
	720	0	15 00
	721	0	18 00
	722	0	7 80
	114	0	14 80
	103	0	12 00
	113/2	0	4 50
	104/1	0	12 0
	105	0	5 40
	97	0	4 50
	96	0	5 40
कार्ट ट्रैक	0	0	90
95/5	0	6	0
134	0	12	15
175	0	12	30

[सं. ओ-12016/189/86-ओ एन. जी-डी-4]

S.O. 3854.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. Karjisan-1 to Kalol-126 in Gujarat State pipeline should be laid by the oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any Person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal Practitioner.

Village	Survey No.	Hec-tare	Acre	Cent	Acre
Ghumasan	670	0	18	30	
	669	0	3	0	
	671	0	18	90	
	666	0	12	0	
	733	0	4	50	
	720	0	15	00	
	721	0	18	00	
	722	0	7	80	
	114	0	14	80	
	103	0	12	00	
	113/2	0	4	50	
	104/1	0	12	0	
	105	0	5	40	
	97	0	4	50	
	96	0	5	40	
	Cart Track	0	0	90	
	95/5	0	6	0	
	134	0	12	15	
	175	0	12	30	

[N.O. O-12016/189/86-ONG D 4]

का.आ. 3855.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस.एन.सी. ए. से एस.एन.बी.ए. वे एन.एन.टी.टी.एफ. तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विलाई जानी वाली

आर. यतः यह प्रतीत होता है कि पेसी लॉनों को विलाने के प्रयोजन के लिये पट्टुपाबद्ध अनुसूची में जिन भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करता आवश्यक ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनित पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपशारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 'उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आवध एकद्वारा घोषित किया है ।

वर्णते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई अवृत्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन विलाने के लिये आवेदन संभग प्राप्तिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और बेंखमाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-8 की सूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

आर. ऐसा आवेदन करने वाला हर व्यक्ति विनियोजित: यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह आवृत्ता है कि उपकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि अवसरपै की मार्फत ।

अनुसूची

एस.एस.सो.ए. से एस.एन.बी.ए. से एस.एस.सी.टी. एफ. तक पाइप लाइन विछाने के लिये।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : मेहसाना

गांव	सर्वोन्न.	हैक्टेयर	आर.	सेंटीयर
संधार	492	00	08	28
	562	0	23	16

[सं. ओ-12016/176/86-ओ एन.जी.टी-4]

S.O. 3855.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SNCA to SNBA to S.S.CTF in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any Person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SNCA to SNBA to S.S. CTF
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hec- tare	Are	Centi- tare
Santhai	492	00	08	28
	562	0	23	16

[सं. ओ-12016/176/86-ONG-D4]

का.आ. 3856—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में डी.एस.नं. एस.के.एफ.ए. बी. से सी.टी.एफ. कड़ी तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आपोग द्वारा विछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि सभी लाइनों को विछाने के प्रयोजन के लिये एतत्पावर अनुसूची में वर्णित शूलि में उपयोग का अधिकार अंजित करना आवश्यक है।

अतः यब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अंजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है:

ब्रह्मते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन विछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आपोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, सकरपुरा रोड, बड़ोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यवितरण रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की माफत।

अनुसूची

डी.एस. नं. एस. के.ए.बी. से सी.टी.एफ. कड़ी तक पाइप लाइन विछाने के लिये।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कड़ी

गांव	सर्वोन्न.	हैक्टेयर	आर.	सेंटीयर
कड़ी	1643	0	9	75

[सं. ओ-12016/177/86-ओ.एन.जी.टी-4]

S.O. 3856.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Drill Site No. SKAB to C.T.F. Kadi in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any Person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Drill site No. SKAB to CTF Kadi.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centi- tiare
Kadi	1643	0 9 75		

[No. O-12016/177/86—ONG-D 4]

का. आ. ३८५७.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सोक आयल बाल्व पिलेट फार्म से आई.पी.एस. दक्षिण कड़ी तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आपोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एटदुपावड़ अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अंजित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अंजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बास्ते कि उक्त भूमि में तिहवद्द कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सभ्य प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आपोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ीदा-९ को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि व्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

सोक आयल बाल्व पिलेट फार्म से आई.पी.एस. दक्षिण कड़ी तक पाइपलाइन बिछाने के लिये।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कड़ी

गांव	सर्वेनं.	हैक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
कड़ी	1857	0 6 00		
	फार्ट ट्रैक	0 6 30		
	1953	0 2 55		
	1976	0 3 60		
	1977	0 4 50		
	1978	0 2 00		

[स. नो-12016/180/86-ओ.एस.पी.-४]

S.O. 3857.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Sokoil Vaive Platform to I.P.S. South Kadi in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any Person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Sokoil Valve platform to IPS. South Kadi

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centi- tiare
Kadi	1857	0 6 00		
	Cart Track	0 6 30		
	1953	0 2 55		
	1976	0 3 60		
	1977	0 4 50		
	1978	0 2 00		

[No. O-12016/180/86—ONG-D 4]

का.आ. ३८५८.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं. के-३९७ से जी जी०एस०-८ तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आपोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एटदुपावड़ अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अंजित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अंजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बास्ते कि उक्त भूमि में तिहवद्द कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सभ्य प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आपोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ीदा-९ की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों की अधिकार कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसी मुन्हाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की माफत।

अनुसूची

के० 397 से जी० जी० एम० V तक पाइपलाइन विभाग के लिए
राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कलोल

गांव	सर्वेन०	हेक्टर	आर०	सेन्टीयर
वडावस्वामी	100	0	09	00
	107	0	13	50
	106	0	07	50
	104/2	0	01	80
	100	0	05	70
	101	0	17	40

[सं० O-12016/178/86-ओएनजी-डी-4]

S.O. 3858.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. K-397 to G.G.S. V in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any Person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from K. 397 to GGS. V

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hec- tare	Are	Cent- tare
Wadavswami	100	0	09	00
	107	0	13	50
	106	0	07	50
	104/2	0	01	80
	100	0	05	70
	101	0	17	40

[N.S. O-12016/178/86-ONG.D 4]

का० घा० 3859 —यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीक्षा होता है कि लोकप्रिय में यह प्राप्तशक्ति है कि गुजरात

राज्य में कूप नं०-15 से एस०आई०पी०-34 तक पैदेलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपावेद्य अनुसूची में बणित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैदेलियम और छनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उपर्योग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एकट्ट-स्टार्ग घोषित किया है।

वर्णते कि उक्त भूमि में हितवद्वा कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देवभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी मुन्हाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की माफत।

अनुसूची

कूप नं० 15 से एस०आई०पी०-34 तक पाइपलाइन विभाग के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कलोल

गांव	सर्वेन०	हेक्टर	आर०	सेन्टीयर
हाजीपुर	615/1	0	07	50
		—	—	—
	1/ए			

[सं० O-12016/181/86-ओएनजी-डी-4]

S.O. 3859.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. 15 to S.I.P. 34 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any Person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipe line from Well No. 15 to SIP 34

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hec-tare	Acre	Centiares
Hajipur	615/1 1/A	0	07	50

[No. O-12016/181/86-ONG-D 4]

का०आ० 3860.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी०जी०एस० XI से जी०जी०एस० I तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपावद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरसुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से ज्ञो या किसी विभिन्न व्यटमाणों की मार्कत ।

अनुसूची

जी०जी०एस० XI से जी०जी०एस० I तक पाइपलाइन बिछाने के लिए ।

राज्य: गुजरात ज़िला व तालुका : गांधीनगर

गांव	लाकन० हृष्टयर आर० सन्टायर	1	2	3	4	5
अडलज	576	0	06	80		
	576	0	17	40		
	569	0	07	80		

	1	2	3	4	5
अडलज (ज़ारी)	571	0	02	70	
	570	0	11	80	
	557	0	03	40	
	556	0	09	00	
	555	0	01	70	

[सं० O-12016/182/86-ओएनजी-डो-4]

S.O. 3860.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from G.G.S. XI to G.G.S. I in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the said land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from GGS XI To GGS I.

State : Gujarat District & Taluka : Gandhinagar

Village	Block No.	Hec-tare	Acre	Centiares
Adalaj	576	0	06	80
	576	0	17	40
	569	0	07	80
	571	0	02	70
	570	0	11	80
	557	0	03	40
	556	0	09	00
	555	0	01	70

[No. O-12016/182/86-ONG-D 4]

का०आ० 3861.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का०आ० सं० 1270, तारीख 6-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

ओं पत: संसद प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम को भारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यह: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विवार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संबंध अनुमूली में विनियिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार वर्जित करने का विभिन्नत्व किया है।

यद्यपि, अतः उक्त अधिनियम की घारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शर्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एकत्रात्मा अधिकार करती है कि उस अधिसूचना में संबंध अनुमूली में विनियिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइंगचाहा विलाने के प्रयोजन के लिए एकत्रात्मा वर्जित किया जाना है।

और आगे उस घारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त अधिकार में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित इनी यी बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी वादायों से मुद्रा रूप में, जोधना के प्रकाशन की इस तारीख पर विभिन्न होगा।

अनुमूली

जी० नी० अस०-॥ ने सोगासन सी०टी०एफ० तक पाइपलाइन विलाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाना
गांव व तालुक नं० हेस्टेपर मारे० सेन्टीपर

पुनातन	1	2	3	4	5
404/2	0	05	70		
403	0	03	00		
360	0	00	10		
402	0	00	40		
372	0	01	70		
373	0	04	40		
374	0	03	75		
393	0	01	00		
392	0	03	50		
कार्ट ट्रैक	0	00	60		
391	0	02	60		
390	0	04	30		
432	0	02	10		
433	0	01	75		
434	0	02	75		
90	0	01	50		
4	0	02	80		
3	0	02	25		
कार्ट ट्रैक	0	00	15		

पुनातन (आरी)	1	2	3	4	5
68	0	05	50		
87	0	01	10		
73	0	00	15		
74	0	02	00		
कार्ट ट्रैक	0	00	50		
36	0	06	00		
80	0	01	00		
82	0	04	50		
31	0	01	50		
0	00	25			

[सं० O-12016/31/S5/-जीएनजी-३-४]

S.O. 3861.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. 1270 dated 6-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration, in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE
Pipeline from GGS II to C.T.F. Sobhasan
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hec- tare	Are	Con- tiare	1	2	3	4	5
Punasan	404/2	0	05	70					
	401	0	03	00					
	360	0	00	10					
	402	0	00	40					
	372	0	01	70					
	373	0	04	40					
	374	0	03	75					
	393	0	01	00					
	392	0	03	50					
	Cart track	0	00	50					
	391	0	02	60					
	390	0	04	30					
	432	0	02	10					
	433	0	01	75					
	434	0	02	75					
	90	0	01	50					
	4	0	02	80					
	3	0	02	25					
	Cart track	0	00	25					
	434	0	01	75					
	434	0	02	75					

1	2	3	4	5
Puwasen (Contd.)	90	0	01	50
4	0	02	60	
3	0	02	25	
Cart track	0	00	15	
68	0	05	50	
87	0	01	10	
73	0	00	15	
74	0	02	00	
Cart track	0	00	50	
86	0	06	00	
80	0	01	00	
82	0	04	50	
81	0	01	50	
Cart track	0	00	25	

[No. O-12016/31/85-ONG-D4]

का०आ० 3862.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में वासना-7 से वासना-3 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिय पाइपलाइन तेज तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिय एतदुपाद्व अंतु सूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतरा घोषितकिया है।

बायाँ कि उक्त भूमि में हिन्दूड कोई डिक्टित उस भूमि के नीवे पाइपलाइन बालाने के लिय आक्षेप समझ प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा बांदोदरा-9 को इस धिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की माफ़त।

मनुसूची

कृप मं० वासना-7 से वासना-3 तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : सेवा तालुका : मेहमदाबाद

गांव	लालनं०	क्षेत्रयर मार०	सेवीयर	
1	2	3	4	5
महीज	1240	0	04	50
	1227	0	10	38

1	2	3	4	5
महीज (जारी)	1256	0	17	70
	1255	0	01	50
	1273	0	09	00
	1274	0	06	60
	1275	0	18	00
	1277	0	06	30
	1270	0	20	50
	1292	0	18	45
	1295	0	10	65
	1294	0	06	30
	1312	0	12	30

[सं० O-12016/179/86-ओएनजी-डी-4]

S.O. 3862.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. Wasna-7 to Wasna-3 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereeto:—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any Person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. Wasna-7 to Wasna-3

State : Gujarat District : Kaira Taluka : Mehmabad

Village	Block No.	Hec- tare	Are	Cent- tare
Mahij	1240	0	04	50
	1237	0	10	35
	1256	0	17	70
	1255	0	01	50
	1273	0	09	00
	1274	0	06	60
	1275	0	18	00
	1277	0	06	30
	1278	0	20	50
	1292	0	18	45
	1295	0	10	65
	1294	0	06	30
	1312	0	12	30

[No. O-12016/179/86-ONG-D 4]

का. आ. 3863:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कृप नं के-443 से डब्ल्यू एच आई पानसर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन लेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विद्युत जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विछाने के प्रयोजन के लिए एन्डोवर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अनन्त आवश्यक एतद्वारा घोषित किया है।

बताते कि उक्त भूमि में डिटर्मिनेट कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे विश्वासी विछाने के लिए आक्षेप संबंध प्राप्ति-कारी, लेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकारपुरा रोड, बडौदहा-9 को इस अविसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने काला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि अवसायी की आवश्यकता नहीं।

अनुसूची

कृप नं के-443 से डब्ल्यू एच आई पानसर तक पाइपलाइन विछाने के लिए

राज्य : गुजरात तालुका : कलोल जिला : मेहसाना

गांव	ब्लॉक नं	हैक्टर	अ.र	सेंटीयर
पानसर	17	0	08	80
	17	0	09	15
कार्ट्रक	0	01	35	
1637	0	04	50	
1636	0	09	75	
1640	0	07	50	
1610	0	11	10	
1611	0	11	85	
1601	0	00	75	
1602	0	03	30	
1600	0	09	15	
1604	0	05	70	
1600	0	01	50	

[†. O-12016/190/86-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 3863.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. K-443 to WHZ-Pansar in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any Person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. K-443 to WHI Pansar

State : Gujarat Taluka : Kakol District : Mehsana

Village	Block No.	Hecta- res aro	Are Centi- ares
Pansar	17	0	08
	17	0	09
Crt Track	0	01	35
1637	0	04	50
1636	0	09	75
1640	0	07	50
1610	0	11	10
1611	0	11	85
1601	0	00	75
1602	0	03	30
1600	0	09	15
1604	0	05	70
1600	0	01	50

[No. O-12016/190/86-ONG D4]

का. आ. 3864:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कृप नं कलाल-8 से के-188 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन लेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विद्युत जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विछाने के प्रयोजन के लिए एन्डोवर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आपण एतद्वारा घोषित किया है।

यशर्तों कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडौदरा-9 को इस अधिसूचना को तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कूप नं. कलोल-8 से के-188 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : व तालुका : गांधीनगर

गांव	ब्लाक नं.	हैवट्यर	सेटीयर
जमीयतपुरा	336	0	03 00
	311	0	07 50
	334	0	02 35
	312	0	06 30
	313	0	09 15
	310	0	09 15
	308	0	21 00
	298	0	09 00
	297	0	06 00
	271	0	07 05
	270	0	09 30
	259	0	06 00
	261	0	06 15
	237	0	16 50
	229	0	10 50
	230	0	13 50
	3	0	12 30
	42	0	26 30
	54	0	12 60

[सं. O-12016/184/86-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 3864.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. Kulal-8 to Well No. K-188 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any Person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline From Well No. Kalol-8 to K-188

State : Gujarat Taluka & District : Gandhinagar

Village	Block No.	Hect- are	Arc- are	Centi- are
Jamiyat Pura	336	0	03	00
	311	0	07	50
	334	0	02	35
	312	0	06	30
	313	0	09	15
	310	0	09	15
	308	0	21	00
	298	0	09	00
	298	0	09	00
	297	0	06	00
	271	0	07	05
	270	0	09	30
	259	0	06	00
	261	0	06	15
	237	0	16	50
	229	0	10	50
	230	0	13	50
	3	0	12	30
	42	0	26	30
	54	0	12	60

[No. O-12016/184/86-ONG-D-4]

का. प्रा. 3865:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं. के-243 से जी सी एस कसोल तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का प्रधिकार प्रदित्त करना आवश्यक है।

अतः ग्रब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के प्रधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का प्रधिकार प्रदित्त करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

यशर्तों कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडौदरा-9 को इस अधिसूचना को तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और एसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की माफत ।

मनुसूची

कूप नं. के-243 से जी सी एस कलोल तक पाइप लाइन बिछाने के लिये ।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कलोल

गांव	ब्लॉक नं	हेक्टेयर	आर	सेंटीयर
ओला	471	0	06	00
	473	0	06	60
कार्ट ट्रूक	0	01	05	
	474	0	10	65

[सं O-12016/183/86-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 3865.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. K-243 to G.C.S. Kulal in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any Person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. K-243 to GCS Kalol
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Block No.	Hecta- are	Arc	Con- tiare
Ola	471	0	06	00
	473	0	06	60
Cart Track	0	01	05	
	474	0	10	65

[No. O-12016/183/86-ONG-D4]

का.आ. 3866:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं. 15 से एस आई पी 34 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पावद्ध अनुसूची में विभिन्न भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

यतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्धारा घोषित किया है ।

वशर्ते कि उक्स भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और एसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की माफत ।

मनुसूची

कूप नं. 15 से एस आई पी 34 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कलोल

गांव	ब्लॉक नं	हेक्टेयर	आर	मेंटीयर
1	2	3	4	5
जेठलज	372/2	0	06	50
	364/1	0	01	50
	364/2	0	04	70
	362/1	0	03	00
	357/1	0	04	70
	357/2	0	01	45
काट ट्रूक	0	00	45	
	475	0	03	45
	477/3	0	01	05
	477/1	0	2	50
	478/जी/1	0	3	53
	478/1/सी	0	2	55
	49/1/ए	0	0	50
	480/2	0	1	95
	480/1	0	2	20
	486	0	3	55
	483	0	1	15
	484	0	04	20
	550/2	0	04	50

1	2	3	5	6
550/1		0	04	35
1		0	07	20
7		0	02	20
8/2		0	00	80
9/2		0	02	20
10/पी		0	00	75
10/पी		0	01	70
24/1		0	01	00
27/2		0	01	00
28		0	01	70
29/2		0	01	70
30/1		0	01	80
31/पी		0	02	10
31/पी		0	05	90
32/2		0	03	45
32/पी		0	01	95
32/पी		0	02	10
कार्ट ट्रैक		0	02	35
162/2		0	02	65
162/1		0	01	65
148		0	03	85
149		0	04	20
146		0	02	15
98/1		0	04	25
99/2		0	03	40
89		0	01	40
91/2		0	12	30
92/2		0	04	50
92/1		0	00	50
61		0	03	55
60		0	03	00
58		0	02	60
56		0	03	75
57		0	04	05

[सं. O-12016/188/86-ओन्जी ई-4]

Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Piping from Well No. 15 to S.I.P. 34

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hecta-are			Are Cen- tiare
		1	2	3	
Jethlaj	372/2			0	06 50
	364/1			0	01 50
	364/2			0	04 70
	362/1			0	03 00
	357/1			0	04 70
	357/2			0	01 45
	Cart Track			0	00 45
	475			0	03 45
	477/3			0	01 05
	477/1			0	2 50
	478/B/1			0	3 55
	478/I/C			0	2 55
	479/I/A			0	0 50
	480/2			0	1 95
	480/1			0	2 20
	486			0	3 55
	483			0	1 15
	484			0	04 20
	550/2			0	04 50
	550/1			0	04 35
	1			0	07 20
	7			0	02 20
	8/2			0	00 80
	9/2			0	02 20
	10/P			0	00 75
	10/P			0	01 70
	24/1			0	01 00
	27/2			0	01 00
	28			0	01 70
	29/2			0	01 70
	30/1			0	01 80
	31/P			0	02 10
	31/P			0	05 90
	32/2			0	03 45
	32/P			0	01 95
	32/P			0	02 10
	Cart Track			0	00 35
	162/2			0	02 65
	162/2			0	01 65
	148			0	03 85
	149			0	04 20
	146			0	02 15
	98/1			0	04 25
	99/2			0	03 40
	89			0	01 40
	91/2			0	12 30
	92/2			0	04 50
	92/1			0	00 50
	61			0	03 55
	60			0	03 00
	58			0	02 60
	56			0	03 75
	57			0	04 05

[No. O-12016/188/86-ONG-D4]

S.O. 3866.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. 15 to S.I.P.-34 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any Person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent

का. आ. 3867 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में क-386 से जी जी एस 6 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिलाई जानी चाहिए;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिलाने के प्रयोजन के लिए एकत्रावद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है :

बास्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिलाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रमाण, मकरपुरा, रोड बोदरा-9 को इस अधिसूचना को तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

के— 386 मे जी. जी. एस— 6

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : काडी

गांव	सर्वे नं	हेक्टर	आरे	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
मुलासन	383	0	14	10
	397/1	0	09	15
	426	0	21	30
	422/1	0	07	50
	421	0	06	00
	420	0	06	00
	430	0	06	75
	431/1	0	17	10
	434	0	14	70

[सं O-12016/187/86-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 3867.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from K-386 to G.G.S.-6 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the Pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

SCHEDULE

Pipe Line from K-386 to GGS 6.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Arc	Centiare
Zulasan	383	9	14	10
	397/1	0	09	15
	426	0	21	30
	422/1	0	07	50
	421	0	06	00
	420	0	06	00
	430	0	06	75
	431/1	0	17	10
	434	0	14	70

[No. O-12016/187/86-ONG-D 4]

का.आ. 3868 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) व्वी धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3208 तारीख 20-9-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइन को बिलाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है;

और आग यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनियन्य किया है;

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है, कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिलाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त प्रधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बंदर्व के खेत्रोकरण में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

गांव—बाधोली तहसील—हवेली जिला—पुणे, महाराष्ट्र

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	भेत्रफल
बाधोली	2063	"	00-40
	2060	"	00-11
	2062	"	00-24
	2069	"	00-20
	2070	"	00-01
	2074	"	00-06
	2075	"	00-11
	2076	"	00-11
	2077	"	00-11
	2078	"	00-33
	2079	"	00-22
	2089	"	00-09
	2222	"	00-21
	2223	"	00-18
	2225	"	00-27
	2226	"	00-18
	2229	"	00-09
	2230	"	00-04
	2272	"	00-27
	2273	"	00-61
	2274	"	00-38
	2275	"	00-25
	2272	"	00-76
	2307	"	00-67
	2328	"	00-33
	2329	"	00-76
	2333	"	00-47
	2335	"	00-34

[सं 0-12016/57/83-प्रोड]

S.O. 3868.—Whereas by a notification of Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O. 3208 dated 20-9-86 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the Lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further the Central Government has after considering the said report decided to acquire the right of user in the Lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification are hereby acquired for laying the pipelines;

And further, in exercise of the power conferred by Sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Bombay free from all encumbrances.

SCHEDULE

Village : Magholi		Tahsil : Haveli,		Dist : Pune	
Village	Survey No.	Gut No.	Hissa No.	Area H A	
Vagholi	2063	Part		00	40
	2060	"	"	00	11
	2062	"	"	00	24
	2069	"	"	00	20
	2070	"	"	00	01
	2074	"	"	00	06
	2075	"	"	00	11
	2076	"	"	00	11
	2077	"	"	00	11
	2078	"	"	00	33
	2079	"	"	00	22
	2089	"	"	00	09
	2222	"	"	00	21
	2223	"	"	00	18
	2225	"	"	00	27
	2226	"	"	00	18
	2229	"	"	00	09
	2230	"	"	00	04
	2272	"	"	00	27
	2273	"	"	00	61
	2274	"	"	00	38
	2275	"	"	00	25
	2272	"	"	00	76
	2307	"	"	00	67
	2328	"	"	00	33
	2329	"	"	00	76
	2333	"	"	00	47
	2335	"	"	00	34

[No. O-12016/57/83-Prod]

का. आ. 3869 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का प्राप्ति) अधिनियम 1962 (1962 का 50) को धाया 3 को उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3196 तारीख 20-9-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन को विभाजने के प्रयोगन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और आगे सभी प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे यह: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

प्रब श्रन: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है, कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बंबई के खेत्रीकरण में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

तहसील — खेड जिला — पुणे, महाराष्ट्र

गांव	खसरा	हिस्सा	क्षेत्रफल
	नम्बर		नम्बर
मांगूडे	76	"	00-03-60
	111	"	00-10-08
	112	"	00-07-92
	129	"	00-30-24

[सं. O-12016/142/86 — ओ एन जी-डी - 4]

S.O. 3869.—Whereas by a notification of Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. 3196 dated 20-9-86 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the Lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the Lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification are hereby acquired for laying the pipelines;

And further, in exercise of the power conferred by Sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Bombay free from all encumbrances.

SCHEDULE

Village : Sangunde Tehsil : Khed Dist : Pune, Maharashtra

Village	S. No.	H. No.	Area
Sangunde	76	Part 00 03 60	
	111	,, 00 10 08	
	112	,, 00 07 92	
	129	,, 00 30 24	

[No. O-12016/142/86-ONG-D4]

का. आ. 3870.—यह: पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का भर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3195 तारीख 20-9-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाईप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना प्राप्त घोषित कर दिया था;

और दत्त: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे, यह: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

प्रब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है, कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड मुंबई के खेत्रीकरण में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

तहसील — खालापुर जिला — रायगड, महाराष्ट्र

सं०	गांव	खसरा	हिस्सा	क्षेत्रफल
		नम्बर		नम्बर
1	2	3	4	5
(1)	सोधीवली	106	—	00-01-35
		107-अ	—	00-05-40
		108	7	00-04-75

1	2	3	4	5
(2)	पसरोली	41	1	00-00-4-50
		53	--	00-01-50
(3)	निगडोली	39	--	00-25-38
		89	1	00-08-82
		89	2	00-02-25
		97	4(1)	00-08-75
		97	4	00-06-12
		97	5	00-16-64
		100	5	00-06-94
		100	6	00-10-08
		100	9	00-07-74
		106	--	00-23-92
		119	--	00-23-00
(4)	शिरवली	7	--	00-07-70
		13	--	00-02-70
(5)	कर्बे खालापुर	गांवठाण का भाग		
				00-10-35
		131	1	00-12-78
(6)	मध	72	4	00-09-65
		101	--	00-03-60
		103	--	00-03-24
		104	1	00-00-90
(7)	हालखुर्द	27	--	00-04-05
(8)	अजोशी	6	1	00-16-00
		13	--	00-04-00
(9)	शोल	19	2	00-03-00
		2452	00-01-86	
		2450	00-01-68	
	सीटीएस	2443 का भाग		00-03-38
(10)	वरोसे	16	का भाग	00-06-37
(11)	काटरंग	3	"	00-12-15

[सं O-12016/143/86-ओ एन जी-डी - 4]

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government,

And further the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the Lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification are hereby acquired for laying the pipelines,

And further, in exercise of the power conferred by Sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Bombay free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipe Line from Ladhivali to Katrang.

Taluka : Khalapur. Dist : Raigad, Maharashtra.

Sr. No.	Village	S. No. G. No.	H. No.	Area
1.	Ladhivali.	106 (pt) 107-A 108 7	00 01 35 00 05 40 00 04 75
2.	Asroti.	41 53 (pt)	1 ..	00 04 50 00 01 50
3.	Nigdoli.	39 (pt) 89 89 97 97 97 97 100	.. 1A 2B 4A(1) 4K 5 5	00 25 38 00 08 82 00 02 25 00 08 75 00 06 12 00 16 64 00 06 94
4.	Shirvali	7 (pt) 13 (pt)	00 07 70 00 02 70
5.	Karbe Khalapur.	Gaothan (Part) 131	.. 1	00 10 35 00 12 78
6.	Madh.	72 101 (pt) 103 (pt) 104	4 1	00 09 65 00 03 60 00 03 24 00 00 90
7.	Hal. Kd.	27 (pt)	..	00 04 05
8.	Ajoshi	6 13 (pt)	1 ..	00 16 00 00 04 00
9.	Sheel.	19 C.T.S. C.T.S. C.T.S.	2 2452 (pt) 2450 (pt) 2443 (pt)	00 03 00 00 01 86 00 01 68 00 03 38
10.	Varose.	16 (pt)		00 06 37
11.	Katrang.	3 (pt)		00 12 15

[No. O-12016/143/86-ONG-D4]

S.O. 3870.—Whereas by a notification of Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. 3195 dated 20-9-86 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the Lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline,

ई. दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1986

शुद्धि पत्र

का. आ. 3871:—भारत सरकार के राजपत्र भाग II खंड 3 उपखंड, (ii) दिनांक 16/4/1983 पृष्ठ क्रमांक 1831, 1832, और 1833 का. आ. संख्या 120,16/31/82-प्रैष-II के अंतर्गत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना संख्या 1861 दिनांक 16-4-1983 के अंतर्गत पेट्रोलियम और खनिज पार्ईट लाईन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन, अधिनियम 1962 की धारा 6 उपधारा, (i) के अधीन वर्णित गांव-1 निगड़ोली 2. शिखली 3. वणवे 4. निबोड़े 5. नडोये तहसील खालापुर जिला-रायगढ़ महाराष्ट्र के अंतर्गत अधिसूचना में भूमि में खसरा नं., हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल कालम 1 के बदले अनुसूची में खसरा नम्बर, हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल कालम 2 में दी गई अनुसूची को पढ़ें।

निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि पार्ईट लाईन विभाने का प्रयोजन अलाइनमेंट बदलने से अब न रहा है। अब अतः निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में वर्णित भूमि की धारा 56 के उपधारा (i) के अधिसूचना के अनुसूची से कम कर दी गई है।

गांव	अनुसूची				कालम 1 के लिये			
	खसरा नंबर	हिस्सा नंबर	क्षेत्रफल है.	गांव आ.से.	खसरा नंबर	हिस्सा नंबर	क्षेत्रफल है.आ.से.	
निगड़ोली	59	0	00-11-40	निगड़ोली	59	का भाग	00-06-00	
"	60	0	00-01-35	"	60	"	00-06-00	
"	61	0	00-14-00	"	61	"	00-07-00	
"	62	1	00-07-75	"	62	"	00-07-00	
"	63	0	00-18-30	"	63	"	00-22-00	
"	64	1	00-07-50	"	64	"	00-13-00	
"	64	17-ब	00-11-88					
"	83	0	00-41-59	"	83	"	00-73-00	
"	84	0	00-07-00	"	84	"	00-07-00	
"	85	1	00-06-12	"	85	"	00-22-00	
"	90	0	00-00-56	"	90	"	00-18-00	
"	111	0	00-18-90	"	111	"	00-15-00	
"	113	2 क	00-03-00	"	113	"	00-22-00	
"	114	0	00-14-12	"	114	"	00-11-00	
"	118	3	00-14-38	"	118	"	00-38-00	
"	118	4 अ	00-12-12					
"	118	12 अ	00-18-00					
"	120	5 अ	00-05-40	"	120	"	00-23-00	
"	120	5 ब	00-06-00					
"	120	5 क	00-08-10					
"	120	5 झ	00-04-32					

भाग - II

निगड़ोली	91	का भाग	00-07-00
"	92	"	00-13-00
"	95	"	00-09-00
"	96	"	00-12-00
"	107	"	00-37-00

अनुसूची

कालम 2 पढ़े		भाग I			कालम 1 के लिए		
गांव	खसरा नंबर	हिस्सा नंबर	क्षेत्रफल हे.आ.से.	गांव	खसरा नंबर	हिस्सा नंबर	क्षेत्रफल हे.आ.से.
शिरवाली	4	1	00-10-26	शिरवाली	4	का भाग	00-15-00
"	4	2	00-05-40	"	"	"	"
"	5	0	00-07-84	"	5	"	00-15-00
"	10	0	00-06-57	"	10	"	00-07-00
"	11	0	00-05-40	"	11	"	00-02-00
"	12	0	00-05-40	"	12	"	00-07-00
"	34	1	00-04-40	"	34	"	00-07-00
"	35	1	00-03-60	"	35	"	00-04-00
"	35	2	00-02-70				
"	35	3	00-03-15				
"	35	4	00-02-70				
"	42	0	00-05-15	"	42	"	00-02-00
"	43	0	00-20-25	"	43	"	00-18-00
"	55	0	00-03-24	"	55	"	00-10-00
"	56	0	00-06-48	"	56	"	00-04-00
"	57	0	00-18-00	"	57	"	00-13-00
"	60	2	00-25-10	"	60	"	00-22-00

भाग II

शिरवाली	6	का भाग	00-01-00
"	51	"	00-04-00
"	41	"	00-11-00
"	54	"	00-01-00

अनुसूची

कालम 2 पढ़े		भाग I			कालम 1 के लिये		
गांव	खसरा नंबर	हिस्सा नंबर	क्षेत्रफल हे.आ.से.	गांव	खसरा नंबर	हिस्सा नंबर	क्षेत्रफल हे.आ.से.
बनवे	1	का भाग	00-02-70	बनवे	1	का भाग	00-19-00
	2	1	00-08-00		2		00-11-00
	3	का भाग	00-05-40		3		00-09-00
	4		00-08-10		4		00-04-00
	14		00-21-15		14		00-26-00
	15		00-16-06		15		00-07-00
	27	1	00-16-08		27		00-18-00
	27	2	00-04-77				
	32	का भाग	00-08-64		32		00-07-00
	47		00-09-18		47		00-04-00
	48		00-09-46		48		00-09-00
	50		00-02-40		50		00-05-00
	51		00-08-66		51		00-16-00
	52		00-08-26		52		00-05-00

भाग II

वर्तमान	46	का भाग	00-04-00	भाग I			
निबोड़े	30	1	00-01-98	निबोड़े	30	का भाग	00-02-00
	34	7	00-06-30		34		00-14-00
	36	0	00-03-75		36		00-20-00
	37	3	00-02-70		37		00-23-00
	41	2	00-28-08		41		00-30-00
	41	का भाग	00-16-72				
	56	1	00-10-80		56		00-22-00
	56	2	00-15-75				
	56	3	00-17-28				
	58	का भाग	00-06-48		58		07-00
	59	1	00-01-35		59		00-10-00
अमुक्तस्थी							
कालम 2 पर्यंत			भाग 1				कालम 1 के लिये
गांव	खसरा	हिस्सा	क्षेत्रफल	गांव	खसरा	हिस्सा	क्षेत्रफल
	नंबर	नंबर	हे.मा.से.		नंबर	संबर	हे.मा.से.
निबोड़े	62	3	00-12-65	निबोड़े	62	(Pt)	00-27-00
	62	5वी + 8	00-22-86				
	62	5	00-07-77				
	63	1	00-04-25		63	(pt)	00-16-00
	63	2	00-04-50				
भाग 2							
निबोड़े	64	का भाग	00-14-00	भाग 1			
नडोथे	26	का भाग	00-34-40	नडोथे	26	का भाग	00-14-00
	28		00-60-00		28		00-23-00
	43	1	00-17-42		43		00-57-00
	43	4	00-10-80				
	43	15	00-03-00				
	43	16	00-18-00				
	43	19	00-06-00				
	43	23	00-08-82				
	48	5 ए	00-29-70		48		00-18-00
	54	का भाग	00-12-0		54		00-06-00
	69		00-06-75		69		00-23-00
	70		00-18-90		70		00-05-00
	74	1	00-03-37		74		00-18-00
	74	2	00-05-94				
	74	3	00-05-85				
	75	का भाग	00-06-07		75		00-09-00
	79	भाग II	00-33-12		79		00-32-00
नडोथे	68	का भाग	00-05-00				
	78		00-37-00				

ह./-सत्यम् प्राधिकारी

[स. O-12016/31/82-प्रोड 1]

New Delhi, the 29th October, 1986

S.O. 3871.—In the Notification of Government of India, Ministry of Energy (Department of Petroleum) No-12016/31/82/Prod-II dated 16th April, 1983 published under S.O. No. 1861 in the Gazette of India Part II Section 3, sub-section (ii) at pages 1831, 1832 & 1833 issued under Section 6 of sub-section (i) of the Petroleum and Minerals Pipe lines (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 in respect of villages : 1. Nigdoli 2. Shirwali 3. Vanve 4. Nimbode

5. Nadodhe Tahsil Khalapur District Raigad, State Maharashtra, for S. Nos., Hissa Nos, and areas shown in the Column No-1 of the schedule appended to this corrigendum, read the S. Nos, H. Nos, and areas as shown in the column No II of the said schedule.

2. Lands mentioned in the part II of the appended schedule, however, do not come under the pipe line project due to change in the alignment and therefore, they are deleted from the schedule appended to the Notification under section 6 sub-section (i) referred to above.

Read (Col.II)

SCHEDULE

For (Col. I)

PART-I

Village	S.No. G.No.	H.No.	Area	Village	S.No. G.No.	H.No.	Area
			H.R.C.				H.R.C.
Nigdoli	59	(pt)	00-11-40	Nigdoli	59	(pt)	00-06-00
	60	(pt)	00-01-35		60	(pt)	00-06-00
	61	(pt)	00-14-00		61	(pt)	00-07-00
	62—1	(pt)	00-07-75		62	(pt)	00-07-90
	63	(pt)	00-18-30		63	(pt)	00-22-00
	64—1	(pt)	00-07-50		64	(pt)	00-13-00
	64	17/B	00-11-88				
	83	(pt)	00-41-59		83	(pt)	00-73-00
	84	(pt)	00-07-00		84	(pt)	00-07-00
	85	1	00-06-12		85	(pt)	00-22-00
	90	(pt)	00-00-56		90	(pt)	00-18-00
	111	(pt)	00-18-90		111	(pt)	00-15-00
	113	2 K	00-03-00		113	(pt)	00-22-00
	114	(pt)	00-14-12		114	(pt)	00-11-00
	118	3	00-14-38				
	118	4A	00-12-12		118	(pt)	00-38-00
	118	12A	00-18-00				
	120	5A	00-05-40				
	120	5B	00-06-00		120	(pt)	00-23-00
	120	5K	00-08-10				
	120	5D	00-04-32				

PART-II

Nigdoli	91	(pt)	00-07-00
	92	(pt)	00-13-00
	95	(pt)	00-09-00
	96	(pt)	00-12-00
	107	(pt)	00-37-00

SCHEDULE

Read Col.-II

For Col.-I

Part I

Village	S.No. G.No.	H. No.	Area	Village	S.No. G.No.	H. No.	Area
			H.R.C.				H.R.C.
Shirwali	4	1	00-10-26	Shirwali	4	(pt)	00-15-00
	4	2	00-05-40		5	(pt)	00-15-00
	5	(pt)	00-07-84		10	(pt)	00-07-00
	10	(pt)	00-06-57		11	(pt)	00-02-00
	11	(pt)	00-05-40		12	(pt)	00-07-00
	12	(pt)	00-05-40		34	(pt)	00-07-00
	34	1	00-04-40				
	35	1	00-03-50				
	35	2	00-02-70				
	35	3	00-03-15		35	(pt)	00-04-00
	35	4	00-02-70				
	42	(pt)	00-05-15		42	(pt)	00-02-00
	43	(pt)	00-20-25		43	(pt)	00-18-00
	55	(pt)	00-03-24		55	(pt)	00-10-00
	56	(pt)	00-06-48		56	(pt)	00-04-00
	57	(pt)	00-18-00		57	(pt)	00-13-00
	60	2	00-25-10		60	(pt)	00-22-00

PART-II

Village	S.No.	H.No.	Area
	G.No.		H.R.C.
Shirvali	6	(pt)	00-01-00
	51	(pt)	00-04-00
	41	(pt)	00-11-00
	54	(pt)	00-01-00

SCHEDEULE

Read (Col II)

For (Col I)

PART-I

Village	S.No.	H. No.	Area	Village	S.No.	H. No.	Area
	G.No.		H.R.C.		G.No.		H.R.C.
Wanave	1	(pt)	00-02-70	Wanave	1	(pt)	00-19-00
	2	1	00-08-00		2	(pt)	00-11-00
	3	(pt)	00-05-04		3	(pt)	00-09-00
	4	(pt)	00-08-10		4	(pt)	00-04-00
	14	(pt)	00-21-15		14	(pt)	00-25-00
	15	(pt)	00-16-06		15	(pt)	00-07-00
	27	1	00-16-08		27	(pt)	00-18-00
	27	2	00-04-77				
	32	(pt)	00-08-64		32	(pt)	00-07-00
	47	(pt)	00-09-18		47	(pt)	00-04-00
	48	(pt)	00-08-46		48	(pt)	00-09-00
	50	(pt)	00-02-40		50	(pt)	00-05-00
	51	(pt)	00-08-66		51	(pt)	00-16-00
	52	(pt)	00-08-26		52	(pt)	00-05-70

PART-II

Village	S.No.	H.No.	Area
	G.No.		H.R.C.

Wanave	46	(pt)	00-04-00
--------	----	------	----------

PART-I

Village	S.No.	H. No.	Area	Village	S.No.	H. No.	Area
	G.No.		H.R.C.		G.No.		H.R.C.
Nimbode	30	1	00-01-78	Nimbode	30	(pt)	00-02-00
	34	7	00-06-30		34	(pt)	00-14-00
	36	0	00-03-75		36	(pt)	00-20-00
	37	3	00-02-00		37	(pt)	00-23-00
	41	2K	00-28-08				
	41	(pt)	00-18-72		41	(pt)	00-30-00
	56	1	00-10-80				
	56	2	00-15-75		56	(pt)	00-22-00
	56	3	00-17-28				
	58	(pt)	00-06-48		58	(pt)	07-00-00
	59	1	00-01-35		59	(pt)	00-10-00

SCHEDEULE

Read Col II

For Col-I

PART-II

Village	S.No.	H.No.	Area	Village	S.No.	H. No.	Area
	G.No.		H.R.C.		G.No.		H.R.C.
Nimbode	62	2	00-12-65				
	62	5 B+8	00-22-86		62	(pt)	00-27-00
	62	5	00-07-77				
	63	1	00-04-25		63	(pt)	00-16-00
	63	2	00-04-50				

PART-II

Village	S.No.	H.No.	Area
Nimbode	64	(pt)	00-14-00
PART-I			
Nadodhe	26	(pt)	00-34-40
	28	(pt)	00-60-00
	43	1	00-17-42
	43	4	00-10-80
	43	15	00-03-00
	43	16	00-18-00
	43	19	00-06-00
	43	23	00-08-82
	48	5A	00-29-70
	54	(pt)	00-10-26
	69	(pt)	00-06-75
	70	(pt)	00-18-00
	74	1	00-03-37
	74	2	00-05-94
	74	3	00-05-85
	75	(pt)	00-06-07
	77	(pt)	00-33-12
			75
			79
			(pt) 00-09-00
			(pt) 00-32-00

PART-II

Village	S. No.	H. No.	Area
	G.No.		H.R.C.
Nadodhe	68	(pt)	00-05-00
	78	(pt)	00-37-00

Sd/- Competent Authority
[No. O-12016/31/82-Prod. I]

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1986

गृहिणी

का. आ. 3872—भारत सरकार के राजपत्र विभाग II, छप्प 3, उपचान्द (ii) दिनांक 20-9-1986 का आ. संख्या O-12016/31/82-प्रोड-II की प्रतिमूलता संख्या 3201 दिनांक 20-9-1986 पृष्ठ क्रमांक 3636 से 3640 तक जोड़े हुए अनुसूची में नीचे वर्णित किया हुआ छद्म किया जाता है।

1. गांव निवाड़े

के लिए पर्याप्त
खसरा नं० हि. नं. शेषकल खसरा नं० हि. नं. शेषकल
(i) 62-8-00-07-77 62-5-00-07-77

(ii) गांव नदीये

के लिए पर्याप्त
खसरा नं० हि. नं. शेषकल खसरा नं० हि. नं. शेषकल
(i) 54 का भाग 00-12-06 54-का भाग 00-10-26

ह०/- सक्षम अधिकारी

[नं. O-12016/31/82-प्रोड]

पी. के. राजगोपालन, डैस्ट्रिक्ट प्राइविटर

New Delhi, the 29th October, 1986

ERRATUM

S. O. 3872.—For the words and figures appearing in the Corrigendum to section 3 (i) Notification issued under Govt. of India's Notification No. O-12016/31/82-Prod-II under S.O. 3201 dated 20th September 1986 (Published in Govt. of India Gazette Part II—Section 3 (ii) page No. 3640 dated 20-9-86, read.

For			Road		
(i) S.No.	H. No.	Area	S.No.	H.No.	Area
(ii) Village—Nadodhe			62	9	00-07-77
(i) S.No.	H.No.	Area	S.No.	H.No.	Area
54	(pt)	00-12-06	54	(pt)	00-10-26

Sd/- Competent Authority,
[No. O-12016/31/82-Prod]
P.K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

स्वास्थ्य और परिवार काल्पनिक मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1986

का. आ. 3873.—भारतीय उपचान परिवद् प्रतिनियम, 1947 (1947 का 48) की धारा 3 की उपचान (i) के छप्प (j) के अनुसरण में राज्य सभा ने ग्राम सदस्यों में से श्रीमती विजय चक्रवर्ती को 13 मर्द, 1986 से श्रीमती रोडा मिस्ली के स्थान पर भारतीय उपचान परिवद् का सदस्य नियमित किया है।

प्रस: यह केन्द्रीय सरकार उक्त प्रतिनियम की धारा 3 की उपचान (i) के उपचानों के अनुसरण में भारत के राजपत्र, भाग-2, छप्प 3(i)

तारीख 8 दिसम्बर, 1958 में वृक्ष संख्या 1131 पर प्रकाशित भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रतिस्थापना संख्या का था। 1147 तारीख पहली दिसम्बर, 1958 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसंघना में “धारा 3 की उपधारा (1) के बाण्ड (4) के अधीन निर्वाचित” शीर्ष के अस्तर्गत अम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित त्रैम संख्याएं और प्रविष्टियाँ रखी जायेंगी, अर्थात् :—

“3. श्रीमती विजय चक्रवर्ती, संसद सदस्य”

[संख्या थी। 14013/1/86-पी.एम.एस.]

गोपना राजेश्वरी, उप सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Dept of Health)

New Delhi, the 31st October, 1986

S.O. 3873.—Whereas in pursuance of clause (o) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (48 of 1947), the Rajya Sabha has elected from among its Members Shrimati Bijoy Chakravorty on the 13th May, 1986 to be a Member of the Indian Nursing Council in place of Shrimati Roda Mistry.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Health No. S.O. 1147, dated the 1st December, 1958, published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i), dated the 6th December, 1958, at page 1131, namely :—

In the said notification, under the heading “Elected under clause (o) of sub-section (1) of section 3”, for serial number 3 and the entries relating thereto, the following Serial number and entries shall be substituted, namely :—

“3. Shrimati Bijoy Chakravorty, Member of Parliament.”

[No. V. 14013/1/86-PMS]

SHOBHANA RAJENDRAN, Dy. Secy.

अंतरिक्ष विभाग

बंगलौर, 20 अक्टूबर, 1986

का. प्रा. 3874 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरिक्ष विभाग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंतरिक्ष विभाग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अंतरिक्ष विभाग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1976 में :—

(i) “खण्ड VIII—पुनरीक्षण” शीर्षक के लिए निम्न-

लिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“खण्ड VIII—परिशोधन और पुनरीक्षण”, और “पुनरीक्षण” हासिये शीर्षक के लिए “परिशोधन” प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) नियम 26 के उप-नियम (1) में

(क) “पुनरीक्षण” शब्द के लिए “परिशोधित” शब्द प्रतिस्थापित किया जायगा और “पुनरीक्षण किया गया” शब्द के लिए “परिशोधित किया गया” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) पहले परन्तुक में, “पुनरीक्षण प्राधिकारी” शब्द के लिए “परिशोधन प्राधिकारी” शब्द प्रतिस्थापित किया जायगा और “पुनरीक्षण किया गया” शब्द के लिए “परिशोधित किया गया” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) दूसरे परन्तुक में, “पुनरीक्षण के अधिकार” शब्दों के लिए “परिशोधन के अधिकार” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) नियम 26 के उप-नियम (2) में, “पुनरीक्षण” शब्द के लिए “परिशोधन” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) नियम 26 के उप नियम (3) में, “पुनरीक्षण” शब्द के लिए “परिशोधन” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) नियम 26 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जायगा अर्थात् :—

“26-अ पुनरीक्षण—राष्ट्रपति, किसी भी समय स्वप्रेरणा पर या अन्यथा, इन नियमों के अंतर्गत पारित किसी आदेश का पुनरीक्षण कर सकेगा, जब कोई साक्ष या नई चीजें जो पुनरीक्षण के अधीन आदेश पारित करते समय प्रस्तुत महीं कर पाए या उपलब्ध नहीं करा सकें और जिसमें मामले की प्रकृति को ही बदलने के विचार उसके ध्यान में आये था लाया जाए।

परन्तु राष्ट्रपति द्वारा शास्ति अधिरोपित या वर्द्धित करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध सरकारी कर्मचारी को प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध अध्यावेदन करने का युक्तियुक्त प्रब्रह्म न दे दिया गया हो और जहां नियम 8 में विनियिष्ट प्रमुख शास्तियों में से कोई शास्ति या उस आदेश द्वारा अधिरोपित लघु शास्ति को कोई प्रमुख शास्ति के रूप में वर्द्धित करने के लिए पुनरीक्षण चाहा गया हो और यदि पहले ही मामले में नियम 11 के अधीन जांच नहीं किया गया हो, और जब तक नियम 16 के प्रावधानों के शर्त पर नियम 11 में निर्धारित सीति से जांच किए बिना, तथा जहां आयोग से परामर्श करना आवश्यक

हो, वहां ऐसे परामर्श किए विभा ऐसी शास्ति, अधिरोपित नहीं की जायगी।”

[सं 2/5(2)/86-V]

टी० एस० वैक्टरामन, उप सचिव

टिप्पण : प्रधान नियमों को दिनांक 1-4-1976 के अधिसूचना सं 2/9(12)/74-III(I) द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में दिनांक 1-4-1976 को प्रकाशित किया गया और नत्यशात् निम्नप्रकार संशोधन किये गये :—

क्रम सं	अधिसूचना सं	दिनांक
1.	2/10(32)/76-I	10-02-1977
2.	2/10(32)/76-I	16-05-1977
3.	2/10(27)/76-I	01-08-1977
4.	2/7(5)/77-I	15-02-1978
5.	2/7(5)/77-I	27-05-1978
6.	2/9(12)/74-III(I)	16-03-1979
7.	9/4(1)/80-III	26-05-1980
8.	9/4(1)/80-III	26-05-1980
9.	9/4(1)/80-III	05-09-1980
10.	9/4(1)/80-III	13-10-1980
11.	9/4(1)/80-III	13-10-1980
12.	9/4(1)/80-III	20-12-1980
13.	9/4(1)/80-III	20-12-1980
14.	2/8(1)/81-I	28-08-1981
15.	2/8(1)/81-I	16-07-1982
16.	2/9(1)/83-I(V)	29-07-1985
17.	2/5(1)/85-V	02-01-1986
18.	2/9(1)/83-I(V)	02-01-1986
19.	2/5(1)/86-V	17-03-1986

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore, the 20th October, 1986

S.O. 3874.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Space Employees' (Classification, Control and Appeal) Rules, 1976, namely:—

- (1) These rules may be called the Department of Space Employees' (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 1986.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Department of Space Employees' (Classification, Control and Appeal) Rules, 1976 :—
 - for heading "Part VIII—Review", the following heading shall be substituted namely :— "Part VIII—Revision and Review", and for the marginal heading "Review", "Revision" shall be substituted.
 - in sub-rule (1) of Rule 26
 - for the word 'review', the word 'revise' shall be substituted and for the word 'reviewed' the word 'revised' shall be substituted;

(b) in the first proviso, for the words 'reviewing authority', the words 'revising authority' shall be substituted and for the word 'reviewed' the word 'revised' shall be substituted;

(c) in the second proviso, for the words "power of review", the words "power of revision" shall be substituted;

(iii) in sub-rule (2) of rule 26, for the word 'review' the word 'revision' shall be substituted;

(iv) in sub-rule (3) of the rule 26 for the word 'review', the word 'revision' shall be substituted;

(v) after rule 26, the following rule shall be inserted namely :—

"26-A Review.—The President may, at any time, either on his own motion or otherwise, review any order passed under these rules, when any new material or evidence which could not be produced or was not available at the time of passing the order under review and which has the effect of changing the nature of the case, has come, or has been brought, to his notice.

Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by the President unless the Government servant concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed or where it is proposed to impose any of the major penalties specified in rule 8 or to enhance the minor penalty imposed by the order sought to be reviewed to any of the major penalties and if an enquiry under rule 11 has not already been held in the case, no such penalty shall be imposed except after inquiring in the manner laid down in rule 11, subject to the provisions of rule 16, and except after consultation with the Commission where such consultation is necessary."

[No. 2/5(2)/86-V]

T. S. VENKATARAMAN, Dy. Secy.

NOTE : Principal rules were published vide Notification No. 2/9(12)/74-III(I) dated 1-4-1976 in the Gazette of India (Extraordinary), Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated 1-4-1976 and have been subsequently amended by :—

Sl. No.	Notification No.	dated
1.	2/10(32)/76-I	10-02-1977
2.	2/10(32)/76-I	16-05-1977
3.	2/10(27)/76-I	01-08-1977
4.	2/10(5)/77-I	27-05-1978
5.	2/7(5)/77-I	27-05-1978
6.	2/9(12)/74-III(I)	16-03-1979
7.	9/4(1)/80-III	26-05-1980
8.	9/4(1)/80-III	26-05-1980
9.	9/4(1)/80-III	05-09-1980
10.	9/4(1)/80-III	13-10-1980
11.	9/4(1)/80-III	13-10-1980
12.	9/4(1)/80-III	20-12-1970
13.	9/4(1)/80-III	20-12-1980
14.	2/8(1)/81-I	28-08-1981
15.	2/8(1)/81-I	16-07-1982
16.	2/9(1)/83-I(V)	29-07-1985
17.	2/5(1)/85-V	02-01-1986
18.	2/9(1)/83-I(V)	02-01-1986
19.	2/5(1)/86-V	17-03-1986

मानव संसाधन विकास भंगालय

(रिक्ता विभाग)

नई दिल्ली, ७ नवम्बर, १९८६

प्रारंभण

का. आ. ३८७५.—आरोविल (आपात उपबन्ध) अधिनियम, १९८० (१९८० का ५९) की धारा ५ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, तथा केन्द्रीय सरकार, जिका तथा मंसूखनि मंत्रालय (जिका विभाग) के आदेश संभ्या एक. ८-५/८०, पी.एन.-१ दिनांक १४ नवम्बर, १९८०, में एक. ४३-२४/८२-आई.एन.सी. (यू.यू.) (ए.यू.आर.) दिनांक १८ मई, १९८३, में एक. ४३/२४/८२-आई.एन.सी. (ए.यू.आर.) (यू.यू.) दिनांक ३ नवम्बर, १९८३ तथा में एक. ४३-२४/८२-आई.एन.सी. (ए.यू.आर.) (यू.यू.) दिनांक ३१ अक्टूबर, १९८४ और भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (जिका विभाग) के आदेश संभ्या एक. ४३-२४/८२-आई.एन.सी. (ए.यू.आर.) (यू.यू.) दिनांक २४ जनवरी, १९८६ के क्रम में केन्द्रीय सरकार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्यायमूर्ति एन.पी. निगम की उक्त अधिनियम के प्रयोगन के लिये प्रशासक के रूप में नियुक्ति की अवधि को ९ नवम्बर, १९८७ तक बढ़ाती है।

[में.एक. ४३-२४/८२-आई.एन.सी. (ए.यू.आर.) (यू.यू.)]

मन्त्रीवर महाजन, निदेशक

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Education)

New Delhi, the 7th November, 1986

ORDER

S.O. 3875.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 5 of the Auroville (Emergency Provisions) Act, 1980 (59 of 1980) and in continuation of the orders of the Central Government in the Ministry of Education and Culture (Department of Education) No. F. 8-5/80-PN-1, dated the 14th November, 1980, No. F. 43-24/82-INC(UU)(AUR), dated the 18th May, 1983, No. F. 43-24/82-INC(AUR)|UU, dated the 3rd November, 1983, No. F. 43-24/82-INC(AUR)|UU, dated the 31st October, 1984 and the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Education) Order No. F. 43-24/82-INC(AUR)|UU, dated the 24th January, 1986, the Central Government hereby extends the term of appointment of Justice L. P. Nigam, retired Judge of the Allahabad High Court as the Administrator for the purpose of the said Act up to the 9th November, 1987.

[No. F. 43-24/82-INC(AUR)|UU]
BALDEV MAHAJAN, Director

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, ३ नवम्बर, १९८६

का. आ. ३८७६.—बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, १९७६ (१९७६ का ६३) के अंडे ७ के उप अंडे (१) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री रमेश चाहू, भागीरथ लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा की वित्त सलाहकार, बेतवा नदी बोर्ड, भांसी के रूप में प्रतिनियुक्त की अवधि ३० जून, १९८६ में ३१-७-८६ तक की और प्रवधि के लिये एतत्वाग्र बढ़ाती है।

[में. १०/४७/८५-परि. सी.]
के.के. टाइट, अधर निवार

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 3rd November, 1986

S.O. 3876.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of the Section 7 of the Betwa River Board Act, 1976 (63 of 1976), the Central Government hereby further extends the period of deputation of Shri Ramesh Chandra, JA&AS as Financial Adviser, Betwa River Board, Jhansi for a further period with effect from 30th June, 1986 upto 31-7-86.

[No. 10/47/85-P. III]

K. K. TANDON, Under Secy.

शहरी विकास भंगालय

नई दिल्ली, २८ अक्टूबर, १९८६

का. आ. ३८७७.—यस: केन्द्रीय सरकार का नीचे लिखे क्षेत्रों के बारे में दिल्ली की बृहत योजना में कलिप्य संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ (१९५७ का ६१) की धारा ४४ के उपबन्धों के अनुसार दिनांक १९-९-८६ को नोटिस संभ्या एक-२०(६)/८४-एम पी, के साथ प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से ३० दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा ११-क की उपधारा (३) में अपेक्षित आपत्तियों/मुक्ताव मार्गे गए थे।

और यह: उक्त संशोधन के बारे में कोई आपत्ति/मुक्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा ११-क की उपधारा (२) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा दिल्ली की बृहत योजना में भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः—

संशोधन :—“जौन-डी-३ के अन्तर्गत आने वाले लगभग २६४८.१८ वर्ग गज क्षेत्रफल का भूमि उपयोग” सरकारी और अधिसरकारी सुविधाओं (“धोबी घाट और विद्युत सबस्टेशन स्थल”) और “परिचालन” से “सरकारी उपयोग” (वकीलों का चैम्बर) में बदला जाता है, जो उसर की ओर गैक्षणिक संस्था (विधि संस्थान), दक्षिण और पूर्व की ओर रिहायशी (सरकारी वंगले) और पश्चिम की ओर सार्वजनिक उपयोगिता (विधि त सबस्टेशन) से विरा है।

[में. के-१३०११/१८/८४-डी डी-IIए]

एच. के. धोष, डैस्ट्रिक्ट अधिकारी

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 28th October, 1986

S.O. 3877.—Whereas certain modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan

for Delhi regarding the areas mentioned hereunder, were published with Notice No. F. 20(6)/84-MP dated 19-9-86 in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions, as required by sub-section (3) of section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice;

And whereas no objections or suggestions have been received with regard to the aforesaid modifications;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India, Namely :—

MODIFICATION :

"The land use of an area measuring about 2648.18 sq. yds. falling in Zone D-3 and bounded by Educational Institution (Law Institute) towards its North, residential (Government Bungalows) towards South and East and Public utility (Electric Sub Station) towards West is changed from Public and Semi Public facilities (Dhobi Ghat and Electric Sub Station Sites) and Circulation 'to' Governmental use" (Lawyers' Chamber)."

[No. K-13011/18/84-DDHA]

H. K. GHOSH, Desl. Officer

(निर्माण प्रभाग—निर्माण-3)

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर 1986

का.पा. 3878.—यतः राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 (1951 का 41) की धारा-4 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसरण में, श्री आर० के० नारायण, संसद सदस्य को श्री खुशवन्न सिंह, संसद सदस्य के स्थान पर राजघाट समाधि समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व निर्माणी और आवास मंत्रालय के दिनांक 25 जून, 1985 के का० प्रा० सं० 3793 में जारी अधिसूचना में एतदद्वारा निम्नलिखित भंशोधन करती है, अर्थात् :—

उपर्युक्त अधिसूचना में, का० सं० 10 पर प्रविष्ट "श्री खुशवन्न सिंह" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"श्री आर के नारायण, संसद सदस्य,"

[फाइल सं० 25011/7/85—निर्माण-3]

डी० एन० भार्व, निदेशक (डब्ल्यू०पी०)

(Works Division—W.3)

New Delhi, the 30th October, 1986

S.O. 3878.—Whereas in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of section 4 of the Rajghat Samadhi Act, 1951 (41 of 1951), Shri R. K. Narayan, Member of Parliament, has been elected as Member of the Rajghat Samadhi Committee vice Shri Kushwant Singh, Member of Parliament, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Works and Housing number S.O. 3793 dated the 25th June, 1985 namely :

"In the said notification, against serial No. 10, for the entry "Shri Kushwant Singh", the following shall be substituted, namely :—

"Shri R. K. Narayan, M.P."

[F. No. 25011/7/85-W.3]

D. N. BHARGAVA, Director (WP)

परिवहन मंत्रालय

(नागर विमानन विभाग)

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 1986

का.पा. 3879 :—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (प्राप्तिकृत अधिभोगियों की वेदव्वरी) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 17 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के भूतपूर्व पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना सं० एवी-24023/2/85-एए (एफ०२) तारीख 23 जुलाई, 1985 को अधिकांत करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) की सत्स्थानी प्रविष्टि में विनिदिष्ट अपनी अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे।

सारणी

अधिकारी का पदनाम

अधिकारिता की स्थानीय
मीमांसा

1. उप कलक्टर, (अधिकमण)	निम्नलिखित स्थानों में कुर्ला-II टोपी बाला कालेज, मुंबई, मुंबई।	केन्द्रीय सरकार की भूमि- वाई "कैर्ड" तालुक अंद्रेरी और कुर्ला
2. उप कलक्टर, (अधिकमण)	वाई "एल" तालुक कुर्ला कुर्ला-3 भवन सं० 6 सिध्धी कैम्प के निकट नवजीवन सोसाइटी चेम्बूर, मुंबई।	वाई "एल" तालुक कुर्ला अंद्रेरी बौद्रा एल एच भवन मुंबई।
3. उप कलक्टर (अधिकमण), वाई "एच ई" तालुक अंद्रेरी अंद्रेरी बौद्रा एल एच भवन		

[सं. एवी-24023/2/84-एए (फा. 2)]

ए०एम० सहगल, विनियंत्रक

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Civil Aviation)

New Delhi, the 23rd October, 1986

S.O. 3879.—In exercise of the powers conferred section 3 read with section 17 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971, (40 of 1971) and in supersession of the notification of the Government of India in the then Ministry of Tourism and Civil—Aviation No. AV. 24023/2/84-AA (F. II), dated the 23rd July, 1985, the Central Government hereby appoints the officers of the Government of Maharashtra mentioned in column (1) of the Table below, being gazetted officers of Government, who shall

exercises the powers conferred and perform the duties imposed on estate officers by or under the said Act within the local limits of their respective jurisdiction specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table:—

Table

Designation of Officers	Local limits of jurisdiction	
	(1)	(2)
Land belonging to the Central Government in—		
1. Deputy Collector, (Encroachments), Kurla—II, Topiwala College, Mulund, Bombay.	WARD 'KE', TALUKA ANDHERI AND KURLA	
2. Deputy Collector, (Encroachments), Kurla—III, Building No. 6, Sindhi Camp near Nav Jeevan society, Chembur, Bombay.	WARD 'L', TALUKA KURLA	
3. Deputy Collector, (Encroachments), Andheri Bandra, MH Building, Bombay.	WARD 'HE', TALUKA AND HERI	
[No. AV.24/023/2/84—AA (P. II)]		
A.M. SEHGAL, Financial Controller.		

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1986

का. आ. 3880:—राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (2) और (4) के अनुसरण में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) पश्चिम रेलवे के क्षत्रीय प्रशिक्षण स्कूल, उदयपुर को जहां के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करता है।

[सं० हिन्दी-86/रा०भा० 1/12/3]

ए० एन० वांचू, सचिव, रेलवे बोर्ड एवं
भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 4th November, 1986

S.O. 3880.—In pursuance of Sub-Rule (2) & (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for the Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Ministry of Railways, Railway Board hereby notify the Zonal Training School, Udaipur of Western Railway, where the staff have acquired the working knowledge of Hindi.

[No. Hindi-86/OL-I/12/3]

A. N. WANCHOO, Secy, Railway Board & Ex-Officio
Joint Secretary to the Govt. of India.

धूरसंचार मंत्रालय

(धूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1986

का. आ. 3881:—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खंड 3 के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, धूरसंचार विभाग ने वल्लम, कुरुगलम, नाडू कावेरी, मेलाथिरुपन्त्युरुथी तथा कल्लापेरम्बूर टलीफोन केन्द्र तमिलनाडू सकिल, में दिनांक 16-11-1986 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-26/86-पी एवं बी]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 28th October, 1986

S.O. 3881.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specified 16-11-1986 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Vallam, Kurungulam, Naducauvery, Melathirupanthuruthi and Kallaperambur Telephone Exchanges, Tamil Nadu Circle.

[No. 5-26/86-PHB]

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1986

का. आ. 3882:—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम, 434 के खंड 3 के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, धूरसंचार विभाग ने एम पुडपट्टी, थाईलपट्टी कावोवडमपट्टो, नांगुनेरि, कलकाडू, मूल करैपट्टी तथा पांगांकुल टलीफोन केन्द्र, तमिलनाडू सकिल, में दिनांक 16-11-1986 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-33/86-पी एवं बी]

के. पी. शर्मा, सहायक महानिदेशक, (पी एवं बी)

New Delhi, the 29th October, 1986

S.O. 3882.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specified 16-11-1986 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in M. Pudupattu, Thayilpatti, Kakividampatti, Nanguneri, Kalakad, Moolakaraiapatti and Panankulam Telephone Exchanges, Tamil Nadu Telecom. Circle

[No. 5-33/86-PHB]

K. P. SHARMA, Asst. Director General (PHB)

(दूरसंचार बोर्ड)

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1986

आ. 3883.—जबकि सारीय तार नियम, 1951 के नियम 434 (iii) (2सी) के अनुसार कर्वी चित्रकूट टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र में संशोधन करने के लिए कर्वी चित्रकूट में परिचालित समाचार पत्रों में एक सरकारी नोटिस प्रकाशित कराया गया था, जिसमें उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर आपत्तियां और सुशाष मार्गे गए थे;

और जबकि यह नोटिस 15-3-86 को नार्वें हॉटिल्या पत्रिका और दैनिक जागरण में तथा 17-3-86 को दैनिक कर्मपुण प्रकाश में प्रकाशित करके तथा 29-7-86 को नार्वें हॉटिल्या पत्रिका में और 30-7-86 को दैनिक जागरण समाचार पत्रों में संशोधन प्रकाशित कराके जनता के ध्यान में लाया गया था;

और जबकि जनता से उपर्युक्त नोटिस के बारे में कोई आपत्ति और सुशाष ग्राह्य नहीं होती है;

इसलिए, अब उक्त नियमावली के नियम 439 (iii) (2 सी) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग तरसे हुए, महानिवेशक, दूरसंचार विभाग एवं द्वारा घोषित करते हैं कि 16-11-1986 से कर्वी चित्रकूट का स्थानीय क्षेत्र निम्नानुसार होगा;

कर्वी चित्रकूट टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली

कर्वी चित्रकूट टेलीफोन प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र में चित्रकूट धाम कर्वी नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में आगे बढ़ाया जायेगा;

याते हैं कि चित्रकूट धाम कर्वी नगरपालिका सीमा से बाहर के टेलीफोन उपभोक्ता जिन्हें कर्वी चित्रकूट टेलीफोन प्रणाली से सेवा मिलती है, तब तक स्थानीय शूलक देते रहेंगे जब तक वे इस प्रणाली के किसी एक्सचेंज के 5 कि. मी. के अन्दर आते हैं और इससे जुड़े रहते हैं।

[स. 3-7/85-पी.एच.बी.]

जे. के. आबड़ा, निवेशक फोन (ई)

(TELECOM BOARD)

New Delhi, the 7th November, 1986

S.O. 3883.—Whereas a public notice for revising the local area of Karvi-Chitrakoot Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III) (2c) of the Indian Telegraphs Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Karvi-Chitrakoot, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers;

And whereas the said notice was made available to the publication on 15-3-1986 in 'Northern Indian Patrika' and 'Dainik Jagran' and on 17-3-1986 in Dainik Karamyug Parkash, and corrigendum published on 29-7-1986 in Northern India Patrika and 30-7-1986 in Dainik Jagran Newspapers;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434 (III) (2c) of the said Rules, the Director General Department of Telecommunications hereby declares that with effect from 16-11-1986, the revised local area of Karvi-Chitrakoot shall be as under :

KARVI-CHITRAKOOT Telephone Exchange System :—

The local area of Karvi-Chitrakoot telephone system shall cover an area following under the jurisdiction of Chitrakoot Dham Karvi Nagarpalika ;

Provided that the telephone subscribers located outside the Chitrakoot Dham Karvi Nagarpalika limits but who are served from Karvi-Chitrakoot Telephone System will continue to pay local tariffs as long as they are located within 5 Kms of any exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-7/85-PHB]

J. K. CHHABRA, Director Phones(E).

भ्रम शंशालय

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर 1986

का.प्रा. 3884.—श्रीद्वयिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसार में, केन्द्रीय सरकार नार्वें रेलवे, लखनऊ के प्रबन्धनताव से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के भी अनुबन्ध में लिखित श्रीद्वयिक विवाद में केन्द्रीय सरकार श्रीद्वयिक अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-10-86 को प्राप्त हुआ था।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 24th October, 1986

S.O. 3884.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Northern Railway, Lucknow and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th October, 1986.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 45 of 1984

Reference No. L-41012/22/83-D. II(B) dt. 14-5-1985

In the matter of dispute between :

Shri Uma Shanker,

C/o Shri B. D. Tewari, 96/196 Roshan Bajaj,
Lane Ganesh Ganj, Lucknow.

AND

Senior Civil Engineer/Construction,
Northern Railway.

Lucknow

APPEARANCE :

Shri B. D. Tewari—for the workman.

Shri K. C. Jauhari—for the Management.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-41012/22/83-D. II(B) dt. 14-5-1985, has referred the following dispute for adjudication to this tribunal;

Whether the action of the management of Northern Railway, in relation to their Senior Civil Engineer Construction, Lucknow in not providing employment to Shri Umu Shanker Chowkidar w.e.f. 17-3-1982 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?

2. The case of the workman is that he was initially appointed as casual labour on 15-2-76 and worked till 16-3-82 and in this way had completed 1585 days of work during this span and he completed more than 280 days of work in several span. The workman was first of all illegally retrenched by PWI construction 2-3-81. The union raised objection and raised industrial dispute and in the earlier proceedings Sr. Civil Engineer (Const) agreed to take back workman on duty he was consequently taken back on duty on 15-9-81. The workman was not paid authorise scale of pay on which he again raised dispute before this honourable court on which the senior civil engineer construction and PWI Shri GS Bhatt fell enraged and terminated the services of the workman w.e.f. 17-3-82. It is averred that though his termination took place on 17-3-82 his services were terminated earlier on 15-3-82 and he was reappointed as gaongman at Roja station on the same day i.e. 15-3-82 on the name of transfer from Lucknow to Roza knowing full well that casual workman are not liable for transfer, however, the workman continued to work at Lucknow on 15-3-82 and 16-3-82 and from 17-3-82 he was shunted out without any prior notice, notice pay or retrenchment compensation. He consequently be entitled to be reinstated with full back wages.

3. The management in its written statement took plea that the workman was never transferred to Roza but being work charged staff he was charged in the yard remodelling work of Roza with head quarters at Roza under the jurisdiction of Senior Civil Engineer Construction Northern Railway, Lucknow and also under the jurisdiction of P.W.I. The workman was never transferred but on completion of other works/handing over of the work to other incumbent the employee was charged against other sanction and shifted to other work charge sanction alongwith other staff for executing the work. It is further averred that the workman was never retrenched but absconded from duty from Roza w.e.f. 17-3-82 and never presented himself for employment. Information by P.W.I. vide letter dt. 27-4-82 was given. The management by way of written statement made para-wise reply and averred that if on 25-1-81 the workman was retrenched but he left on his own accord and left the store materials unattended at his place of duty and according to Railway Board circular dt. 8-6-81 a casual labour ceases to be on the roll if he remains on unauthorised leave for more than 3 days. After conciliation before ALC, the workman was given fresh appointment on 15-9-81 as labour to work on workcharged employee on post created for completion of any work, so workman can not claim any right. The management reiterated the stand that the management ever terminated the services of the workman w.e.f. 17-3-82, but he absconded from duty from Roza w.e.f. 17-3-82 but despite information he never returned for duty. That he was never terminated but on completion of their work and handing over the work to other incumbents the employee was charged against other sanction and shifted to other work charge sanction alongwith other staff for executing the work. In the end it is averred that at no stage of time the employee was retrenched but the employee himself absconded

from duty of his own accord, unauthorisedly and without informing the railway official and left the stores unwatched at the place of his duty. It is averred in the same sequence that it was his legal and nominal duty of watching the railway property in his charge before leaving his service and that the workman being project casual labour is not entitled to benefits of next below rule.

4. In the rejoinder it is averred on behalf of the workman that the workman was paid at Lucknow as Chowkidar upto 17-3-82 whereas the record shows that he was retained at Lucknow by employer.

5. In support of its contention the management has filed the letter of the Senior Accounts Officer (Const.) dated 8-3-83 testifying that the workman was paid for the period 15-3-82 to 16-3-82 vide pay sheet submitted by under VR No. 372 on 20-4-82 in presence of Shri G. S. Bhatt PWI construction (ii) Lucknow. The next documents filed is registration slip no. 1013 showing that a letter was sent to Umu Shanker workman, paper no. 3, is the letter of Sunder Lal Mate under his thumb impression intimating the PWI (ii) Lucknow informing that the workman attended duty on 15th and 16th and left for Lucknow by Siyaldah Express informing that he would not work at Roza, hence he is marking the workman absent from 17-3-82, 4th document is letter of PWI dt. 26-4-82 intimating the workman that he had approached him with the letter of Asst. Engg. Construction dt. 22-4-82 in which he was asked to employ the workman in project no. 116 for which work he did not come forward hence he was asked to contact him within a week else PWI would be helpless for want of vacancy. It appears that this letter was sent by registered post. The management has further filed letter addressed to Shri Bhatt to appoint him and Shri Umu Shanker was directed to go to project no. 116 on 22-4-82. The management has filed letter of management dated 10-3-82 whereby he has requested that he absent from duty to 26-1-81 to 12-2-81 on medical hence he be given scale rate of pay. The management has filed mustur-cum-pay sheet showing that the workman was present on 15th and 16th March, 1982 and was absent thereafter and in the end it is endorsed as left. The next document is the photo copy of the telegram showing that the workman was working as Chowkidar at STU had left store unattended from 2-3-81. The management has filed the service sheet showing that the workman had worked as chokidar from 15-10-80 to 14-3-81 in broken period and his scale rate was discontinued from 26-1-1981.

6. In support of its contention, the management has examined 2 witnesses namely Shri G. S. Bhatt as M.W. 1 and in his affidavit has deposed about unauthorised leave from 25-1-1981 leaving the stores materials unwatched and without informing the railway authorities as a result of which he ceased to be on rolls after three days and he was given fresh appointment on 15-9-81, that he being a project casual labour was never authorised to scale of pay similarly he was never retrenched from 17-3-82 but he absconded from duty from Roza despite information by registered post on 17-4-82. He further averred therein that the workman was transferred to Roza but being a work charged staff he was charged for yard remodelling work at Roza with Head Quarters at Lucknow, and under the jurisdiction of the Civil Engineer Construction Lucknow,

7. In cross examination he admits that the workman was not transferred to Roza on 15 or 16-3-82. He further admits pay slip ext. W.1 dated 17-4-82 which shows that the workman was chowkidar and his wage period was from 15-3-82 to 14-4-82 and that for two days he was paid Rs. 14 at the rate of Rs. 7 per day. The witness however, states that designation chowkidar is written wrongly in ext. W-1 but admits that payment was made at Lucknow. He admits that Umashanker had obtained card pass from his office for going to Roza as Gangman, he further admitted that card pass register could be filed in court, it may be mentioned here that the management never filed any document to show that the workman under his signature obtained card pass for attending duty at Roza as gangman. He admits that the workman was made gangman from chowkidar on 14-3-82 when sanction of the post of chowkidar was expired and the post was transferred under P.W.I. Shri G. P. Singh where the workman refused to work. The management has failed to show that the sanction of the post of chowkidar was expired on 14-3-82 and it was on that account that he was transferred to Roza from 15-3-82 and exhibit W-1 shows that the post of chowkidar continued for the period 15-3-82 to 14-4-82 for which period he was paid for two days work at Lucknow on 17-4-82, before the witness i.e. after expiry of period of chowkidar, if the workman was not entitled to his two day pay between 15-3-82 to 14-4-82 on the post of chowkidar the management witness should not have signed it. From the fact that he has signed the document and in the absence of the document to show the post on which the workman was working earlier expired on 14-3-82 lend support to this contention that the post of chowkidar continued for the period 15-3-82 to 14-4-82 and it was two days work during this period possibly on 15-3-82 and 16-3-82 for which the workman was paid on 17-4-82. The management's own document paper no. 1 shows that the workman was paid for 15-3-82 and 16-3-82 in the presence of Shri G. S. Bhatt P.W.I. (1) Lucknow. This document falsifies the suggestion of Shri G. S. Bhatt in cross examination when he deposes that Ext. W-1 does not disclose for what two days he worked for which he got payments.

8. Management's another witness M.W.-2 is Mate Shri Sunder Lal. He deposed that in March, 1982 workman was working in his gang under his supervision at Roza and that he worked for two days i.e. 15-3-82 and 16-3-82 and absconded from duty w.e.f. 17-3-82 and he accordingly informed the PWI (II) about it. In his cross examination he admits that he was illiterate. He admits that one beldar under him was literate and he used to write names, according to him Umashanker workman was present on 15th and 16th March, 1982 and workman was in store and was not digging earth for earth work. He further states that workman has not brought with him any letter of PWI when he met him for duty. He further admits that prior to that workman was not working with him. He further admits that Shri Bhatt did not visit Roza on 15th and 16th March, 1982 but had verbally told him on 14th March, 1982 that the workman may be taken on duty while he was leaving Roza for Lucknow. He further stated that the workman had gone Roza on 14th by some night train but later resiled and stated that he did not know by which train the workman had reached at Roza. It is strange that the workman was taken on duty by Sunder Lal on the verb 1 instruction of Mr. Bhatt at Lucknow, in the absence of any document to show that project work commenced at Roza from 15th March and the workman was working at

store camp and card pass by management was issued to him under these circumstances I am not inclined to believe this witness and it appears that the paper no. 8 filed by the management was prepared later on the instructions of the PWI. Admittedly all this is in English and must have been prepared by some one else other than Sunderlal.

9. On behalf of workman two witness have been examined out of which WW1 is workman himself and in his affidavit he has reiterated the case set out in the claim statement. He had given two affidavit one is dated 13-12-84 and the other is dated 8-8-85 and in the earlier affidavit he simply reiterated the stand taken in the claim statement and in the next affidavit dated 8-8-85 is regarding submission of medical certificate dated 15th and 16th March, 1982 showing that the said document is genuine. The certificate is dated 14-5-85 issued by Dr. SZHR Baraha on 14-5-85 showing that the workman was suffering from Dyria from 15 to 16th March, 1982 and was advised treatment and rest for two days. He too has been examined as WW. 2 Workman in his cross examination has deposed that despite his illness he attended duty and obtained medical certificate later. He deposed that he was chowkidar of PWI G. S. Bhatt and the work of Shri Bhatt was doing in Lucknow as well as at Roza on those days. He has denied the management's suggestion that Shri Bhatt P.W.I. had no work at Lucknow on 15th and 16th March, 1982 and no material was lying at Lucknow at that time. He has emphasised that he had line sleepers at Lucknow which were given under his supervision at Lucknow it may be during that line sleepers were given to him as Shri Bhatt PWI was instructed with the work of remodelling of yard for additional facility at Roza. The workman has deposed that all that was kept under tent in the camp office.

10. Dr. Zahiruddin M.W. 2 has proved his certificate WW2 in cross examination he admits that he had a register for issuing certificate which he has not with him at the time of deposition and he has not noted any reference number in his certificate. He however, stated that while suffering from Dyria one can work. His evidence in the absence of treatment register certificate issuing register and particularly the fact that certificate was issued about 3 years later in May, 85 about treatment in March, 1982 does not inspire confidence. I fail to understand why this certificate at all obtained and the witness examined when admittedly he worked on 15th and 16th March, 1982 and thus I am not inclined to believe him on the point that the workman was at Lucknow on those days if purpose of his deposition is that but I am inclined to believe the workman on this point which emerges from Ext. W-1 that he was chowkidar for the period 15-3-82 to 14-4-82 and that he was paid at Lucknow before Shri G. S. Bhatt on 17-4-84. It appears that payments for two days was made to the workman on the instructions of Shri G. S. Bhatt, P.W.I. when he was making efforts for being taken on employment and it was on this count that soon after on 26-4-82 P.W.I. (II) wrote to the workman that on the instruction of Assistant Engineer Construction he was required to attend project no. 116 but he did not go for duty. The management's letter dated 19-4-82 addressed to Shri G. S. Bhatt shows that the workman was directed to go on 24-4-82 to project no. 116. In these circumstances, and for the reasons discussed above I am inclined to believe that the workman was cease to work from his chowkidar duty w.e.f. 17-3-82 whereas he was required to work for the period 15-3-81 to 14-4-82. The workman was issued service certificate by the CSE Northern Railway showing that the workman worked either as chowkidar or gangman from 15-12-76 to 16-3-82 in broken period and in one span or year counting back word from 16-3-82 he worked for 183 days. The management has not filed any document to show that the workman was working on project despite averments in the written statement to that effect on 3-7-86

management moved an application filing two documents alleging that the management had taken plea from the very beginning that the workman was daily rated casual labour on project for remodelling of yard for providing additional facility at Roza. He has filed true copy of the sanction of the abstract works programme 1979-80 of item no. 372. The paper filed by the management shows that item no. 372 was regarding remodelling of yard for additional facility at Roza, the payment record filed by the management shows that pay sheet was submitted as no. 372, the payment receipt ext. W.1 filed by the workman suggests that one period was for the period 15-3-82 to 14-4-82 and according to workman rails were put in his charge at Lucknow for watching as chowkidar. All this suggests that the workman was employed on project no. 372 which work was to continue from 15-3-82 to 14-4-82 and that after working for two days i.e. 15-3-82 and 16-3-82 the workman was ceased to work without any justifying cause.

In its application management stated that the workman absconded from duty consequently not providing him work from 17-3-82 as chowkidar was not justified. The result is that the workman will be reinstated on the said post from 17-3-82 with full back wages.

I, therefore, hold that the action of the management of Northern Railway in relation to their Senior Civil Engineer (Construction), Lucknow in not providing employment to Shri Uma Shanker Chowkidar w.e.f. 17-3-1982 is not justified. The result is that he will be reinstated on the said post with effect from 17-3-82 with full back wages.

I, therefore, give my award accordingly.

Let six copies of this award be sent to the government for its publication.

Dated : 3-10-86.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer
[No. L-41012/22/83-D.II(B)]
HARI SINGH, Desk Officer

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1986

का. आ. 3885.—केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 के उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली में सम्बद्ध नियोजकों और उसके कर्मकारों, जिनका प्रतिनिधित्व जनरल सेकेटरी, सी. पी. डब्ल्यू. डी. मजदूर यूनियन, नई दिल्ली, करती है के बीच हुए माध्यस्थम करार को अम मंत्रालय के दिनांक 31 अक्टूबर, 1986 के आदेश संख्या 42013/1/86-डी-2(बी) के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त संदर्भ में उल्लिखित व्यक्ति प्रतीक पक्ष के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3क) के अनुसार में एतदुनारा उन नियोजकों और कर्मकारों की जानकारी के लिये सचिना देती है कि जो माध्यस्थम करार के पक्षाकार नहीं हैं, लेकिन उक्त विवाद में संवैति हैं, उन्हें अपने मामले उक्त माध्यस्थम के समर्थन करते का अवसर दिया जायेगा।

[म. एल.-42013/1/86-डी.-2(बी)]

New Delhi, the 7th November, 1986

S.O. 3885.—Whereas in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government has published the arbitration agreement between the employers in relation to C.P.W.D. Nirman Bhawan, New Delhi and its workmen represented by the General Secretary, C.P.W.D. Mazdoor Union, New Delhi in the Gazette of India vide Ministry of Labour Order No. L-42013/1/86-D.II(B) dated 31 October, 1986.

And, whereas, the Central Government is satisfied that the persons in the reference represent the majority of each party:

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3A) of Section 10A of the said Act, the Central Government hereby notify for the information of the employers and workmen who are not parties to the arbitration agreement but are concerned in the dispute that they shall be given an opportunity of presenting their case before the Arbitrators.

[No. 1-42013/1/86-D.II(B)]

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1986

आदेश

का. आ. 3886.—भारत सरकार में तत्कालीन अम तथा पुनर्वासि मंत्रालय (अम विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 2251 दिनांक 21 मई, 1983 द्वारा गठित अम न्यायालय, चंडीगढ़ के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में एक स्थान रिक्त हो गया है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबंधों के अनुसार में केन्द्रीय सरकार श्री एम. के. बंसल को 23 अक्टूबर, 1986 से उक्त अम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या ए-11016/1/86-सी.एल.टी.]

New Delhi, the 29th October, 1986

ORDERS

S.O. 3886.—Whereas a vacancy has occurred in the Office of the Presiding Officer of the Labour Court, Chandigarh constituted by the notification of the Government of India in the then Ministry of Labour & Rehabilitation (Department of Labour) No. S. O. 2251 dated the 21st May, 1983.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri M. K. Bansal, as the Presiding Officer of the said Labour Court with effect from 21st October, 1986.

[F. No. A-11016/1/86-C.I.T.]

का. आ. 3887.—भारत सरकार में तत्कालीन अम तथा पुनर्वासि मंत्रालय (अम विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 2252 दिनांक 21 मई, 1983 द्वारा गठित औद्योगिक अधिकरण, चंडीगढ़ के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में एक स्थान रिक्त हो गया है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबंधों के अनुसार में केन्द्रीय सरकार श्री एम. के. बंसल को 21 अक्टूबर, 1986 से उक्त औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या ए-11016/86-सी.एल.टी.]

प्रार. टी. पाण्डे, उप सचिव

S.O. 3887.—Whereas a vacancy has occurred in the Office of the Presiding Officer of the Industrial Tribunal, Chandigarh constituted by the notification of the Government of India in the then Ministry of Labour & Rehabilitation (Department of Labour) No. S. O. 2252 dated the 21st May, 1983.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri M. K. Bansal, as the Presiding Officer of the said Industrial Tribunal with effect from 21st October, 1986.

F. No. A-11016/1/86-C.L.T.]

R. T. PANDEY, Dy. Secy.

इद दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1986

का.आ. 3888.—ओद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की घरा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, मैसर्स सिंगरैनी कॉलरीज कं. लिमिटेड, कोठगुडम डिवीजन, पो. वेंकटेशखानी, जिला खम्माम (आन्ध्र प्रदेश) के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट ओद्योगिक विवाद में ओद्योगिक अधिकारण, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16-10-1986 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 29th October, 1986

S.O. 3888.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem Division, P. O. Venkateshkhani, Distt. Khammam (A.P.) and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th October, 1986.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL)
AT HYDERABAD.

Industrial Dispute No. 19 of 1984.

BETWEEN

The Workmen of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem Division, Khammam District (A.P.)

AND

The Management of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem Division, Khammam District.

APPEARANCES :

Shri D. S. R. Varma, Advocate for the Workmen.

Sarvastri K. Srinivasa Murthy, H. K. Saigal and Miss G. Sudha, Advocates for the Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour & Rehabilitation by its Order No. L-22011/117/83-D. III(B) dated 2nd March, 1984 referred the following dispute under Sections 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers in relation to the Management of Messrs Singareni Collieries Compay Limited, Kothagudem Division P.O. Venkateshkhani, District Kammam and their workmen to this Tribunal for adjudication :

"Whether the management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem are justified in not sending Sri Thalla Durgaiah, Scraper Khalasi, Sand Gathering Station for assessment of his age and retiring him on 31-1-1983. If not, to what relief is workman concerned entitled ?"

This reference was registered as Industrial Dispute No. 19 of 1984 and notices were issued to the parties.

2. The claims statement filed by the workman Thalla Durgaiah, Scraper Khalasi, Sand Gathering Station, appealed to the Management of Singareni Collieries Compay Limited, to confirm his age particulars as recorded in the Bonus Card wherein it was stated very clearly that his age was 25 years as on 14-12-1957, the photostat copy of the

same is enclosed also. According to him he has to retire during the year 1992 after attaining 60 years of age as per the Company Age Retirement Rules. But the Management stated he was sent to hospital during January 1973 for assessment of his age and his age was assessed by the Medical Board as 50 years as on 23-1-1973. In other words he has to retire on 23-1-1983 this aspect of the matter was brought to the notice of the Management by he affected party to send him to assess his age correctly. The Management should have sent up as per the Circular dated 6-7-1981 which is enclosed as Annexure 2. The Management normally should have sent Thalla Durgaiah for medical examination instead of retiring him on 31-1-1983. Thus the Management denied the natural justice and they did not give him fair opportunity to the workman in assessing his age according to Bonus card and other records of the Management. The Management should have corrected his age as per records provided by the workmen through Age Determination Committee/Medical Board by doing natural justice. Therefore when the same is not done and when they want to retire him on 23-1-1983 they requested that the same is illegal and to declare the same as not justified and grant him all the reliefs as prayed for.

3. The reference is received in this Tribunal on 7-3-1984 and the claims statement is filed on 21-4-1984. The Management filed its counter on 28-4-1984.

4. It is mentioned in the counter filed by the Management that it was a fact that Thalla Durgaiah, Scraper Khalasi, Sand Gathering Station was appointed in the Company on 31-3-1948. According to them as his age was not assessed at the time of his appointment he was sent for Medical Board on 23-1-1973 and the Medical Board by its letter dated 23/29-1-1973 has confirmed that Thalla Durgaiah was 50 years as on 23-1-1973. The Union claimed that Durgaiah was only 25 years as on 14-12-1957 as per Bonus Card is not correct because the bonus card does not stipulate the age of Thalla Durgaiah as 25 years as on 14-12-1957. The Bonus Card only speaks about the preparation for bonus card and not age of the worker as on that particular date. The Medical Board rightly after examining the worker confirmed the age of 50 years as on 23-1-1973. The Argument of the Union that Thalla Durgaiah was absent on 23-1-1973 at the time of age assessment before the Medical Board is false as the said Thalla Durgaiah was present and inscribed his thumb impression in the Medical Form before the Medical Board. The true copy of the age assessment by the Medical Board of which Thalla Durgaiah thumb impression has been inscribed is enclosed herewith. It is clearly indicated that Thalla Durgaiah did present before the Medical Board and accepted his age as 50 years on 23-1-1973. As such he cannot dispute the age after a lapse of 10 years and that too at the verge of his retirement. The Circular dated 6-7-1981 quoted by the Union does not stipulate anything to send the worker for age assessment when his age has been already assessed by the Medical Board. So there is no justification in the Union's demand of again referring Thalla Durgaiah to the Medical Board for his age assessment.

5. There afterwards after number of adjournments the Workman was examined on 25-6-1985. He was cross-examined also. According to W.W1 the original bonus card issued of him for which xerox copy is taken is marked as Ex. W1. He is an illiterate person. It is his case that he was 25 years old when bonus card was issued to him on 14-12-1957 and that he should retire at the age of 60 years. As per the bonus card Ex. W1 he should be in service till 1992. He denied that he was examined by the Medical expert at the instance of the Management on 23-1-1973. According to him they gave notice as per Ex. W2 on 7-11-1982 and he also relied upon the Circular dated 6-7-1981 to substantiate his case that he should have been referred to the Age Determination Board or Medical Board. He denied that the Union entered into an agreement with the Management in 1961, 1965 and 1969 and the Management sent those employees whose age was in dispute to the Medical Board for determining their age. He also denied that he approached the Management to decide his age correctly by referring to the Medical Expert and Dr. D. Anjeneyulu determined his age as 50 years on 23-1-1973 after examining him as per

Ex. M1. He denied that he put his thumb impression on Ex. M1. It is his case that he cannot identify his own thumb impression on the deposition as well as the document shown to him Ex. M1. The ten L.T.I.s was taken in the open Tribunal for the purpose of comparison and for the purpose of comparison and identification Ex. M2 is the L.T.I. sheet. He denied that his age was already determined as 50 years as on 23-1-1973 and therefore he need not be sent for medical examination for determining the age again. He denied under Ex. M3 and M4 that the Management followed the procedure required for determination of his age properly. He admitted that he had taken gratuity and Provident Fund after retirement.

6. Thereafterwards the Management took number of adjournments Prior to that even on 29-9-1985 the Management reported that the talks of compromise were going on. So 29-9-1985 to 25-11-1985, no settlement was reported and no evidence is adduced by the Management and finally a Memo was filed on 10-12-1985 stating that the talks of settlement are going on between the union and the Management as such the matter may be adjourned for another 20 days. On 15-1-1986 as no settlement or agreement is filed between the parties, the Tribunal posted for the evidence of the Management on 14-2-1986.

7. From 14-2-1986 the matter is adjourned to 24-3-1986, 1-4-1986, 30-5-1986, 1-8-1986, 25-8-1986, 10-9-1986 and 22-9-1986 and as there was no interest evidenced by the Management, the matter was decided on merits on the file and records and evidence as other side was opposing for granting of any adjournment stating that it is already delayed.

8. On 10-9-1986 the Management filed a Memo which is numbered as M.P. No. 310/86 stating that they filed petition in I.D. No. 41/85 on 3-9-1986 stating that they are not proceeding in the above matter as they are moving the application for transfer of this case from this Tribunal to another Tribunal as such it may be deferred. That Memo was rejected on 10-9-1986 stating that in view of the orders passed in M. P. No. 278/86 in I. D. No 41/85 on 4-9-1986 this Memo is rejected. By that time no Writ is filed as averred in their petition that they are moving the matter against I. D. No. 41/85 on 3-9-1986 and further there was no intimation also seeking adjournment in this case or further expressing their difficulties if any.

9. Even afterwards the Tribunal was considerate and adjourned the matter from 10-9-1986 to 22-9-1986 and finally as there was no representation on the available data material, the matter was proceeded with. Now the workers relied upon his date of birth that he was aged 25 years as per Ex. W1 which is a Bonus card given to him. Admittedly he is an illiterate markman working as Scraper Kbalasi since 1957. He denied having been examined by the Medical Board regarding the assessment of his age on 23-1-1983, by a Medical Board expert Dr. D. Anjaneyulu. He denied this Ex. M1. On the other hand he filed that he was asked to retire as per Ex. W2 on 31-1-1983 and that he had no knowledge of the other documents. He relied upon Annexure 2 of his claims statement which is marked as Circular dt. 6-7-1981 issued by the Management. It is mentioned that in Ex. M3 also to that effect. The procedure also mentioned regarding the determination of verification of age assessment. In the case of illiterates the date of birth will be determined by the Colliery Medical Officer keeping in view any documentary or other relevant documents as may be produced by the appointed and date of birth so determined should be treated as correct date of birth and the same will be altered under any circumstances. Whenever there is no variations in records such cases will not be reopened unless there is glaring and apparent entry brought to the notice of the Management. The Management after being satisfied on the merits of the case will take appropriate action for correction through Age Determination Committee/Medical Board. Now it is his case that he never approached before the Medical Board on 23-1-1973. He denied Ex. M1. Now when the workers denied Ex. M1 and also specifically stated that he knew Dr. D. Anjaneyulu but it is not correct that Dr. Anjaneyulu determined his age as 50 years on 23-1-1973 after examining him as per Ex. M1 and when Ex. M1 thumb impression is questioned, the Management failed to examine the Junior Engineer, Sand

Gathering Station who is alleged to have signed it to show that he said assessment of age to prove that he was present when Dr. D. Anjaneyulu examined. The thumb impression of the workman is disputed rightly by the workman as an illiterate person stating that he cannot identify his thumb impression. Now the Management took some samples of 10 L.T.I.s which was marked as Ex. M2 in this open Tribunal but still they were not bold enough to send them to the Finger expert or Thumb Impression Expert to connect the thumb impressions on Ex. M2 with Ex. M1 as they were done by the same Thalla Durgiah i.e. the worker involved. Having taken thumb impression on 25-6-1985 when the Worker was being examined; when no steps were taken for about more than a year and when they dragged the matter on the pretext of settlement stating that they are compromising an agreement with the workman and his Union and when they did not and could not come out with the said Settlement for more than a year and when they failed to examine their witnesses in support of Ex. M1, the Circulars under Exs. M3 and M4 come into effect. In other words when there is no verification of records such cases will not be reopened unless there is glaring and apparent wrong entry brought to the notice of the Management. In the instant case there is no record to show that the Management gave notice to him that there is glaring and apparent wrong entry under Ex. W1 and thus he was examined by the Medical Board as sought to be explained. When Ex. M1 is not proved according to law and Management witnesses could not come into witness box for more than 1-1/2 years and when Ex. M1 is denied by the witness stating that he was never examined on 23-1-1973 by Dr. D. Anjaneyulu whom he knew; when there is no other evidence to disbelieve him, it must be held that the argument of the Management that he was examined on 23-1-1973 under Ex. M1 is not true and correct. Ex. M1 is marked subject to proof and relevance in the said circumstances, if Ex. M1 goes as not proved document, the oral evidence read with Exs. M3, M4 coupled with Exs. W1 and W2 would show that the retirement of the workman on 31-1-1983 holding him that he completed 60 years of age is incorrect. Ex. W1 and oral evidence of workman which stand unrebutted would show that he is entitled as per Ex. M2 to be continued till 1992 and the management evidently took number of adjournments on the pretext of settlement and were talking for the best reasons known to themselves without even adducing oral evidence for more than 1-1/2 years. Moreover it need not be stressed as per I.D. Act the workers case should be disposed of in a stipulated time of three months from the date of reference if it is an individual case or within period of six months if it is a case involving more than one worker and looked from any angle this kind of delay without any explanation would only add to the misery of the worker who is involved in this reference while the Management is quite happy in dragging on for reasons best known to them, and it cannot be said that they should have been given further opportunity to prove their case.

10. Thus on a careful consideration I held that the action of the Management of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem is not justified in not sending Sri Thalla Durgiah, Scraper Khalasi, Sand Gathering Station without any proper assessment of age by the Medical Board or Age Determination Board from 31-1-1983. The said action is unjustified and therefore the workman is entitled to all the reliefs and he is deemed to be in service continuously from that date of his retirement during this period also with back wages and attendant benefits and he should be continued till 1992 in the given circumstances.

Award is passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him, corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 4th day of October, 1986.

Sd. (Illegible)
Industrial Tribunal

Appendix of Evidence.

Witnesses Examined

for the Workmen :

W W1 T. Durgiah

Witnesses Examined

for the Management :

NIL

Documents marked for the Workmen :

Ex. W1 Bonus Card pertains to T. Durgaiah.

Ex. W2 Letter dt. 7-11-82 addressed to T. Durgaiah by the Asst. Engineer, Aerial Ropeway & Sand gathering Station, S.C. Company Limited, Kothagudem with regard to retirement from company's service.

Documents marked for the Management :

Ex. M1 Letter dt. 27-12-72 addressed to T. Durgaiah by the Junior Engineer, Sand Gathering Station, S.C. Co. Ltd., Kothagudem with regard to assessment of age.

Ex. M2 Ten L.T. Is of T. Durgaiah.

Ex. M3 True copy of the Circular No. P49/3533/1981 dt. 6-7-81 issued by Chief General Manager, S.C. Co. Ltd., Kothagudem to all Pits and Departments all collieries with regard to procedure for determination/verification of the age of the employees.

Ex. M4 True copy of the procedure for determination/verification of age of the employees.

Dt. : 7-10-86

S. VENUGOPALA RAO, Industrial Tribunal
 [No. L-22011/117/83-D. III(B)]

गई विल्सी, 31 अक्टूबर, 1986

का.आ. 3889—मौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार, सिंगरेणी कोलीरीज के, लिमिटेड, मण्डपामारी, पो. कल्यानीखाणी, जिला-मूद्यवाला (भारत प्रदेश) के प्रबंधनताव से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में तिदिव्य मौद्योगिक विवाद में मौद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद (भारत प्रदेश) के पांचाट को प्रकाशित करती है, जो केंद्रीय सरकार को 16-10-1986 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 31st October, 1986

S.O. 3889.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad (AP) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited, Mandamarri, P.O. Kalvankhani District Adilabad (AP) and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th October, 1986.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL)
 AT HYDERABAD

Industrial Dispute No. 84 of 1984

BETWEEN

The Workmen of Singareni Collieries Company Limited,
 Mandamarri, Adilabad District.

AND

The Management of Singareni Collieries Company Limited,
 Mandamarri, Adilabad District.

APPEARANCES :

Sarvashri M. Pandu Ranga Rao and B. G. Ravinder Reddy, Advocate for the Workmen. Servarsi K. Srinivasa Murthy, H. K. Saigal, and Kumari G. Sudha, Advocate for the Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-22012/37 84-D. III(B) dated 20-11-1984 referred the following dispute under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employees in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited, Mandamarri and their workman to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Ramakrishnapur Division I in dismissing Shri G. Lakshminarayana, Tarex Loader Operator with effect from 2-6-1984 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

This reference was registered as Industrial Dispute No. 84 of 1984 and notices were issued to the parties.

2. The claims statement filed by the workman that the punishment is very heavy and disproportionate compared to the charge alleged and the order of dismissal is bad in law as the same is against the Standing Orders of the Company and that his right of appeal is denied as the orders are passed by the General Manager instead of Manager as per the Standing Orders.

3. Of course the Management filed a counter that G. Lakshminarayana was given full opportunity to defend in the domestic enquiry conducted on the 1st and on the basis of the allegations being proved, the dismissal order was served by the General Manager who is appropriate authority to issue dismissal orders. According to them the right of appeal to the Appellate Authority namely Executive Director/Chairman and Managing Director who is above General Manager is not dispensed with and therefore he should have any grievances for the same. It is also mentioned that the offence is a serious one and would have resulted in heavy damage to the Company property and the punishment awarded to him is not at all disproportionate.

4. The Management examined two witnesses, as M.W.1 and M.W.2 and marked Exs M1 to M9 and the Workmen examined one witness as W.W1 and marked Exs. W1.

5. When the Management filed a M. no to decide the preliminary point regarding the validity of the domestic enquiry, the said witness and evidence was adduced before this Tribunal by both parties and elaborate orders, on hearing both sides, was passed by me on 19-6-1986 holding that the domestic enquiry was conducted fairly and no illegality was committed by the Management and the principles of natural justice was fully observed and the enquiry was fair and proper. It is part of the record.

6. The afterwards the matter was adjourned to 11-7-1986. The matter went through number of adjournments from 11-7-1986 to 19-8-1986, and to 22-8-1986 and finally to 4-9-1986 when the Management filed a petition which is numbered as M.P. No. 283.86 stating that they filed a petition in I.D. No. 41 of 1985 dated 3-9-1985 in this Tribunal and they are not proceeding further in the above matter and they are moving an application for transfer of all their cases including this matter as stated in that petition in I.D. No. 41 of 1984 and as such hearing may be defereed. The workman counsel filed a counter stating that the allegations that the management cannot proceed with this case for the reasons stated in their petition in I.D. No. 41 of 1985 is unreasonable and unjustified and they are no way concerned with the said case and the management should have taken steps to engage another counsel if the counsel is not prepared to proceed with the case before the Tribunal and the workman cannot be put to irreparable delay tactics just because the counsel wanted not to proceed with the case in this Tribunal and counsel for the workmen stated that matter should be heard in the interests of the justice. On that the order was passed rejecting the same as both matters have no relevance as they are not connected also.

7. As per the charge sheet Sri G. Lakshminarayana Tarex Loader Operator who was engaged in first shift on 29-1-1984 to lift stock of coal at M.K. No. 4 Incline at about 11.30 a.m. was not found on Tarex Loader but in his place one

Chandragiri Rangaiah, General Mazdoor was found operating the Terax Loader for about $\frac{1}{2}$ hour and that this affected the lifting of coal and thus amounted to misconduct under Standing Order 16(18), (9) and (2). Now under Standing Order 16(18) leaving work without permission is a misconduct. Under Order 16(9) causing damage to work in progress or to the property of the Company amounts to misconduct, under Order 16(2) theft, fraud and dishonesty in connection with the Company business or property is also defined as misconduct. For these things it is said an employee may be suspended, fine or dismissed without notice or any compensation in lieu of notice if he is found to be guilty of misconduct. Now as per the evidence of M. W2 who is the Additional Chief Mining Engineer Bellampally that A. Prabhakar, Junior Engineer as Acting Manager C.S.P., Ramakrishnapur and Ex. M1 is the chargesheet issued by the Executive Engineer who is the head of the Department, Ramakrishnapur Division I and as per Ex. M5 the enquiry proceedings and the report Ex. M6, it is established that at the relevant time he was Terax Loader to lift stock of coal at M. K. No. 4 Incline. The explanation given by him is marked as Ex. M2. The workman stated that he worked till about 12 noon and that he left the place for taking tea and therefore the allegation that he was not present bodily is not correct. It is his case that about 12.30 noon Additional C. E. and D.E., RKP I came to the Loader and at that time he came in opposite direction and the Helper mazdoor who was with him was found operating Terax Loader as per them. He mentioned that the Helper Mazdoor did not know how to operate Terax loader and promised to know the exact facts. In the explanation it is his case that Additional C.E. and D.E., RKP I left the place and that he verified from Chandragiri Rangaiah that he did not operate the Loader and requested that the charge sheet should be withdrawn. He examined one witness by name Bhasker Rao in defence to support that the said Chandragiri Rangaiah, General Mazdoor who was attached to the Terax Loader and brought water and poured into the radiator and he was trying to stop running of the Terax Loader by pulling stop lever which is in the Loader cabin and when he was asked why he was in the cabin, told him to get down as the Additional C.E., and Senior D.E., RKP I came there and then Chandragiri Rangaiah got down from the Loader and within 10 minutes G. Lakshminarayana, Driver who was operating Terax Loader came there and had a discussions with the above Officers. In fact he asked in the cross examination by the management why he brought the lorry API 3550 if the Terax loader was not running for loading as it might likely to cause accident. The witness answered that he did not bring the lorry near to the Terax loader and the coal heap was in front of the loader. He was asked how much time he waited at the coal for loading the coal with his lorry, he mentioned that he waited for about 10 minutes. He was asked why he was present when the Terax loader was not present. He answered that he did not see it. He sat in the lorry cabin. He explained when engine is hot, water will not be poured in the radiator and while pouring water in the radiator he will keep engine running. In fact there was no question put to him to this defence witness Bhasker Rao by the Management witnesses to show that this Chandragiri Rangaiah was seen operating terax loader and that this Driver Bhasker Rao was not present when the Additional C.M.E. and Senior D.E. RKP came there. So it cannot be said that the evidence of M. Bhasker Rao can be brushed aside very lightly. He defended and explained that Chandragiri Rangaiah never operated this Terax Loader. The explanation of G. Lakshminarayana would also show that the engine worked for a long time and it was not. Hence after pouring water in the radiator the engine should be stopped and he asked master to get water from M.K. 4, Incline and to stop engine. So he did not take the ignition key as the mazdoor is working with Terax Loader permanently since one year. He asked the mazdoor to stop engine after pouring water in the radiator, and he also explained that when he left the Terax Loader he locked emergency brake and even that day he did the same. So the explanations of G. Lakshminarayana as well as the witness Bhasker Rao would show that the allegations as contemplated under Clauses 16(9) and 16(2) is not established because there is no proof of causing damage to the work in progress or to the property of the Company or any dishonesty in connection with the business of the Company or property that he left for 10 minutes for taking tea while the mazdoor was asked to pour water when the Terax Loader engine was hot as

defended by him and also supported by Bhasker Rao defence witness is not vindicated by any suspension and there is nothing in the cross examination done to them that Bhasker Rao was not present when the Additional C.M.E. and D.E., RKP I came there and he was not at all present and he was only a brought up witness. So Chandragiri Rangaiah is an accused General Mazdoor and he was therefor about one year and he was helping the Terax Loader. There is no evidence that something was lost or damaged except stating that the lifting of coal was affected which is not proved by any statistical data maintained by the management to show that there was no coal loading at all. There is no proof of dishonesty except alleging that there is "dishonesty" when he left for having tea. The three charges levelled against the workman are that Chandragiri Rangaiah was operating the Terax Loader. It is disputed by G. Lakshminarayana as well as his statement as supported by Bhasker Rao. Chandragiri Rangaiah is not examined by the Management to support their case. Surprisingly the said Chandragiri Rangaiah who was found operating was not given a charge sheet. If Chandragiri Rangaiah was found sitting in the cabin, it cannot be said as an offence on Terax loader alone under the Standing Orders. The delinquent case is that he was absent for 10 minutes and there is therefore no loss of loading stock of coal and even Junior Engineer who is examined in the domestic enquiry P.W3 mentioned that lorries could not come for loading and so there is no loss of loading of coal into the lorries. The third charge is about dishonesty. Even about dishonesty, there is no proof. Enquiry Officer could not make out any proof of dishonesty for the absence of 10 minutes or 30 minutes as the case may be simply because helper was sitting in the cabin and when there is any loss of production or damage to the machinery proved; without penalising the concerned workman or without examining the said Chandragiri Rangaiah who was the real delinquent equally responsible for such a mistake. When there is no proof that the said Chandragiri Rangaiah had done the operation of the Terax Loader at the instance of Lakshminarayana. It is surprising that the management thought fit to award the maximum punishment of dismissal to him having considered the entire facts and also the nature and the gravity of the offence when the evidence in relation to the matter is not satisfactory to hold that the same resulted in heavy damage to the Company property and the persons involved in the Company by the tangible evidence without any other bad record; I am of the opinion that it is a fit case where Section 11-A of the I.D. Act has to be given effect while considering on the punishment having been satisfied that the order of dismissal was not justified. Section 11-A is incorporated in the I. D. Act, 1947 to give power to the Tribunal in case wherever necessary to set the order of dismissal and direct reinstatement of the workman on such terms and conditions, if any as it deems fit or given to such a relief to the workman including award of lesser punishment as the circumstances may require. Now the material on record as produced before me do not show that there is any dishonesty proved so as to hold that there is misconduct. The evidence of G. Lakshminarayana who is the alleged delinquent as well as Bhasker Rao the lorry driver who was examined were not shattered that the Terax Loader engine got overheated and the labour was asked to pour water in the radiator and thus the expression misconduct as contemplated under Standing Order 16(2), 16(18) and 16(9) had no application, to show the improper behaviour of intentionally doing wrong or doing deliberate violation of rules or standing orders. For offences of trifling nature if works is to be charged holding such things would constitute an act of "misconduct" then it becomes that the Management can exercise an unbridled power and terminate every worker on some pretext or other for offences of trifling nature. The charge of misconduct, therefore, is the charge of some positive act or of conduct which would be quite incompatible with the express and implied terms of relationship of the employee to the employer. What is misconduct will naturally depend upon circumstances of each case. In the instant case it is not proved beyond reasonable doubt that deliberate disobedience of any orders of superior authority to hold it as misconduct. Further there is no proof of any loss to the employer. Further this so called misconduct must have direct connection with the commitment or comfort of the workman at work, even that is lacking. Moreover there is no material bearing on the smooth efficient working of the concern. Thus when there

is no proof that he is habitually avoiding work and entrusting to his helper and sitting idle and when there is no proof of loss of property and damage to any materials and when there is no proof of wilful insubordination or disobedience even such mistakes were pointed out or that he was in the habitual negligence doing neglect of work it cannot be misconduct. Even from the language of the Model Standing Orders it is clear that it does not define "misconduct" or "illust rate it exhaustively". Thus on a careful consideration of the entire matter I hold that it is a fit case where the dismissal order passed is quite disproportionate and very heavy compared with the charges alleged even if proved and therefore the order of dismissal is set aside. The period from the date of dismissal i. e. 2-6-1984 till this date of passing of the award is treated as a period without pay but the same will have to be treated as continuity of service and the person is directed to be reinstated from this date as on duty with wages as Texax Loader.

Award is passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him, corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 4th day of October, 1986.

Sd/-Illegible
INDUSTRIAL TRIBUNAL

Appendix of Evidence

Sd/- Illegible

Witnesses Examined
for the Management

M. W1 S. Janardhan Rao
M. W2 S. K. Garg

Documents marked for the Management

- Ex. M1 Charge Sheet dt. 1-2-1984 issued by Executive Engineer, CSP-RKP to G. Laxminarayana, Terax Loader Operator.
- Ex. M2 Explanation dt. 4-2-84 given by G. Laxminarayana to the Executive Engineer, CSP. R.K.P.
- Ex. M3 Enquiry Notice dt. 9-3-1984 issued by Executive Engineer CSP. RKP to G. Laxminarayana.
- Ex. M4 Enquiry Notice dt. 14-3-1984 issued by Executive Engineer CSP.. RKP to G. Laxminarayana.
- Ex. M5 Enquiry Proceedings Pertaining to G. Laxminarayana.
- Ex. M6 Enquiry Report pertaining to G. Laxminarayana.
- Ex. M7 True copy of the letter dt. 4-10-83 addressed by Addl. CME, RKP, I to all Pits & Departments with regard to S. Janardhan Rao, P.O. will conduct domestic enquiries in the Pits and Departments of RKP. I division with effect from 5-10-83 in place of R. Narasimha Reddy.
- Ex. M8 Letter dt. 13-3-84 addressed to the Director General of Mines Safety, Dhanbad, Eastern Rly. and to the Director of Mines Safety, Hyderabad Region, Hyderabad by the Additional Chief Mining Engineer Ramakrishnapur Division I with regard to A. Prabhakar Junior Engineer authorised to act as Manager, C.S. Plant, Ramakrishnapur from 13-3-84 till Yadagiri resumes duty who went on leave from 13-3-84 to 16-3-84.
- Ex. M9 Letter dt. 5-2-84 addressed by G.M. M.M. and RKP to M. Yadagiri with regard to privilege leave.

Documents marked for the Workmen :

Ex. W1 Dismissal Order dt. 1-6-1984 issued to G. Laxminarayana by the General Manager, M. M. & RKP.

Dated : 8-10-86.

[No. L-22012/37/84-D.III(B)]
J. VENUGOPALA RAO, Industrial Tribunal

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1986

का. आ. 3890 :—आद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, कोट्टौय सरकार, मै. सिंगरेणी कोलरीज कं. लिमिटेड, कोठागुडम, छिंदिजन, पो. वैकटेशरामानी, जिला कुम्मान (आंध्र प्रदेश) के प्रबंधतांत्र से स्थान नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट आद्योगिक विवाद में आद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो कोट्टौय सरकार को 16-10-1986 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 3rd November, 1986

S.O. 3890.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad (A.P) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem Division, P.O. Venkatesh Khani, District Khammam (A.P.) and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th October, 1986.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL)
AT HYDERABAD

Industrial Dispute No. 17 of 1984

BETWEEN

The Workmen of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem Division, Khammam District A.P.

AND

The Management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem Division, Khammam District, A.P.

APPEARANCES :

Sri D. S. R. Varma, Advocate—for the Workmen.
Sarvashri K. Srinivasa Murthy, H. K. Saigal and Kumari G. Sudha, Advocates—for the Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation by its Order No. L-22012(109)83-D III(B) dated 28-2-1984 referred the following dispute under Sections 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers in relation to the Management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem Division P.O. Venkatesh Khani District, Khammam A.P. and their Workmen to this Tribunal for adjudication :

"Whether the management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem were justified in not calling Shri Kudipudi Suryanarayana, acting as Munshi with effect from 28-7-1981 for selection to the post of Munshi on a regular basis, and not confirming him as Munshi. If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

This reference was registered as Industrial Dispute No. 17 of 1984 and notices were issued to the parties.

2. The claims statement filed by the workman, it is mentioned that he was working as Trammer, No. 5 Incline and he was not called for interview for selection of Munshi by the Management on the plea that he is not a senior candidate alongwith other eligible Trammers. According to him the Management did not fix any norms prior to the selection and there is no promotional policy for selection of Munshi and there was no such agreement or approved policy even by the Union. It is his case that as per the Company rules right from the date i.e. 28-7-1981 he is acting as Munshi and he was paid acting allowance as per the Company rules and the vacancies caused in 5 Incline due to medically unfit of a permanent Munshi by name Chitakabathula Narasiah. It is also his case that the Management after verifying amongst the other Trammers to do that job, but none are interested to act as Munshi nor they have called for acting Munshi post. So it is asserted that Kudupudi Suryanarayana is doing his job from 27-1-1981 onwards without having any adverse remarks and he should be confirmed as per the Company Standing Orders vide No. 2(1). As he was continuously working till the date of filing of this application to the satisfaction of his superiors. According to him when he claimed for confirmation the Management denied confirmation and they have conducted interview by calling the senior most Trammers in Category I by adopting promotional policy without having any conformity with Unions. Thus it is his case that as he was working continuously till 28-7-1981 he should be made permanent with retrospective effect as per principles of natural justice.

3. The reference was made to this Tribunal on 3-3-1984. The claims statement was filed by the Workman on 4-7-1984. The counter was filed by the Management on 22-12-1984 i.e. after 5½ months after filing of the claims statement.

4. In the counter filed it is stated that the petition is misconceived under the rules and Standing Orders. It is admitted that Sri K. Suryanarayana, Trammer working in 5 Incline was acting as Munshi in Grade III in the place of Sri C. Narasiah from 28-7-1981 as later has been declared medically unfit for further service. It was also true that he was being paid acting allowance as per the rules for the duties discharged by him as Munshi. But it is incorrect to say that there is no promotional policy for selection of munshi and that it was not proved or agreed by the Union. The framing of promotional policy is a managerial function and the workers have no right to interfere with regard to promotional policy. It is submitted that according to their promotional policy circulated by the General Manager by his letter dated 2-5-1976 to fill up the vacancies of Munshi, area seniority of Trammers was taken into account. So the Divisional Heads of Kothagudem, Yellandu and Manuguru were asked to submit the list of senior-most Trammers to be considered for the promotion of munshis. There are guidelines given in the Circular since 1976 for selection of Munshi. As the post is temporarily vacant Sri K. Suryanarayana was called upon to act as Munshi from 28-7-1981. After calling for the particulars from the seniormost Trammers out of the three Divisions for the post of Munshis, interviews were conducted since Sri K. Suryanarayana was promoted as Trammer on 15-12-1984 as there were number of other seniors who were eligible for promotion, he is not called for interview. No junior to K. Suryanarayana was called for interview. The job of munshi is mere of clerical in nature and it has to supervise to coordinate with the Trammers which are to enable the Trammers to discharge their duties. The definition of permanent employee under Standing Order 2(1) had nothing to do with the promotional policy. No workman has a right to demand for promotion on the basis of their acting experience which is temporary in nature. No principles of natural justice were involved and the Management is right in not confirming him as Munshi and the petition is liable to be dismissed.

5. The workman examined himself as W.W1 on 25-6-1985 and marked Ex. M1 as a document on behalf of the Management. The workman mentioned that he acted as Munshi in the office for some time and he was incharge of 50 workers as acting Munshi since 28-7-1981 though he worked as Trammer in the Singareni Collieries since 1952. He asserted that he was continuously working from 28-7-1981 till 10-5-1985 and he was having pay slip that he received

as acting allowance during that period. The witness infact produced pay slip and wanted to file them properly. He asserted that the post in which he was acting was a clear vacancy and he has to be absorbed in it permanently as per Standing Orders from 28-7-1981 onwards with attendant benefits. According to him he admitted in the cross examination done by the management counsel that Yellandu, Manuguru and Kothagudem will be considered as one area for the purpose of seniority of employees including Trammers and there are Trammers working in Yellandu, Manuguru and Kothagudem. He conceded that he is not the seniormost trammer in the area and Regional i.e. Yellandu, Manuguru and Kothagudem. But at the same time he did not know to give promotion from a Trammer to Munshi post the seniormost Trammer will be considered for the said post. He denied the suggestion that he is not entitled for the post of Munshi as he is not the seniormost Trammer among the area and that the promotional policy of the Management observe only seniority as criteria for such promotion. He admitted that under Ex. M1 the seniormost Trammer of the Area will be given opportunity to be posted as Munshi. But he explained that he did not know by the time whether by that time they called for seniority list of Trammers or not. But it is his case that one C. Narasiah, permanent munshi was medically declared unfit for promotion and the post became vacant and denied about the promotional policy. It is his case that he joined in the Company in the year 1952 and denied the suggestion that he was appointed as Trammer on 1954.

6. After the evidence is over on 25-6-1985 for workman, it is posted for Managements evidence on 31-7-1985 and it was being adjourned from time to time and they took time till 29-8-1985 and 30-9-1985 and they filed a Memo finally on 10-12-1985 stating that they are reporting settlement and that the talks are going on between the Union and the Management to arrive at a settlement. Again on 1-4-1986 there was such a Memo stating that negotiations to settle the matter out of Court was going on and sought for adjournment for two months. After 1-4-1986 the matter was adjourned to 30-5-1986, 1-8-1986, 25-8-1986, 10-9-1986 and 22-9-1986 but still no settlement is filed and the management also given one more chance to adduce evidence from 10-9-1986 to 22-9-1986 to produce their evidence for filing the said settlement in the matter. They did not file any settlement. In fact they filed a Memo on 10-9-1986 stating that they are not proceeding further in the matter as they are moving application for transfer of their cases as petition filed in I.D. No. 41 of 1985. But no such transfer order was received in this matter at any time stating this matter is stayed. There is no representation from authorised representative to that effect. The Tribunal had occasion to pass an order in M.P. No. 278/86 in I.D. No. 41 of 1985 on 4-9-1986 and the Memo was also rejected. Both the matters have no connection at all. They are not common issues also.

7. The interesting facts in this case are after having taken time to produce settlement from the time the workman's evidence was closed on 25-6-1985 for more than 1-1/2 years. The Management could not bring forth the so called negotiated settlement with the workers and they could not adduce evidence on their part to substantiate their promotional policy. Further they did not indicate that there were number of seniors and by virtue of the said promotional policy. Further they did not indicate that there were number of seniors and by virtue of the said promotional policy that so and so were posted in his place. It is not denied that K. Suryanarayana was working as Munshi in Grade III in the place of C. Narasiah from 28-7-1981 and he continued to work so till 10-5-1985. Now if there is a promotional policy for filling up the vacancies from Trammer to Munshi as per Ex. M1 there must be clear date to show that XY or Z who is working at Yellandu, Manuguru and Kothagudem who were seniors to K. Suryanarayana were called for interview in view of the so called promotional policy and they were given the said posting. Infact Ex. M1 would show that in Clause 4 as follows : "In the light of past experience it has now been decided to adopt the following procedure for promotion to Grade II and Grade III Munshies, and that the Tramming McCadams may be taken separately for each area of Kothagudem, Bellampalli

and Ramagudam Area I and II) as one Unit for promotion to Grade II Munshies and Grade III Munshies respectively in the respective areas". So far Grade III Munshies from Training Muccadams separately from each area treated each as one unit by itself to be construed for promotional policy is quite contrary to the promotional policy suggested to the witness. Moreover vaguely stating that there are some senior to him will not give a light to the Management to show that mere seniority is the criterion for promotional policy. At any rate the experience of this K. Suryanarayana as acting Munshi from 28-7-1981 to 10-3-1985 in a clear existing vacancy would show that he had gained experience in the higher post of Munshi and thus he had acquired better qualifications or supervisions and he was able to do the job satisfactorily to the satisfaction of his superiors and the Management could not file any complaints during the period of four years that the said K. Suryanarayana was not able to perform the duties of Munshi or that he acted contrarily to the Standing Orders or the job requirements of a Munshi. There is no such evidence forthcoming. So if the promotional policy is only based upon seniority they should not have allowed K. Suryanarayana to act in a clear vacancy without calling the seniormost people whose data is available with the Management and when it is their case that after one week after he was kept incharge they tried to call for the seniormost Trainer from the three areas. If it is really correct they could have displaced K. Suryanarayana by the seniormost Trainer either from Yellianou, Manuguru or Kothagudem and the Management did not require four years to implement their promotion policy based upon mere seniority. It is ridiculous to say that seniority is only the criterion in a given circumstances like this when K. Suryanarayana was already acting continuously for four years as a Munshi in a higher category drawing acting allowance when compared with others. Section 2(1) of the Standing Orders directly apply to such a case and when he is continuously working as a Munshi for four years to say that he is only a Trainer and because he is paid acting allowance without being confirmed he should face the interview and he cannot be called for interview on the ground that there were senior to him seems to be rather violation of Rule 2(1) of Standing Orders as no worker should be kept acting for a long time when there is a clear vacancy without filling it properly when the workers is discharging his duties continuously for four years, it is incorrect to say that he is only acting and that he cannot be construed as a permanent employee in that acting category or post. The Managements attitude in dragging on the proceedings for over 1 1/2 years without any evidence on the pretext of negotiations being conducted would show that the seniority for Grade III Munshis from Training Muccadams was being taken separately of each area of Kothagudem, Bellampally and Ramagudam and therefore they were in a very difficult fix to explain their own socalled promotional policy and the socalled alleged promotional policy was not implemented and it was not even brought to the notice of the workers and the Management cannot contend that it is managerial function when it affects the rights of the workers that they can frame their own promotional policies without consulting the workers who are affected parties. Moreover it need not be stressed as per the Industrial Dispute Act a workers case should be disposed of in a stipulated time of three months from the date of reference, if it is an individual case or within period of six months if it is a case involving more than one worker and looked from any angle this kind of delay without any explanation would only add misery to the worker who is involved in this reference while the Management is quite happy in dragging the proceedings for reasons best known to them. So taking all these matters into consideration and also evidence of W.W1 and also Ex. M1 and the attendant circumstances as discussed supra, I hold that the Management of Singarao Company Limited was not justified in not calling Kudipudi Suryanarayana who was acting Munshi with effect from 28-7-1981 for selection to the post of Munshi on regular basis and not confirming him as Munshi. On a clear understanding of the Standing Orders as well as the clear evidence placed before me I hold that he was continuously acting for more than four years from 28-7-1981 and that he is entitled for being selected for the post of Munshi on a regular basis and also for confirmation as Munshi as per the Standing Orders, and therefore the said

Sri Kudipudi Suryanarayana is entitled for confirmation from 28-7-1981 with attendant benefits as Munshi.

Award is passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the fourth day of October, 1986.

Sd/- Industrial Tribunal

Appendix of Evidence

Witness Examined
for the Workmen :
W.W1 K. Suryanarayana

Witnesses Examined
for the Management
NIL

Documents marked for the workmen

NIL

Documents marked for the Management:

Ex. M1 True copy of the letter dt. 2-8-76 addressed to all Additional General Managers and all Divisional Superintendents (Kothagudem) by the General Manager S. C. Company Limited, Kothagudem with regard to filling up of vacancies of training munshies.

J. VENUGOPALA RAO, Industrial Tribunal
[No. I-22012/109/83-D.III(B)]
V. K. SHARMA, Desk Officer

तहि दिनी, 31 अक्टूबर, 1986

का आ 3891:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) को धारा 17 के प्रत्युत्तर में, केन्द्रीय सरकार, स्टेवेडोर्स/क्लोरिंग एंड फारवाइंग एजेंट्स, कांट्रैक्टर्स के प्रबंधतत्त्व से याम्बद्ध नियाजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में मात्रवस्थों के पैकेट का प्रकाशित करतो है, जो केन्द्रीय सरकार का 27 अक्टूबर, 1986 का प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 31st October, 1986

S.O. 3891.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby publishes the award of Arbitrators as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employees in relation to the Stevedores/Clearing and Forwarding Agents/Contractors and their workmen, which was received by the Central Government on the 27th October, 1986.

IN THE MATTER OF ARBITRATION UNDER SECTION 10-A OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, RELATING TO QUANTUM OF HOUSE RENT ALLOWANCE TO UNLISTED WORKERS AND THREE OTHER ISSUES BETWEEN THE PARADEEP PORT STEVEDORES ASSOCIATION, PARADEEP PORT, ORISSA AND PARADEEP PORT & DOCK MAZDOOR UNION,

PARADEEP PORT, ORISSA

BEFORE SHRI P. D. SHENOY AND SHRI H. G. BHAV
JOINT ARBITRATORS

FOR THE EMPLOYERS :

1. M/s. The O.S.C.T.C. Ltd.
A. Suba Rao

2 M/s. J. M. Baxi & Co.
K. Rameah

3. M/s. L. M. Hati & Co.
S. C. Hati

4. M/s. S. C. Das & Co.
B. Das
5. M/s. E. C. Bose & Co.
K. J. Valson
6. M/s. T. P. Roy Choudhury & Co.
Balaram Khuntia
7. M/s. Orissa Stevedores (P) Ltd.
Mahimananda Mishra
8. M/s. Roy & Chatterjee (P) Ltd
A. Patnaik
9. M/s. Mahima Nanda Mishra
P. K. Hati
10. S. P. Nanda, Advocate
11. B. M. Patnaik, Advocate.

FOR THE WORKMEN :

1. G. S. Jena, President
2. A. C. Nag, Vice-President
3. Dulal Nath, Vice President
4. C. K. Mahapatra, Joint Secretary
5. Babaji Ch. Swain, Orgn. Secretary
6. A. K. Swain, Orgn. Secretary.

Representative of Paradeep Port & Dock Mazdoor Union
Paradeep Port, Orissa.

AWARD

Under an agreement between the management of Paradeep Port Stevedores Association, Paradeep Port on behalf of all Stevedores, clearing and forwarding Agents, contractors of Paradeep Port, Orissa and their workmen represented by the Paradeep Port and Dock Mazdoor Union, Paradeep Port signed on 29th January, 1985 in terms of Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947, the dispute between them regarding the Quantum of House Rent Allowance to unlisted workers, payment of wages to unlisted workers in terms of National Wage Settlement dated 4-1-1981 and 11-4-1984, method of working out daily wage to unlisted cargo handling workers and payment of attendance allowance to unlisted cargo handling workers, was referred for our joint arbitration. The Government of India, Ministry of Labour in accordance with the provision of sub-section (3) of Section 10-A of Industrial Disputes Act, 1947 ordered the publication of the said agreement vide order No. L-38012/2/85-D-IV(A), dated 18-3-1985.

2. The specific matters in dispute as referred for our arbitration were worded as follows :—

1. Quantum of House Rent Allowance to unlisted workers.
2. Payment of Wages to unlisted workers in terms of National Wage Settlement dated 4-1-1981 and 11-4-1984.
3. Method of working out daily wage to unlisted Cargo Handling Workers.
4. Payment of Attendance Allowance to unlisted Cargo Handling Workers."

3. The parties to the dispute were requested vide letter dated 27/29th March, 1985 to file their statement of the case in triplicate within 15 days from the date, endorsing a copy of the same to the opposite party simultaneously. The parties requested for extension of time for filing their written statement which was granted by us upto 25-4-1985 vide letter dated 19-4-1985.

4. On receipt of the complete papers from the parties concerned, the parties were called for a personal hearing on 21-8-1985 at Bhubaneshwar and were also requested to come with all evidence, oral or documentary substantiating their case. The parties were given personal hearing on 21-8-1985. Employers filed their rejoinder dated 20-8-1985 on 21-8-1985. A copy of the same was given to the representatives of Unions to file their rejoinder/reply to the employer's rejoinder. The Union requested for time which

was allowed. The parties were given personal hearings further on 2-12-1985 at Delhi; 7th and 8th January, 1986 at Bhubaneshwar; 17-4-1986 at Calcutta and finally on 30-7-1986 at Delhi. The parties had time to time mutually extended the time to give our Award and finally on 17-4-1986, the parties gave their consent extending the period for release of the Award upto 31-10-1986.

5. On 7th and 8th January, 1986, the parties had detailed arguments over the issues referred to us in this dispute and finally they desired to arrive at mutual understanding by resolving the issues in 3 or 4 sittings which was allowed with the direction to the parties to keep the arbitrators informed about the progress so achieved by them. When the case came up for final hearing on 30-7-1986, the parties in disputes, submitted their joint petition dated 23-7-86 stating that they have arrived at a compromise and have resolved all their dispute/differences including the specific matters pending before us in this dispute and requested us to accept this agreement and pass an order in terms of their agreement dated 23rd July, 1986. They filed copies of their mutual agreement dated 23rd July, 1986 which have been taken on record and annexed to this Award.

6. During the personal hearing held on various dates, the parties had submitted their pleadings and documents in support of their claims which do not now call for any examination or discussions. The mutual agreement dated 23-7-1986 filed before us has however, been examined by us and we find that the agreement is a package deal on various issues including inter alia the four demands referred to us. This agreement is fair and just. We are of the opinion that this agreement would be in the better interest of the workmen to set at rest their claims in question.

7. We therefore, give this award on the terms, which have been agreed upon between the parties in the agreement dated 23rd July, 1986 which now form part of this award.

8. We are highly thankful to the parties for the whole hearted co-operation extended to us by them during the arbitration proceedings.

(H. G. BHAVE)
Joint Chief Labour Commissioner (C) &
Arbitrator

(P. D. SHENOY)
Chief Labour Commissioner (C) &
Arbitrator

New Delhi:

Dated : 15th October, 1986.

BEFORE

Sri P. D. Shenoy,
Chief Labour Commissioner (Central),
New Delhi.
Sri H. G. Bhave,
Jt. CLC (Central),
New Delhi.Arbitrators

In the matters of :

Reference No. 8 of 1985
(Arbitration under Section 10A of the I.D. Act, 47)

AND

In the matter of Government of India Order No. D/19-3-85.

AND

In the matter of Arbitrator Agreement, dated 21-1-1985.

BETWEEN

C&F Agents/Stevedores/Contractors of Paradip Port
Represented by President, Stevedores Association—
Employer.

AND

The Workmen Represented by Paradip Port and Dock
Mazdoor Union (INTUC) Paradip Port and Work-
men.

In the matter of Joint Petition of Compromise.
The Petitioners, the Employers and the Union jointly beg to submit as under :

1. That the aforesaid case is pending before the Hon'ble Arbitrator for their decision.

2. That in the meantime, an amicable agreement has since been arrived at between the Union and the Employer on various issues including the specific issues pending before the Hon'ble Arbitrator in Reference No. 8 of 1985 as per the terms embodied in the enclosed agreement dated 23rd July, 1986.

PRAYER

The Petitioners, i.e. The Union and the Employers jointly therefore Pray that the Hon'ble Arbitrators may kindly accept the said agreement as reasonable and give an Award accordingly.

And for this Act of kindness, the Petitioners shall ever Pray.

SUBMITTED BY :

Employers :

1. M/s. The O.S.C.T.C. Ltd. A. Suba Rao.
2. M/s. J. M. Baxi & Co., K. Ramesh.
3. M/s. L. M. Hati & Co., S. C. Hati.
4. M/s. S.C. Das & Co., B. Das.
5. M/s. E. C. Bose & Co., K. J. Valson
6. M/s. T. P. Roy Choudhury & Co., Mr. Balaram Khuntia.
7. M/s. Orissa Stevedores (P) Ltd., Mr. Mahimananda Mishra.
8. M/s. Roy & Chatterjee (P) Ltd., Mr. A. Pattanaick.
9. M/s. Mahima Nanda Misra, Mr. P. K. Hati.

UNION

1. Mr. Dulal Nath	—Vice President.
2. Mr. A. C. Nag	—Vice President
3. Mr. Survamani Swain	—Secretary.
4. Mr. Babagicharan Swain	—Organising Secretary.
5. Mr. Brajabandhu Pulta Singh	—Organising Secy.

Settlement arrived at by agreement between the Stevedores/C&F Agents/Contractors of Paradip and Paradip Port & Dock Mazdoor Union (I.N.T.U.C.) Paradip Port.

NAME OF PARTIES

Representing Employers :

1. M/s. The O.S.C.T.C. Ltd.,
2. M/s. J. M. Baxi & Co.,
3. M/s. L. M. Hati & Co.,
4. M/s. S. C. Das & Co.,
5. M/s. E. C. Bose & Co., Pvt. Ltd.,
6. M/s. T. P. Roy Chowdhury & Co., Pvt. Ltd.,
7. M/s. Orissa Stevedores (P) Ltd.,
8. M/s. Roy & Chatterjee & Co., Pvt. Ltd.,
9. M/s. Mahimananda Mishra.

Representing Workmen :

1. President, Paradip Port & Dock Mazdoor Union.
- 2.

TITLE OF THE CASE

By Order dated 18-3-85, The Government of India in exercise of powers U/s 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 have referred the following disputes between Nine Stevedores/Contractors/C&F Agents and 1479 unlisted workers represented by the Paradip Port & Dock Mazdoor Union for Joint Arbitration by the Chief Labour Commissioner, (Central), New Delhi and the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) New Delhi.

1. Quantum of house rent allowance to unlisted workers.
2. Payment of wages to unlisted workers in terms of National wage settlement dated 4-1-81 and 11-4-84.
3. Method of working out daily wage to unlisted Cargo handling workers.
4. Payment of attendance allowance to unlisted Cargo handling workers.

The said reference registered as Arbitration Case No. 8 of 1985 is now pending adjudication.

In the meantime, several other demands including bonus, etc. for past years have been voiced by the Paradip Port & Dock Mazdoor Union, in short, the Union on behalf of the unlisted cargo handling workers.

The Stevedores/C&F Agents/Contractors as named above, herein after to be shortly referred to as the traders, have taken the stand inter alia in the above Arbitration case and also in their Defence against the subsequent demands as voiced by the above Union that there exists no master-servant relationship between the said Stevedores/C&F Agents/Contractors on the one hand whether jointly or severally and the unlisted cargo handling workers on the other, while the Union has the stand that they are the workers of the said nine employers.

In view of the peculiar system of working by the unlisted cargo handling workers and their development for the clearing and forwarding work undertaken by the traders and without prejudice to the respective stand of the parties as stated above, solely in the larger interest of the Port and its operations and with a view to resolve industrial unrest and frequent stalemates in work, the parties had several rounds of prolonged discussions in mutually to evolve some fairly acceptable solution to all the outstanding conflicts and differences between them and ultimately the following accord has been reached by and between them.

Terms of Settlement :

1. It is agreed that this settlement shall apply to the existing cargo handling workers (unlisted) of the pool in respect of 1479 workers to whom the Paradip Port Trust has issued gate passes as recommended by the pool. In case of such unlisted workers who have in the meantime died their legal heirs certified by the Tahasildar of the respective areas to which the deceased workers belong, shall be paid benefits as contained in clause No. 3 below.

2. Payment of all moneys under this agreement shall be made through the Paradip Port clearing forwarding and handling workers pool, briefly the pool.

3. It is agreed that all claims/demands/disputes including those pending in Arbitration, claim to bonus, etc. of the workers for the period immediately prior to the date of this agreement shall stand settled by payment of Rs. 2,500 (Two Thousand Five Hundred only) the traders concerned shall collect the above amount from the principals out of levy. The above payment of Rs. 2,500 shall be made in the following manner.

(i) Each unlisted worker excepting fifty five workers of Iron Ore and Chrome Ore Section shall be paid a lumpsum amount of Rs. 2,500 in five equal instalment of Rs. 500 each per quarter, with the first such quarterly payment to be alongwith the monthly wages (earnings) for July, 1986.

The above said fifty five workers of Iron Ore and Chrome Ore Section shall be paid Rs. 2,000 (Two Thousand Only) as they have already been paid bonus/ex-gratia for two years payable on the line indicated above.

(ii) It is understood and agreed that the above payment shall not attract any legal liability in respect of provident fund and gratuity.

(iii) The Pool will be requested by the parties jointly and severally to immediately intimate each of the traders and the Union the names of unlisted workers who have received such ex-gratia sum.

(iv) It is agreed that with effect from the date of this agreement, each unlisted worker drawn from the pool by any of the traders shall be paid the rates of wages as per Annexure-I to this agreement which has been formulated keeping in view the various wage settlements between the Government of India and the Federation of Unions of Port and Dock Labour and the present practice in the Paradip Port. It is understood and agreed by and between the parties that the term (wages) in the context of this agreement shall include basic Pay, DA, VDA, S.D.A, House Rent Allowance, Off-Day Wages, National and Festival Holidays wages, Attendance Allowance and Computation of Daily wages dividing basic monthly pay by 26 days and other components by 30 days.

Provided that, the amount of bonus/exgratia as agreed in Annexure-I will accumulate with the pool and will be released for payment to the concerned workers alongwith the earnings of the Month of September, 1986.

And thereafter the amount of bonus/exgratia shown in Annexure-I shall be paid alongwith their monthly wages.

Provided that, in respect of ancillary workers, (unlisted) drawn by the traders from the pool, the payment of wages shall be at the same rate as will be paid by the Port Trust authorities to their ancillary workers, and in case the ancillary workers of the Port Trust become entitled to any retrospective increase in wages as per the pending Arbitration Case No. 9/85 from a date prior to the date of this agreement, the traders shall pay in respect of the ancillary workers such increased rate only with effect from the date of this agreement.

(v) The above wage fixation shall remain in force until the next settlement between the Government of India and the Federations of the major Port and Dock workers.

(vi) It is agreed that the itemwise datum and the incentive scheme as indicated in Annexure-II shall be scrupulously followed by the workmen in case the output falls below the datum where the work is available, the concerned workmen shall be entitled to wages only at the prorata basis (Tonnage rate) as stipulated in Annexure-II.

(vii) It is understood and agreed that the pool shall not give booking to any worker for more than two duties in a day and that deployment of mazdoors and sardars shall not depend upon availability or non availability of Supervisors till the time the Union submits to the pool a list of educated workers for consideration of promotion as supervisors.

(viii) It is agreed that the parties will take up with the pool for increasing its efficiency for more effective control of Labour and for an equitable distribution/allocation of Labour to the traders as per requirement.

(ix) It is agreed that in case any worker misconducts himself while working for any trader, the concerned trader will be free not to accept his booking for a period of maximum 7 (seven) days with issuance of a letter to the pool informing the nature of misconduct of the worker immediately with a copy to the concerned Union and the other traders will also be free to refuse acceptance of his booking for any of them for the above period of seven days. An enquiry shall be made jointly by the representatives of the complaining, traders & representative of the concerned Union and representative of the pool in presence of the worker within the said seven days. In case of absence of either of the two parties other than the complaining trader the result of the enquiry by the two parties shall be final. If the concerned worker is found to be not guilty, the complaining trader shall be liable to deposit his wages with the pool of his bookings lost under the said trader.

Provided that the above arrangement shall cease to operate on the coming into force of a code of conduct for the workmen for which the parties hereby agree that they would

approach the pool within a period of two months with a commonly accepted draft code of conduct for adoption and execution by the pool.

(x) The parties understand and agree that in the event of future decasualisation of the unlisted Labour/Workmen, this agreement shall not stand as bar.

(xi) The parties understand and agree that during the currency of this agreement, there shall be no other or further demand involving financial commitments from the traders in respect of the matters covered by this agreement.

(xii) This agreement shall come into operation from the date of signing of this agreement i.e. 23rd July, 1986 and shall be operative until the next settlement between the Government of India and the Federation of Major Port & Dock Workers.

(xiii) Since the parties have resolved all their disputes/ differences including the specific matters pending before the learned Arbitrators in Arbitration Case No. 8 of 1985, the parties agree and undertake to approach the learned Arbitrators to accept this agreement and pass an Award in terms thereof.

In witness whereof the Parties through their Authorised representatives put their hand and seal to this agreement this day of 23rd July, 1986.

REPRESENTATIVES OF TRADERS :	UNION
	REPRESENTATIVES OF PARADIP PORT & DOCK MAZDOOR UNION

1. M/s The O.S.C.T.C. Ltd. (A. SUBA RAO)	Sd/- 1. A.C. NAG, Vice President.
2. M/s J.M. Baxi & Co. (K. RAMFESH)	Sd/- 2. Dular Nath, Vice-President. Sd/-
3. M/s L.M. Hati & Co. (S.C. HATI)	Sd/- 3. Surya Mani Swain Secretary.
4. M/s. S.C. Das & Co. (B. DAS)	Sd/- 4. Babaji Ch. Swain Organising Secretary.
5. M/s E.G. Bose & Co (K.J. VAISON)	Sd/- 5. Brajabandhu Palta Sing. Organising Secretary.
6. M/s T.P. Roy Choudhury & Co. (P) Ltd (B. KHUNTHA)	Sd/- 6. WITNESSES :

7. M/ Oriwa Stevedores (P) Ltd (Mahimananda Mishra)	(1) Signature. Name in Capital letter. Address : Basanta Kr. Bala P.O. Aripada v. Narmhri Pur. P.S. : Kendrapara.
8. M/s. Roy & Chatterjee (P) Ltd. (A. Patnaik)	(2) Signature Name in capital letters Address :

9. M/s. Mahimananda Mishra Bania Sahi (P.K. HATI)	Dt. Cuttack. Cuttack-753003 (Manu Mohan Noharana)
--	---

ANNEXURE—I

Category	Daily Wages including allowances as mentioned in agreement D/23-7-86 under Item No. 3 (IV)	Daily Rate of Bonus/Ex gratia	Daily Wages (Gross) Total
	1	2	3
Supervisor	Rs. 57.63 ps.	Rs. 4.80 Ps.	Rs. 62.43 Ps.
Sardar	Rs. 53.43 ps.	Rs. 3.99 Ps.	Rs. 57.42 Ps.
Mazdoor	Rs. 52.03 Ps.	Rs. 3.87 Ps.	Rs. 55.90 Ps.

N.B. The above wages have been calculated keeping in view of the scale of pay being paid to the above categories by the Paradip port trust as per the wage board recommendations D/11-4-84.

No further wages revisions will take place during the currency of Agreement D/23-7-86, vide Clause Nos. 3(xi) & (xii).

EMPLOYERS

UNION

1. M/s. The O.S.C.T.C. Ltd.	—A. Suba Rao	1. Dulal Nath, Vice President
2. M/s. J.M. Baxi & Co.	—K. Ramesh	2. A.C. Nag, Vice President
3. M/s. L.M. Hati & Co.	—S.C. Hati	3. Surmani Swain, Secretary
4. M/s. S.C. Das & Co.	—B. Das	4. Babaji Charan Swain, Organising Secretary
5. M/s. E.C. Bose & Co.	—K.J. Valson	5. Brajabandhu Paltasingh Organising. Secretary.
6. M/s. T.P. Roy Choudhury & Co. P. Ltd.	—B. Khuntia	
7. M/s. Orissa Stevedores (P) Ltd.—M.N. Mishra		
8. M/s. Roy & Chatterjee (P) Ltd.—A. Pattnaik		
9. M/s. Mahimananda Mishra—P.K. Hati		

ANNEXURE—II

Statements of Datum and Rates/Incentive Rates thereof Fixed PER M.T. for Different types of Cargos of at part of Paralip

S. No.	Cargo	Gang strength	Datum (per gang per shift)	Time/Rate per M.T.	Incentive			
					Up to 50% of above datum		over 50% of above Datum	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Bag Cargo	8—1	36.00 M.T.		Rs. 11.65	Rs. 12.50	Per M.T.	Rs. 13.00	Per M.T.
2. Drum	8+1	30.00 M.T.		Rs. 14.00	Rs. 15.00	-do-	Rs. 16.00	-do-
3. Bale	8+1	36.00 M.T.		Rs. 11.65	Rs. 12.50	-do-	Rs. 13.00	-do-
4. Cooking Coal/Hard Coke/Coastal coal	8+1 U/L (By Wagon)	30.00 M.T.		Rs. 14.00	Rs. 15.00	-do-	Rs. 16.00	-do-
5. Iron Ore	8+1 ..	36.00 M.T.		Rs. 11.65	Rs. 12.50	-do-	Rs. 13.00	-do-
6. Pig Iron	8+1 ..	32.00 M.T.		Rs. 13.10	Rs. 14.00	-do-	Rs. 15.00	-do-
7. Bulk (Iron Ore/Chrome Ore)	8+1	100.00 M.T. (U/L) Truck	Rs. 4.20	Rs. 4.50		-do-	Rs. 4.85	-do-
Ferro Manganese/Manganese Ore.	8+1	50.00 M.T. (L) Truck	Rs. 8.40	Rs. 9.00		-do-	Rs. 9.70	-do-
8. Charge Chrome	8+1	70.00 M.T. (U/L) Truck	Rs. 6.00	Rs. 6.40		-do-	Rs. 6.90	-do-
	8+1	50.00 M.T. (L) Truck	Rs. 8.40	Rs. 9.00		-do-	Rs. 9.70	-do-
9. Copper Concentrate	8+1	65.00 M.T. (U/L) Truck	Rs. 6.45	Rs. 6.90		-do-	Rs. 7.50	-do-
	8+1	50.00 M.T. (L) Truck	Rs. 8.40	Rs. 9.00		-do-	Rs. 9.70	-do-
10. Steel Billets & Wire Rod	8+1	118.00 M.T. L or U/L by Crane	Rs. 3.35	Rs. 3.80		-do-	Rs. 4.15	-do-
11. Steel Sheet Coil & Steel Slab up to 9 M.T. per pc	8+1	23 Pcs L or U/L By crane (207-MT)	Rs. 18.25 Per pc or Rs. 2.05 per MT.	19.50 Per pc 2.15 per MT.		Rs. 21.20 Rs. 2.35	Per pc or Per M.T.	

2	3	4	5
12. Steel Slab/Coil of 25 M.T.	8 + 1 16 Pcs L or U/L by Crane (400 M.T.)	Rs. 26.25 per pcs. Rs. 28.25 per pcs. or or Rs. 1.05 per MT. 1.15 Per MT.	Rs. 30.45 Per pcs or Rs. 1.20 Per MT.
(Weight Above 9 MT. upto 24 MT. Tonnage rate will apply)			
13. Steel-wire rod coils bounding (Minimum 4 Stings each boundle)	8 + 1 44 boundles	Rs. 9.55 per Bdl.	Rs. 10.55 Per Bdl.
14. Hard Coke	8 + 1 U/T 80 M.T. L/T 30 M.T.	Rs. 5.25 Per MT. Rs. 14.00 -do-	Rs. 5.75 Per MT. Rs. 15.00 Per MT.
Rs. 11.05 Per Bdl. Rs. 6.10 Per MT. Rs. 16.00 Per MT.			

Note—(1) The output of the shift shall be as per the Tally maintained by the Pool supervisor and certified by user supervisors.
 (2) In view of the present piece rate scheme there will not be any payment of any nature for increasing output arbitrarily when the actual output is less for the deliberate slowdown of work, the gang will be paid reduced wages pro-rata.
 (3) If it is so required by the user, the gang booked for a particular spot will be shifted to any other work spot within the port to enable the user to provide sufficient work to meet datum requirement.
 (4) In the case of any eventuality, the user would be within his right to change the type of work contemplated originally for the gang viz. L to U/L, Truck loading to wagon Loading vice-versa etc. which will be restricted to one changing.

EMPLOYERS

1. M/s. The O.S.C.T.C. Ltd.—A. Subu Rao
2. M/s. J.M. Boxi & Co. —K. Ramesh
3. M/s. L.M. Hati & Co. S.C. Hati
4. M/s. S.C. Das & Co.—B. Das
5. M/s. E.C. Bosc & Co—K.J. Valson
6. M/s. T.P. Roychoudhury & Co. (P) Ltd. B. Khuntia
7. M/s. Orissa Stevedores (P) Ltd. —M.N. Mishra
8. M/s. Roy & Chatterjee (P) Ltd.—A. Pattnajak
9. M/s. Mahimananda Mishra—P.K. Hati

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1986

का. आ. 3892—श्रीधोगिक विवाद शिवितियम्, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारत कोकिंग कोल लि. की परियम मुदीहाई कोलियरी के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट श्रीधोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार श्रीधोगिक अधिकरण, नं. 2, धनबाद के पांचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-10-1986 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 4th November, 1986

S.O. 3892.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of West Mudidih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd October, 1986.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 113 of 1985

In the matter of industrial disputes under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of West Mudidih Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen: Shri S. N. Bhattacharva Advocate and Shri S. N. Goswami, Advocate.

On behalf of the employers: Shri B. Joshi, Advocate

STATE: Bihar.

INDUSTRY: Coal.

UNION

1. Dulal Nath, Vice President
2. A.C. Nag, Vice President.
3. Suryamani Swain, Secretary
4. Babaji Charan Swain, Organising Secretary
5. Brajabandhu Palasingh, Organising Secretary

[No. L 380 13/2/85/D. IV(A)]
K. J. DYVAPARSAD, Desk Officer

Dated, Dhanbad, the 16th October, 1986

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012(80)/85-D. II(A), dated, the 30th July, 1985.

SCHEDEULE

“Whether the action of the management of West Mudidih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, P.O. Katrasgarh, Distt. Dhanbad in denying employment to the dependant of Smt. Anjwa Chamarain, ex-Wagon Loader as per the provisions of National Coal Wage Agreement is justified? If not, to what relief the dependant of the said workman is entitled?”

The case of the workmen is that Anjwa Chamarain was a permanent wagon loader in West Mudidih Colliery of M/s. B. C. C. Ltd. She was residing in a hut on the management's land and materials for construction of the said hut were supplied by the management as no quarter had been provided to her. The said hut caught fire due to which the hut was burnt and Anjwa Chamarain was also badly burnt in the said fire. The said burning injury caused to her permanent disablement. Anjwa Chamarain represented before the management for giving employment to her dependant son Nunu Ram who was her adopted son under the provision of NCWA-II. The management also declared Anjwa Chamarain as disabled workman on the basis of the report of the medical board dated 14-8-82. When her prayer was not allowed, she represented Bihar Janta Khan Mazdoor Sangh the union who raised an industrial dispute before the ALC(C), Dhanbad. After the failure of the conciliation before the ALC(C) the dispute was referred for adjudication to this Tribunal by the Government of India, Ministry of Labour. It is further submitted that Anjwa Chamarain was married

to Sukhdeo Das. Anjwa Chamarain was issueless and as such she and her husband Sukhdeo Das jointly adopted Shri Nunu Ram and the said adoption was given to them by the natural parents of Nunu Ram. Subsequently a deed of adoption dated 29-3-82 was executed by Anjwa Chamarain and Kaila Devi the natural mother of Nunu Ram. It is further submitted on behalf of the workmen that under para 10.4.3 of NCWA-II Anjwa Chamarain is entitled to the employment of her dependent Nunu Ram when she adopted as her son.

The case of the management is that Anjwa Chamarain, wife of Sukhdeo Das, joined as Casual wagon loader at West Mudidih Colliery on 11-6-75. She left her employment from 27-12-81. She submitted her resignation letter dated 23-9-82 and the same was accepted by the management on 8-10-82. According to the management, Anjwa Chamarain left her employment at her own accord on 27-12-81 and the subsequent submission of her resignation dated 23-9-82 was with some ulterior motive. She had submitted a photo copy purported to be a deed of adoption dated 29-3-82 indicating that she had adopted Nunu Ram aged 23 years and she had requested the management to give employment to Nunu Ram as her dependent. The concerned lady had left her employment on 27-12-81 and had prepared a deed of adoption on 29-3-82 at the instance of certain interested persons on payment of certain considerations for the purpose of giving employment to Nunu Ram. Her claim was mala fide and not a genuine claim for employment of Nunu Ram. The deed of adoption was invalid as Nunu Ram the person purported to have adopted was aged 23 years at the time of the execution of the adoption deed. She had no legal right to claim for employment of the adopted son after having resigned from service. The management had not provided any material for the construction of hut of Anjwa Chamarain. The management was not aware of the alleged accident due to which Anjwa Chamarain was burnt. The concerned lady had submitted her resignation voluntarily after leaving her employment. The case of termination of her services due to her permanent disablement was not true and it was concocted to secure employment to a stranger. On the above plea it is submitted on behalf of the management that Anjwa Chamarain is not entitled for the employment of Nunu Ram as her adopted son.

The only point for consideration in this case is whether Anjwa Chamarain is entitled to get employment of Nunu Ram as her dependent being her adopted son.

The management examined one witness and the workmen have examined three witnesses in support of their respective cases. The management has got 4 documents exhibited which are marked Ext. M-1 to M-4. The workmen's documents have been marked Ext. W-1 to W-3.

Admittedly Anjwa Chamarain was a permanent wagon loader in Mudidih Colliery of M/s. B.C.C. Ltd. It will appear from the evidence of MW-1 Shri Birendra Singh working as Senior Personnel Officer in West Mudidih Colliery that the medical board had reported Anjwa Chamarain unfit. In the cross-examination he has stated that the medical report by which the concerned lady was declared unfit by the management is in the office of the management and the same can be filed. It is thus clear from the evidence of the management's witness that the concerned lady Anjwa Chamarain had been declared medically unfit and that the management possesses the said medical certificate. WW-1 is Anjwa Chamarain herself. She has stated that in December, 1981 the electric line fell on her hut causing fire to her hut and also causing burning injuries to her. She has stated that she was taken to Lovabad hospital where she remained as an indoor patient for about a fortnight. She further stated that she was disabled due to the said injury. It is thus clear from the evidence of MW-1 and WW-1 that Anjwa Chamarain was declared unfit by the medical board.

Ext. M-3 dated 23-9-82 is a petition filed by Anjwa Chamarain to the Manager, West Mudidih Colliery in which it is stated that she has resigned from her service forgiving employment to her adopted son Nunu Ram. She stated in that petition that she had become medically unfit and was declared

unfit by the medical board and as such she demanded that her adopted son Nunu Ram may be given employment under the provision of NCWA-II. Ext. M-4 dated 8-10-82 is a letter by the Manager, West Mudidih Colliery in reply to Ext. M-3 by which the management refused to give employment to Nunu Ram as the dependent adopted son of Anjwa Chamarain. It is also stated in this reply that the medical board after her examination had found that she was not fit for work and as such her resignation was being accepted with effect from 11-10-82. Thus this letter Ext. M-4 also shows that Anjwa Chamarain had been declared unfit and disabled by the medical board of the management and as such her resignation was accepted by the management.

Ext. W-1 is the deed of adoption dated 29-3-82 executed by Anjwa Chamarain adoptive mother and Kaila Devi the natural mother of Nunu Ram. The adoption deed appears to be very badly drafted. It is stated in the deed that Anjwa Chamarain has no natural born son or daughter of her own and there is no chance of having any issue because of her health and age thus she is desirous to adopt a son who should perform necessary and usual ceremonies after her death to afford peace to her soul. It is further stated that Kaila Devi mother of the adopted son was willing to give her son Nunu Ram aged about 23 years to her for adoption on 7-3-78. It is further stated that she had already adopted Nunu Ram as her son with the consent of Kaila Devi and also with the consent of Nunu Ram. It will thus appear from the adoption deed Ext. W-1 that Nunu Ram was adopted when he was aged 23 years and that he natural mother Kaila Devi had given consent for the said adoption and that Nunu Ram had also given his consent for being adopted as the son of Anjwa Chamarain. Ext. W-2 is the affidavit of Sukhdeo Das and Anjwa Chamarain dated 26-6-84 and Ext. W-3 is the affidavit of Kaila Devi of the same date. It will appear from Ext. W-2 that both Sukhdeo Das and Anjwa Chamarain had adopted Nunu Ram and were the adoptive parents. It is further stated by them that they had verbally adopted Nunu Ram at the age when Nunu Ram was aged three years and thereafter they prepared an agreement of adoption on 7-2-78 and lastly prepared a registered deed of adoption on 29-3-82. Kaila Devi in her affidavit Ext. W-3 has stated that her son Nunu Ram was brought up by the adoptive mother Anjwa Chamarain and adoptive father Sukhdeo Das. She has stated that she gave Nunu Ram in Adoption to Anjwa Chamarain and Sukhdeo Das. It will thus appear from the affidavit that Nunu Ram was the adopted son of both Anjwa Chamarain and her husband but the deed of adoption shows that the adoption had been made by Anjwa Chamarain alone and as such she had executed a deed of adoption. No evidence of reliable independent person has been produced to show that Nunu Ram had been adopted at the age of 3 years. On the contrary the evidence of WW-1 and WW-2 is that the adoption took place about 15 years ago. It will appear that WW-3 Nunu Ram who is said to be adopted son of Anjwa Chamarain is aged 24 years. Thus the adoption according to the workman took place about 21 years ago. The evidence of WW-1 and WW-2 that the adoption took place about 15 years ago does not find support from the evidence discussed above. Under Section 16 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 it is provided that when ever any document registered under any law for the time being in force is produced before any court purporting to record an adoption made and is signed by the person giving and the person taking the child in adoption the court shall presume that the adoption has been made in compliance with the provision of this Act unless and until it is disproved. There is already a registered deed of adoption Ext. W-1 and there is presumption in favour of the adoption.

We have therefore to see whether the adoption supported by Ext. W-1 has been disproved by the management. WW-1 Anjwa Chamarain has stated in her evidence that Master Rattan and his wife gave their child Nunu Ram in adoption to Anjwa Chamarain and her husband. She has stated that subsequently her husband Sukhdeo married Shanti Chamarain and out of the said marriage Sukhdeo had two sons named Mahes and Brij and a daughter Usha. She has admitted that she had nominated Brij as son of Sukhdeo for the purpose of gratuity and Provident Fund. Ext. M-1 is the declaration by Anjwa Chamarain in respect of the C.M.P.F. which shows that she

had nominated Bijoy Das for the purpose of withdrawing the amount of her P.F. in case of her death. She has described Bijoy Das as her son aged 10 years. Thus it appears from Ext. M-1 that Anjwa Chamaraian had nominated Bijoy Das as her nominee for the purpose of P.F. In her cross-examination WW-1 has stated that in all the nominees filed by her regarding C.M.P.F. gratuity etc. she had given name of Bijoy Das as her son and that after the execution of the deed of adoption in favour of Nunu Ram he has given the name of had adopted Nunu Ram about 15 years ago and since then Nunu Ram as her adopted son for giving employment by the management. It is clear therefore that she had not declared Nunu Ram as her adopted son prior to her deed of adoption Ext. W-1. WW-2 is Sukdeo husband of Anjwa Chamaraian he has stated that he along with Anjwa Chamaraian Nunu Ram was residing with Anjwa Chamaraian. He has further stated that after the adoption he married Shanti Devi from whom he has two sons Bijoy and Mahesh and a daughter. In his cross-examination he has stated that Bijoy is aged about 7 to 8 years but Ext. M-1 shows that Bijoy Das was aged 10 years when Anjwa Chamaraian had nominated him for the purpose of C.M.P.F. There is no date when Ext. M-1 was filled up by Anjwa Chamaraian and as such it is not possible to say as to the year when Anjwa Chamaraian had described Bijoy Das aged 10 years but this much is certain that he has more than 10 years and WW-2 is not giving the correct age of Bijoy. Sukdeo Das husband of Anjwa Chamaraian has admittedly two sons out of whom one is Bijoy who had been nominated by Anjwa Chamaraian as her son in Ext. M-1. Had Anjwa Chamaraian adopted Nunu Ram about 15 years ago she would not have nominated Bijoy Das as her son for the purpose of P.F. This Ext. M-1 itself is a settler on the point that Nunu Ram had not been adopted by Anjwa Chamaraian prior to nomination of Bijoy Das as her son in Ext. M-1.

Taking the totality of the evidence of the parties it appears clear that Anjwa Chamaraian had not adopted Nunu Ram as her son 15 years ago and that the deed of adoption has been executed after she had left her service. It is clear that the said deed of adoption Ext. W-1 and the affidavits Ext. W-2 and W-3 have been created for the purpose of giving employment to Nunu Ram as adopted son of Anjwa Chamaraian when she had become unfit for work.

In the result, I hold that the action of the management of West Mudidih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P.O. Katrasgarh, Distt. Dhanbad in denying employment to the dependent of Smt. Anjwa Chamaraian, Ex-wagon loader as per the provisions of National Coal Wage Agreement is justified and consequently Nunu Ram, said to be the dependant of Smt. Anjwa Chamaraian ex-Wagon loader is entitled to no relief.

This is my Award.

Dated 16-10-86.

I. N. SINHA, Presiding Officer
[No. L-20012/80/85-D, II (A)]
A. V. S. SARMA, Desk Officer

नंदे दिल्ली, 4 नवम्बर, 1986

का.प्रा. 3693.—केन्द्रीय सरकार, प्रधक खान अम कल्याण निधि नियम, 1948 के नियम 4(1) के साथ परिवर्त प्रधक खान अम कल्याण निधि अधिनियम, 1946(1946 का 22) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त अधिसंघों का प्रयोग करने पर, इस अधिसंघों के प्रकाशन की तारीख से तीन बर्ष की अधिकि के सिये आधिक प्रवेश राज्य के सिये एक सलाहकार समिति गठित करती है जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे—

- अम मंत्री. प्रधक खान अम कल्याण
- प्रधक खान अम कल्याण आयुक्त, 1-7-145/12, श्रीनिवासमंड, कालोनी, मुशीराबाद, हैदराबाद-500048
- प्राधिक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), हैदराबाद।
- श्री आदितागयण रेड्डी, विधान सभा सदस्य, हैदराबाद।
- श्री जी. भावकर रेड्डी, मार्फत-माइका चैम्बर आफ कामसं, गुधुर, जिला—नेल्लोर।
- श्री एन. मुख्य रेड्डी, पार्टनर, एन. एम. रेड्डी, एड कजन, मध्यस्थ, माइका चैम्बर आफ कामसं, 2/191, नर्सिंग राय पेट, गुधुर, जिला—नेल्लोर।
- श्री के वेंकट सुब्रह्मण्य, जनरल सेक्रेटरी, माइका भजद्वार संघ कमरा नं 2071, गुधुर, जिला—नेल्लोर।
- श्री वी. राधाचार्य, वी-175, नवाबपेट, जिला—नेल्लोर।
- श्रीमती कलाहस्ती यशोदमा, कल्याण रमा माइका माहन की कम्बकार, गुधुर, नामुक, जिला—सेल्लोर।
- कल्याण प्रगासक, अधिक कल्याण संगठन, हैदराबाद।

केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि सदस्य

नियोजकों के प्रति निधि

कर्मचारियों के प्रतिनिधि

नहिला प्रतिनिधि

मर्चिव

प्रधक खान अम कल्याण निधि नियम, 1948 के नियम 19 के मनुसार, केन्द्रीय सरकार, आन्ध्र प्रदेश की प्रश्नक खान अम कल्याण निधि की राज्य सलाहकार समिति का मुख्यायत हैदराबाद नियत करती है।

[म. प. -19012/9/84-उच्च. -II (मी)]

New Delhi, the 4th November, 1986

S.O. 3893:—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946 (22 of 1946) read with rule 4(1) of the Mica Mines Labour Welfare Fund Rules, 1948, the Central Government thereby constitute an Advisory Committee for the State of Andhra Pradesh consisting of the following members for a period of three years from the date of publication of this notification, namely:—

- Labour Minister, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad. Chairman
- Mica Mines Labour Welfare Commissioner, 1-7-145/12, Sri Govindanagar Colony, Musheerabad, Hyderabad-500048. Vice-Chairman
- Regional Labour Commissioner, (Central), Hyderabad. Member representing Central Govt.
- Shri Adinarayana Reddy, Member, Legislative Assembly, Hyderabad. Member
- Shri D.B. Bhaskara Reddy, C/o Mica Chamber of Commerce, Gudur, District Nellore. Employers' representatives.
- Shri N. Subba Reddy, Partner, N.S. Reddy & Cousin, Member, Mica Chamber of Commerce 2/191, Narsingraopet, Gudur, Distt, Nellore.

7. Shri K. Venkata Subbaiah, General Secretary, Mica Mazdoor Sangh, R. No. 2071, Gudur, District Nellore.	Employee, representative
8. Shri B. Radhaiah, B-175, Nawabpet, District Nellore	
9. Shrimati Kalahasti Yasodamma, Woman Worker of Kalyanarama Mica Mine, Rapur Taluk, District Nellore.	representative.
10. Welfare Administrator, Labour Welfare Organisation, Hyderabad.	Secretary.

2. In accordance with rule 19 of the Mica Mines Labour Welfare Fund Rules, 1948, the Central Government hereby fixes Hyderabad as the headquarters of the State Advisory Committee for Mica Mines Labour Welfare Fund for Andhra Pradesh.

[No. U. 19012/9/84-W. II(C)]

नई दिल्ली, १५ नवम्बर, १९८६

का.आ. 3894:—विनेमा, कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 (1981 का 33) जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित कल्याण आयुक्तों को तत्काल प्रभाव से नियुक्त करती है जिस का उक्त अधिनियम और मिन्मा कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1981 (1981 का 30) के प्रारंभनी के लिए, उसके द्वारा यथा उल्लिखित वार्षिकाधिकार और मुख्यालय होते। ये कल्याण आयुक्त उसके प्रधान और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रधान अपने मंत्रियों के द्वारा नियुक्त होते हैं और वित्तीय शास्त्रियों का प्रयोग करने के लिए विभागाध्यक्ष के रूप में भी काम करेंगे—

- कल्याण आयुक्त, दिल्ली उत्तर प्रदेश, अमृ और कर्मसीर, हिनाचल प्रदेश राज्यों, दिल्ली तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- कल्याण आयुक्त, भोजप्रदेश, गुजरात और हरियाणा
- कल्याण आयुक्त, बिहार
- कल्याण आयुक्त, दूर्गावाहन
- कल्याण आयुक्त, जबलपुर

[म. एम-22025/3/86-कल्याण-4]

New Delhi, the 6th November, 1986

S.O. 3894:—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Cine-Workers Welfare Fund Act, 1981 (33 of 1981) (hereafter mentioned as the said Act), the Central Government hereby appoint the following Welfare Commissioners with jurisdiction and Headquarters indicated against each for the purpose of the said Act and the Cine-Workers Welfare Cess Act, 1981 (30 of 1981), with immediate effect. These Welfare Commissioners will also act as Head of the Departments to exercise administrative and financial powers for the implementation of welfare schemes under the said Act and rules made thereunder in respect of their respective jurisdiction.

schemes under the said Act and rules made thereunder in respect of their respective jurisdiction—

- Welfare Commissioner, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Union Territories of Delhi and Chandigarh.
- Welfare Commissioner, Rajasthan, Gujarat and Haryana.
- Welfare Commissioner, Bihar.
- Welfare Commissioner, Orissa.
- Welfare Commissioner, Madhya Pradesh.

[S.22025/3/86-W-IV.]

का.आ. 3895.—केन्द्रीय सरकार, सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 (1981 का 33) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सूचना और प्रसारण मंत्रालय की दिनांक 18 नवंबर, 1985 की प्रधानमंत्री संलग्ना 106/5/85-एफ(1) के अधिक्रमण में कल्याण आयुक्त, नागपुर को तत्काल नियुक्त करती है जिसका उक्त अधिनियम और सिनेमा कर्मकार उपकर अधिनियम, 1981 (1981 का 30) के प्रयोगनी के लिए महाराष्ट्र राज्य तथा गोवा, दमण और बीच संघ राज्य क्षेत्र में कार्यक्रमाधिकार होगा। कल्याण आयुक्त, नागपुर उक्त अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन अपने क्षेत्राधिकार में कल्याण योजनाओं के कार्यालयन हेतु प्रशासनिक और वित्तीय शास्त्रियों का प्रयोग करने के लिए विभागाध्यक्ष के रूप में भी काम करेगा।

[म. एम-22025/3/86-इन्डिय-4]

S.O. 3895.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Cine-Workers Welfare Fund Act, 1981 (33 of 1981) (hereafter mentioned as the said Act), and in supersession of Ministry of Information and Broadcasting Notification No. 106/5/85-F(I) dated the 18th November, 1985, the Central Government hereby appoints Welfare Commissioner, Nagpur with the jurisdiction of the State of Maharashtra and Union Territory of Goa, Daman and Diu for the purpose of the said Act and the Cine-Workers Welfare Cess Act, 1981 (30 of 1981), with immediate effect. The Welfare Commissioner, Nagpur will also act as Head of the Department to exercise administrative and financial powers for the implementation of welfare schemes under the said Act and rules made thereunder in respect of his jurisdiction.

[S. 22025/3/86-WIV]

का.आ. 3896.—केन्द्रीय सरकार, सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 (1981 का 33) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 26 अक्टूबर, 1985 को भारत के गजपत के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित सूचना और प्रसारण की प्रधानमंत्री संलग्ना 4963 और का.आ. 4959 के अधिक्रमण में कल्याण आयुक्त, हैदराबाद को तत्काल नियुक्त करती है जिसका उक्त अधिनियम और सिनेमा कर्मकार उपकर अधिनियम, 1981 (1981 का 30) के प्रयोगनी के लिए आप्र प्रदेश, नमिलनाडु राज्यों और पांडिचेरी संघ राज्य थोल में कार्यक्रमाधिकार होगा। कल्याण आयुक्त, हैदराबाद उक्त अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों अधीन अपने क्षेत्राधिकार में कल्याण योजनाओं के कार्यालयन हेतु प्रशासनिक और वित्तीय शास्त्रियों का प्रयोग करने के लिए विभागाध्यक्ष के रूप में भी काम करेगा।

[म. एम-22025/3/86-इन्डिय-4]

S.O. 3896.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Cine-Workers Welfare Fund Act, 1981 (33 of 1981) (hereafter mentioned as the said Act), and in supersession of Ministry of Information and Broadcasting Notification Nos. S.O. 4963 and S.O. 4959, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 26th October, 1985, the Central Government hereby appoints Welfare Commissioner, Hyderabad with the jurisdiction of the States of Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Union Territory of Pondicherry for the purpose of the said Act and the Cine-Workers Welfare Cess Act, 1981 (30 of 1981), with immediate effect. The Welfare Commissioner, Hyderabad will also act as Head of the Department to exercise administrative and financial powers for the implementation of welfare schemes under the said Act and rules made thereunder in respect of his respective jurisdiction.

[S-22025/3/86-W.IV]

का० आ० 3897 —केन्द्रीय सरकार, मिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम 1981 (1981 का 33) (जिसे उसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करने हुए, और दिनांक 26 अक्टूबर, 1985 को भारत के गवर्नर के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ० 4961 के अधिकारण में, कल्याण ग्राम्यक, कलकाला को तत्काल नियुक्त करती है जिसका उक्त अधिनियम और मिनेमा कर्मकार उपकर अधिनियम, 1981 (1981 का 30) के प्रयोजनों के लिए केरल और कर्नाटक राज्यों में कार्य अंतिकार होगा। कल्याण ग्राम्यक, वंगालौर उक्त अधिनियम और मिनेमा कर्मकार उपकर अधिनियम, 1981 (1981 का 30) के प्रयोजनों के लिए केरल और कर्नाटक राज्यों में कार्य अंतिकार होगा। कल्याण ग्राम्यक, वंगालौर उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन इसपर अंतिकार में कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विभागाध्यक्ष के रूप में काम करेंगा।

[म. एम-22025/3/86-इम्सू-4]

S.O. 3897.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Cine-Workers Welfare Fund Act, 1981 (33 of 1981) (hereafter mentioned as the said Act), and in supersession of Ministry of Information and Broadcasting Notification Nos. S.O. 4960 and S.O. 4962, published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 26th October, 1985, the Central Government hereby appoints Welfare Commissioner, Bangalore with the jurisdiction of the States of Kerala and Karnataka for the purpose of the said Act and the Cine-

Workers Welfare Cess Act, 1981 (30 of 1981), with immediate effect. The Welfare Commissioner, Bangalore will also act as Head of the Department to exercise administrative and financial powers for the implementation of welfare schemes under the said Act and rules made thereunder in respect of his respective jurisdiction.

[S-22025/3/86-W.IV]

का आ० 3898 —केन्द्रीय सरकार, मिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 (1981 का 33) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करने हुए और दिनांक 26 अक्टूबर, 1985 को भारत के राज-प्रम. भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ० 4961 के अधिकारण में, कल्याण ग्राम्यक, कलकाला को तत्काल नियुक्त करती है जिसका उक्त अधिनियम और मिनेमा कर्मकार उपकर अधिनियम, 1981 (1981 का 30) के प्रयोजनों के लिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैण्ड और मणिपुर राज्यों में कार्यपीठाधिकार होगा। कल्याण ग्राम्यक, कलकाला उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन इसपर केंद्रीय अधिकार में कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विभागाध्यक्ष के रूप में भी काम करेंगा।

[म० एम-22025/3/86-इम्सू-4]

एम. एम. भल्ला, अवर सचिव

S.O. 3898.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Cine-Workers Welfare Fund Act, 1981 (33 of 1981) (hereafter mentioned as the said Act), and in supersession of Ministry of Information and Broadcasting Notification No. S.O. 4961, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 26th October, 1985, the Central Government hereby appoints Welfare Commissioner, Calcutta with the jurisdiction of the States of West Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura, Nagaland and Manipur for the purpose of the said Act and the Cine-Workers Welfare Cess Act, 1981 (30 of 1981), with immediate effect. The Welfare Commissioner, Calcutta will also act as Head of the Department to exercise administrative and financial powers for the implementation of welfare schemes under the said Act and rules made thereunder in respect of his respective jurisdiction.

[S-22025/3/86-W.IV]

S. S. BHALLA, Under Secy.

